R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth
पाक्षिक
अक्स
वर्ष : 20 । अंक : 02
16 से 31 अक्टूबर 2021
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

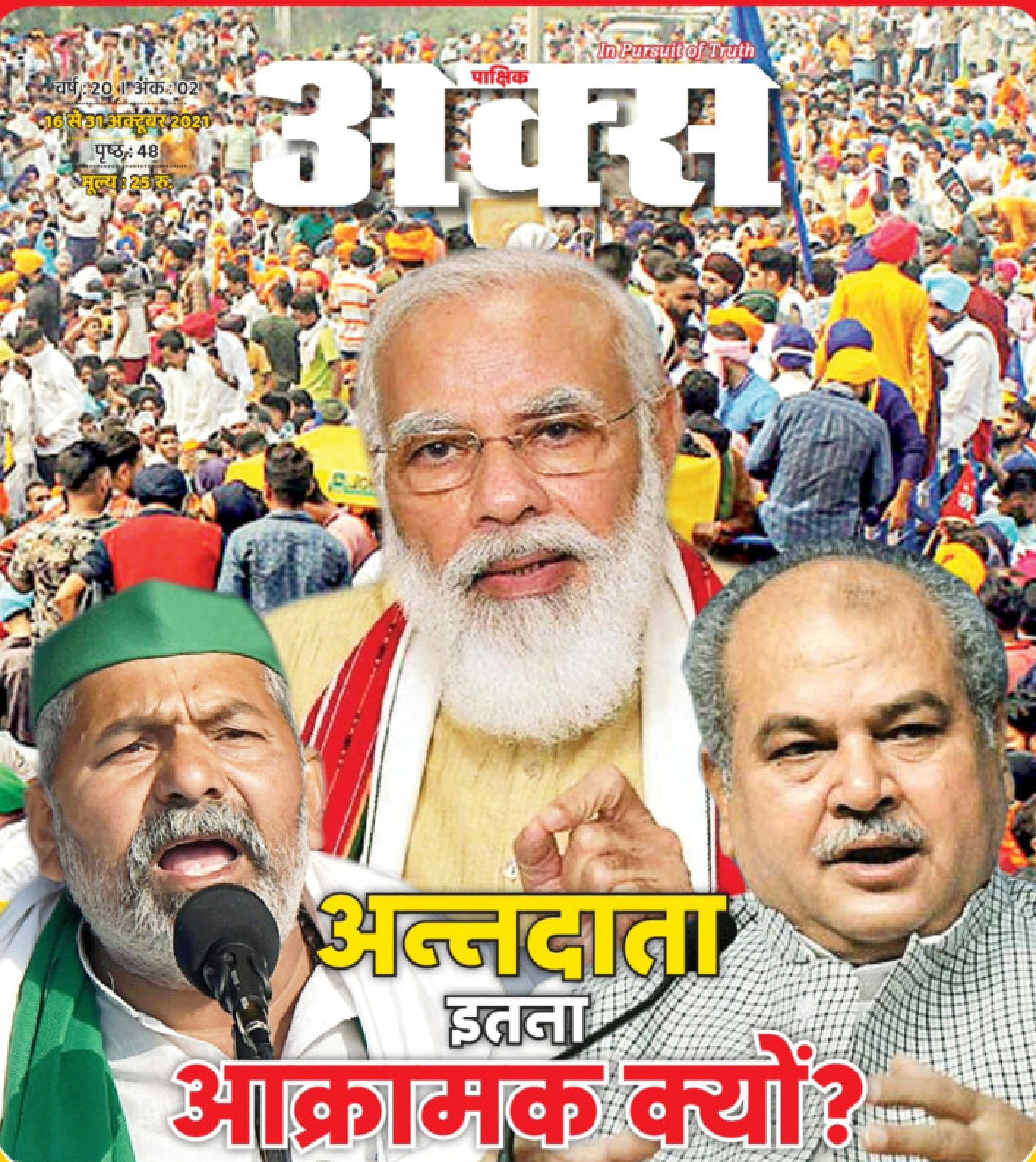

अन्नदाता इतना आक्रामक क्यों?

लखीमपुर खीरी और सिंघु बॉर्डर के हत्याकांड कर रहे

अन्नदाता की छवि खराब...

बातचीत की पटरी से पूरी तरह उतरा आंदोलन...

कृषि में कीर्तिमान गढ़ता मध्य प्रदेश

कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था से गौरवान्वित मध्यप्रदेश कृषकों के सक्षम और सम्पन्न बनाने के लिए कृत-संकल्पित है। राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लगातार कृषि कल्याणकारी योजनाओं और नवाचारों को बढ़ावा दिया है और किसान हित में ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं।

आत्म-निर्भर म.प्र. के निर्माण में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना हमारी प्राथमिकताओं में है।

अब डिजिटल कृषि भी

खेती में उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए मध्यप्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर अंतर्गत लगातार काम किया जा रहा है।

सिंचाई क्षमता में वृद्धि को प्राथमिकता

किसानों की आय को बढ़ाने के लिये बेहतर प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं पर भी प्राथमिकता से कार्य करवाये जा रहे है। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

नेशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रा फायनेंसिंग फेसिलिटी पोर्टल

नेशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रा फायनेंसिंग फेसिलिटी (एआईएफ़) पोर्टल पर बहुत ही कम समय में 2,352 आवेदन आये हैं। इनका लगातार सत्यापन किया जा रहा है और 618 करोड़ का भुगतान भी बैंकों द्वारा कर दिया गया है।

D19239/21

इस अंक में

उपलब्धि

9 | **यूपीएससी में मप्र का दबदबा**

मप्र निरंतर प्रगति की उड़ान भर रहा है। मप्र की इस प्रगति में चार चांद लगाए हैं यूपीएससी में चयनित 38 अभ्यार्थियों ने। गौरतलब है कि यूपीएससी में अभी तक बिहार, उप्र और दक्षिण भारतीय राज्यों का दबदबा रहता था।

राजपथ

10-11 | **दांव पर लोकप्रियता**

वर्ष 2018 में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस ने अपनों की बगावत के कारण 2020 में सत्ता गंवा दी। ऐसे में वह 2023 में हर हाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। वहीं भाजपा लगातार पांचवी बार शिवराज सिंह चौहान को...

मप्र कांग्रेस

14 | **फिर धड़ों में बंटी मप्र कांग्रेस**

मप्र कांग्रेस में गुटबाजी फिर सतह पर है। वजह टिकट की खींचतान, वर्चस्व का खेल और अनसुनी। चर्चा में है खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव में टिकट के लिए अरुण यादव का दावेदारी से खुद को पीछे हटाना। यादव जो मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे...

विकास

23 | **नर्मदा कोरीडोर को हरी झंडी**

नर्मदा सौंदर्य को निखारने और लोगों की आस्था को मजबूत करने वाला नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर का काम जल्द शुरू होगा। नर्मदा नदी के तिलवारा घाट से भिटौली तक लगभग 8.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को बनाने के लिए भोपाल से स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद जबलपुर विकास प्राधिकरण...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

लखीमपुर खीरी और सिंघु बॉर्डर के हत्याकांड कर रहे अन्नदाता की छवि खराब...

बातचीत की पटरी से पूरी तरह उतरा आंदोलन...

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून के विरोध में नवंबर 2020 से किसान आंदोलन चल रहा है। बातचीत की पटरी से उतर चुका आंदोलन अब तक कई मोड़ देख चुका है। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उप्र में आंदोलन का ज्यादा प्रभाव है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने रणनीति बदली है। सिंघु व टीकरी बार्डर पर धरनों के साथ बड़ी-बड़ी महापंचायत की जा रही हैं। यही नहीं अन्नदाता अब आक्रामक होता जा रहा है।

29

35

38

45

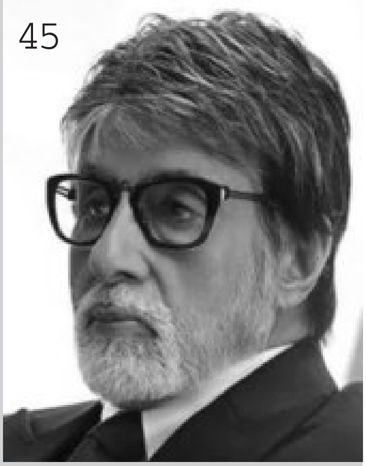

राजनीति

30-31 | **सबके निशाने पर कांग्रेस**

2014 में भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। लेकिन देखा यह जा रहा है कि सभी पार्टियां कांग्रेस को खंड-खंड करने में जुटी हुई हैं। यानी सभी पार्टियों ने कांग्रेसी नेताओं के लिए अपने द्वार खोल रखे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कांग्रेस खोखली होती जा रही है।

महाराष्ट्र

36 | **455 फीसदी बढ़ा ड्रग्स...**

देश में महाराष्ट्र ड्रग्स का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। बॉलीवुड में ड्रग्स की लत ने इसे और बढ़ा दिया है। एक अनुमान के तहत बॉलीवुड का हर चौथा व्यक्ति ड्रग्स का आदी है। अभी हाल ही में एनसीबी ने मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में एक क्रूज पोत से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए जाने के सिलसिले...

बिहार

37 | **लालू के घर में सत्ता संघर्ष**

लालू यादव के घर में झगड़ा अब सारी हदें पार कर चुका है, ये तो ऐसा लगता है कि झगड़े में तेज प्रताप यादव पूरी तरह अकेले भी पड़ चुके हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को निशाना बनाने के चक्कर में बड़ी बहन मीसा भारती का भी ख्याल नहीं रखा है।

6-7 अंदर की बात

40 पड़ोस

41 विदेश

43 कहानी

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य

अपनी बात

आंकड़ों में भरपूर खाद... किसान खाली हाथ

विनोद बक्सरी का एक शेर है...

देवताओं से भी हल नहीं हुई, जिंदगी कहीं सरल नहीं हुई।
कि अबके साल फिर यही हुआ, फिर से फसल नहीं हुई।।

ये पक्तियां अन्नदाता की व्यथा को दर्शाती हैं। लेकिन इसका समाधान होने की बजाय, व्यथा दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। देश-प्रदेश में रबी सीजन में हर साल खाद का संकट होता है। जबकि रबी फसलों की बुवाई का रकबा लगभग तय रहता है। इसके बावजूद भी सरकार समय पर खाद की व्यवस्था नहीं कर पाती है। इस बार भी प्रदेश में कई जगहों से खाद की किल्लत के बाद किसानों की गुस्से और आंदोलन की तस्वीरों ने प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ा दिया। विपक्ष ने किसानों के हालात के लिए पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार बताते हुए सरकार के संरक्षण में कालाबाजारी होने का आरोप लगाया है। हालांकि सत्तापक्ष का दावा है कि सरकार खाद की कृत्रिम कमी पैदा करने वाले लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई करेगी क्योंकि प्रदेश के पास पर्याप्त खाद है। बड़ा सवाल ये कि अगर प्रदेश में खाद का पर्याप्त स्टॉक है तो फिर ये कमी क्यों हैं? ये कतारें और ये संकट किस वजह से है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मप्र के कई क्षेत्रों में खाद की कमी का भारी संकट खड़ा हो गया है। रबी फसलों की बुवाई का समय आ गया है और किसानों के पास खाद नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बुवाई से पहले खाद अचानक मार्केट से गायब हो गई हो। खाद की कालाबाजारी की शिकायत कोई नई बात नहीं है, प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि खाद का संकट सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। खाद की कालाबाजारी की शिकायतों के बाद अब सरकार ने ऐसे लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार बार-बार किसानों से अपील कर रही है कि खाद को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है प्रदेश के पास पर्याप्त खाद है। प्रदेश में कई जिलों में खाद की किल्लत है, सबसे ज्यादा ग्वालियर-चंबल अंचल में खाद की लगातार कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही हैं। भिंड के गोरमी में पुलिस ने व्यापारी संजय जैन के खाद के गोदाम पर छापा मारकर डीएपी की 130 बोरियां जब्त की हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि व्यापारी 1200 रुपए की जगह 1500 रुपए बोरी की दर से खाद बेच रहा था। वहीं मुरैना में खाद खरीदने आए किसानों पर पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। खाद लेने आए किसानों को जब खाद खत्म होने का पता चला तो उन्होंने हंगामा शुरु कर दिया। जिसके बाद किसानों की जमकर नोंक-झोंक हुई। खाद को लेकर किसानों के विरोध और आक्रोश का सामना सरकार के मंत्रियों को भी करना पड़ रहा है। भिंड जिले में खाद की कमी पर किसान जब राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया से अपनी गुहार लगाने पहुंचे तो मंत्री जी भड़क गए। किसानों को डीएपी और यूरिया नसीब नहीं हो रहा। आरोप कालाबाजारी के भी लग रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं विपक्ष खाद की कमी के लिए सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहा है। कुल मिलाकर खाद न मिल पाने के कारण किसान परेशान हैं। उनकी पूरी फसल दांव पर लगी है। अगर समय रहते उन्हें खाद नहीं मिला तो उनका परिवार भूखों मर जाएगा। किसानों की इस मजबूरी का फायदा अब मुनाफाखोर भी उठा रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात से है कि खुद को किसानों की हितैषी बताने वाली सरकारें आखिर इस बुनियादी समस्या का हल क्यों नहीं खोज पाती है?

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 2, पृष्ठ-48, 16 से 31 अक्टूबर, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ** :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

छात्रों की चिंता

कोरोना महामारी ने बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर डाला है। 500 से ज्यादा दिन से बंद रहे स्कूलों के चलते ग्रामीण बच्चे शिक्षा से दूर हो गए हैं। वहीं शहर के स्कूलों में भी कोई खास पढ़ाई का जोश देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि पालक अपने बच्चों को कोरोना में स्कूल नहीं जाने देना चाहते।

● **प्रियंका सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

हक का पानी

मप्र में नर्मदा नदी पर प्रस्तावित परियोजनाएं या तो आधी-अधूरी हैं या शुरू ही नहीं हो पाई हैं। जिन परियोजनाओं का काम चल रहा है उनकी गति काफी धीमी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। ताकि मप्र में पानी की किल्लत न हो। और प्रदेश अपने हक का पानी उपयोग कर सके।

● **परशुराम शर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

माफिया पर शिकंजा

मप्र की शिवराज सरकार माफियाओं को सबक सिखाने के लिए उन पर कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में अतिक्रमण कर रह रहे माफिया के घरों-दुकानों को हटाया जा रहा है। सरकार के इस कदम से जहां एक ओर माफिया में खौफ पैदा हो गया है, वहीं जनता का सरकार पर भरोसा मजबूत हो रहा है।

● **शशिधर पांडे,** शिवपुरी (म.प्र.)

उपचुनाव तय करेंगे अगली सत्ता किसकी?

प्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव तय करेंगे कि यहां भाजपा और मजबूत होगी या फिर कांग्रेस को 2023 में सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। क्योंकि इन्हीं उपचुनावों से दोनों पार्टियों की मजबूती का पता चल सकेगा। कांग्रेस के सामने फिर उपचुनाव चुनौती के तौर पर खड़े हुए हैं। पिछले साल सत्ता गंवाने के बाद 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई थी। दमोह विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों से भाजपा पर जो दबाव बना, उसने कांग्रेस को अतिविश्वास से भर दिया। वहीं भाजपा ने दमोह उपचुनाव में मिली हार को गंभीरता से लेते हुए इन चुनावों का प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है।

● **आदर्श मिश्रा,** सीहोर (म.प्र.)

चरमराई अर्थव्यवस्था

कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में सरकार की परेशानी बढ़ गई है कि वे जनता को क्या जवाब देंगे। सरकार ने अपने सभी विधायकों को विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय होने का निर्देश दे दिया है। लेकिन विधायक पसोपेश में पड़े हुए हैं, क्योंकि विकास कार्य रुके हुए हैं। दरअसल मप्र का राजकोष खाली है। कमाई से ज्यादा खर्च है, राज्य का इस साल का जितना बजट है, उससे ज्यादा कर्ज है और कर्ज पर ब्याज का बोझ भी है।

● **अशरफ अली,** ग्वालियर (म.प्र.)

अनाज सुधारेगा मप्र की आर्थिक स्थिति

प्रदेश में हर साल अनाज का रिकार्ड उत्पादन और सरकारी खरीदी हो रही है। इस कारण प्रदेश के गोदाम और कैप भरे पड़े हैं। ऐसे में सरकार अनाजों को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती है। वर्तमान में सरकार को हर माह लगभग 2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा रहा है। इसलिए सरकार अनाज बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। पिछली बार प्रदेश सरकार छह लाख 45 हजार टन गेहूं की नीलामी करने के बाद अब धान की भी नीलामी करेगी।

● **प्रमोद वर्मा,** राजगढ़ (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स, एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

फिर पाला बदलने की सुगबुगाहट

राजनीति में कब क्या हो जाए, यह कोई नहीं बता सकता। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार कब तक चलेगी कह पाना दिनों-दिन खासा मुश्किल होता जा रहा है। गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना लगातार ऐसे संकेत दे रही है जिससे इस गठबंधन के ज्यादा समय तक नहीं चलने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। इसके बाद से मुंबई में सत्ता के गलियारों में एक बार फिर से शिवसेना और भाजपा के एक होने की खबर जोर पकड़ने लगी हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के जबर्दस्त दबाव के चलते शिवसेना का एक बड़ा वर्ग भाजपा संग दोबारा गठबंधन के लिए ठाकरे पर दबाव बना रहा है। शिवसेना नेता अनिल परब पर इन एजेंसियों का शिकंजा कसने और पूर्व एंकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा (अब शिवसेना नेता) की एनआईए द्वारा गिरफ्तारी के चलते शिवसैनिकों में भारी भय का माहौल है। खबर जोरों पर है कि भाजपा आलाकमान और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एक-दूसरे के निरंतर संपर्क में बने हुए हैं। सूत्रों की मानें तो अगले वर्ष होने जा रहे मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले ही दोनों पुराने साथी एक हो महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है।

कांग्रेस का दांव, भाजपा परेशान

पंजाब में कांग्रेस आलाकमान ने बगैर किसी बगावत को झेले सत्ता परिवर्तन तो किया ही, एक दलित को मुख्यमंत्री बना मास्टर दांव चल भाजपा नेतृत्व को खासी उलझन में डालने का काम भी कर दिया है। खबर गर्म है कि चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से भाजपा के कई मुख्यमंत्री खासे बेचैन और भयभीत हो चले हैं। सत्ता के गलियारों में नाना प्रकार की संभावनाओं पर चर्चा का दौर शुरू हो चला है। कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व जल्द ही अपने शासित प्रदेशों में कुछ ऐसा ही कर कांग्रेस के दांव की धार कुंद करने जा रहा है। अगले बरस होने जा रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में दलित वोटर खासे महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस तो चन्नी का उप्र और उत्तराखंड में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम कराकर दलित वोटरों को लुभाने की तैयारियों में जुट गई है। इन पांच राज्यों में से चार में भाजपा सत्तारूढ़ है। उसका संकट यह कि कांग्रेस के दलित कार्ड की काट करें तो कैसे। उप्र में मुख्यमंत्री बदलना तो पार्टी के आलाकमान तक की ताकत में है नहीं। गुजरात और उत्तराखंड में अभी-अभी मुख्यमंत्री बदले गए हैं। बचे गोवा और मणिपुर तो वहां भी ऐसा होना राजनीतिक कारणों चलते संभव नहीं। कहा जा रहा है कि भाजपा आलाकमान इन राज्यों में चुनावों से ठीक पहले किसी अन्य राज्य में दलित मुख्यमंत्री की ताजपोशी कराने पर विचार कर रहा है।

डिरेल होते विपक्षी एकता के प्रयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि और भाजपा की आक्रामक राजनीतिक शैली से हलाकान विपक्षी दलों के नेता एक महागठबंधन बनाने की बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन धरातल पर इन दलों के मध्य एकता के बजाय अविश्वास की खाई दिनों-दिन गहराती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को करारी शिकस्त देने वाली तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनना चाहती हैं। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता ने इस दिशा में अपने प्रयास तेज भी कर दिए हैं। वे दिल्ली आकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलीं। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार से उनका संपर्क लगातार बना हुआ है। तृणमूल की ताकत को वामपंथी दल भी मरे मन से ही सही अब स्वीकारने लगे हैं। इस सबके बावजूद मौका मिलते ही तृणमूल इन विपक्षी दलों के भीतर सेंधमारी करने से बाज नहीं आ रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी सुष्मिता देव को उसने मौका मिलते ही अपने पाले में कर लिया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता लइजिन्हो फालेयरो ने भी पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही तृणमूल ज्वाइन कर ली। इससे विपक्षी गठबंधन की ट्रेन पटरी पर दौड़ने से पहले ही डिरेल होने लगी है।

धामी के कड़े होते तेवर

उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों चौतरफा दबाव में बताए जा रहे हैं। धामी को मुख्यमंत्री बना भाजपा आलाकमान ने एक बड़ा रिस्क लेने का साहस दिखाया। दरअसल दो दफे के विधायक धामी की बनिस्पत प्रदेश भाजपा भीतर कई बरसों का प्रशासनिक अनुभव वाले लगभग डेढ़ दर्जन नेता हैं। इनमें सरकार में शामिल कई नेताओं का नाम समय-समय पर संभावित मुख्यमंत्री बतौर उछलता रहा है। तीरथ सिंह रावत के स्थान पर लेकिन पार्टी आलाकमान ने युवा विधायक धामी का चयन कर इन पुराने चावलों को खासा नाराज कर डाला। अनुशासन की डोर से बंधे ये नेता खुलकर तो विरोध नहीं कर पा रहे हैं किंतु मुख्यमंत्री धामी के लिए नाना प्रकार की समस्याएं पैदा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दो मंत्रियों ने पिछले दिनों अपने विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों की मलाईदार पदों में तैनाती कर सरकार की छिछालेदर करवा डाली है। ऐसे में धामी इन नेताओं की रिपोर्ट आलाकमान को सौंपने वाले हैं।

छवि की नमी

इन दिनों राजनीति में कैमरे का बहुत महत्व हो गया है। हर किसी के अपने छायाकार होते हैं जो उनकी सामाजिक छवि रचते हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों व भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद प्रियंका गांधी की छवि एक जुझारू महिला नेता के रूप में उभरी। लखीमपुर खीरी जाते वक्त जिस तरह उप्र पुलिस ने उन्हें रोका और उन्होंने सख्ती से सामना किया या फिर अतिथिगृह की हिरासत में झाड़ू लगाना। उप्र में जिस तरह से प्रियंका गांधी सक्रिय हैं उससे कार्यकर्ताओं में भी जोश आ गया है। उप्र कांग्रेस के अध्यक्ष लल्लू सिंह कांग्रेस के जमीन से जुड़े उन नेताओं में हैं जो हमेशा सड़क पर दिखते हैं। प्रियंका गांधी की सक्रियता से उन जैसे नेताओं में भी जोश पहुंचा है। उप्र में प्रियंका गांधी से लेकर दीपेंद्र हुड्डा तक के साथ उप्र पुलिस ने जैसा रुखा व्यवहार किया उसे देख जनता के दिल में इन नेताओं के लिए थोड़ी नमी पैदा होने की उम्मीद कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या होता है।

साहब का टेक्नोक्रेट मकान चर्चा में

देश में मप्र के ब्यूरोक्रेट्स किसी न किसी मामले में चर्चा में रहते हैं। वर्तमान समय में एक आईपीएस अफसर की चर्चा प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में खूब हो रही है। दरअसल, साहब इसलिए चर्चा में हैं कि उनका मकान राजसी ठांठ-बांट की तरह बना हुआ है। प्रदेश में मलाईदार और कमाऊ विभागों में रहकर माल छानने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी साहब के मकान को देखकर आश्चर्यचकित हैं। आश्चर्य की सबसे बड़ी बात यह है कि साहब ईमानदार छवि के अफसर हैं। इसलिए उनके सामने ऐसा मकान बनाना चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में उन्होंने अपना टेक्नोक्रेट दिमाग लगाया और ऐसा मकान बना दिया है, जिसे देखने दूसरे अफसर पहुंच रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि राजधानी की सुरम्य पहाड़ी पर साहब ने जो मकान बनवाया है वह इंजीनियरिंग की मिसाल बना हुआ है। इस मकान में प्राकृतिक सोपानों का ऐसा प्रयोग किया गया है, आधुनिक संसाधनों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। दरअसल, जिस तरह प्राचीनकाल में राजाओं के महल बनते थे, जो हर मौसम के अनुकूल होते थे, वैसा ही मकान इन साहब ने बनवाया है। बताया जाता है कि साहब के मकान के निर्माण की लागत भी अनुमान से काफी कम है। इसके पीछे साहब के टेक्नोक्रेट दिमाग का कमाल है। गौरतलब है कि साहब एक टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट हैं। इसलिए उन्होंने अपने अनुभवों को आधार बनाकर यह मकान बनवाया है।

दो दुखियारे... एक-दूसरे के सहारे

मीराबाई के प्रियभजन 'घायल की गति घायल जाणै, जो कोई घायल होय...' आपने सुना ही होगा। प्रदेश में इन दिनों दो राजनेताओं की स्थिति भी कुछ इस तरह की है। कहने को तो दोनों नेता अपनी-अपनी पार्टी के कद्दावर राजनेता हैं, लेकिन वर्तमान में दोनों की नहीं चल रही है। एक नेता सत्तापक्ष में हैं तो दूसरे विपक्ष में। सत्तापक्ष वाले नेता भले ही सरकार में बड़े विभाग के मंत्री हैं, लेकिन उनकी चल नहीं रही है। सूत्र बताते हैं कि नेताजी अपने विभाग में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरे नेताजी ऐसे हैं जो कभी पार्टी में बड़ी हैसियत रखते थे, लेकिन आज उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है। नेताजी ने कई बार विद्रोही मुद्रा भी दिखाई, लेकिन पार्टी में उन्हें भाव नहीं मिला। ऐसे में अब ये दोनों नेता आपस में मिल-बैठकर गिले शिकवे दूर कर रहे हैं। पिछले एक माह में ये दोनों नेता तीन बार मिल चुके हैं और बंद कमरों में मीटिंग कर चुके हैं। इनकी मुलाकात और मीटिंग का विषय क्या है, ये तो वही जानें, लेकिन राजनीतिक वीथिका में माना जा रहा है कि दोनों अपनी-अपनी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए मेल-मुलाकात का यह खेल खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि इन मेल-मुलाकातों से इनकी पार्टी इन्हें महत्व देती है या ऐसे ही ये हाशिए पर पड़े रहेंगे।

पीएस ने बढ़वा दी शराब की बिक्री

प्रदेश में एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा शराबबंदी पर जोर दिया जा रहा है। शराबबंदी के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शराब की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। शराबबंदी की वकालत करने वाले वे लोग हैं जिन्हें सत्ता संगठन में महत्व नहीं मिल पा रहा है, लेकिन शराब की बिक्री बढ़ाने में विभाग के प्रमुख सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जाता है कि कोरोनाकाल में प्रदेश की बदहाल हुई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने स्तर पर अपने विभाग में ऐसी व्यवस्था करे ताकि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। प्रदेश के कमाऊ विभागों में से एक विभाग जिसकी मुखिया महिला अधिकारी हैं, ने भी सरकार की मंशा के अनुसार कार्य करना शुरू किया है। बताया जाता है कि उन्होंने विभाग के अधिकारियों से गत दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और शराब की बिक्री को बढ़ाने पर फोकस करने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि पीएस के निर्देश के बाद प्रदेशभर में शराब की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन इससे राजस्व संग्रह में कितना फायदा होगा, यह तो बाद में ही पता चलेगा। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला है, जब विभाग की मुखिया ने शराब की बिक्री बढ़ाने पर इतना जोर दिया है।

ऐसे होते हैं सरकार में काम

मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों आम चर्चा है कि नौकरशाही मंत्रियों तक की नहीं सुन रही है। कुछ हद तक इसमें हकीकत भी है। लेकिन सरकार में कुछ मंत्री ऐसे भी हैं, जो ताल ठोककर अपना काम करा लेते हैं। प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में एक ऐसा ही ताल ठोक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, शहर और गांव के विकास का कामकाज देखने वाले विभाग के एक सीएमओ के तबादले का मामला है। उक्त सीएमओ ने अपने तबादले के लिए अपने करीबी एक दमदार मंत्री के यहां सिफारिश की। उक्त मंत्रीजी ने इस मामले में विभागीय मंत्री को नोटशीट लिखी। फिर विभागीय मंत्री ने इस संदर्भ में विभाग के आयुक्त को निर्देशित किया। तो आयुक्त ने कायदे-कानून का हवाला देकर तबादला न करने की बात कही। यह बात जैसे ही सीएमओ के करीबी मंत्रीजी को पता चली उन्होंने साहब को तलब किया और निर्देश दिया कि शाम 5 बजे तक तबादले का आदेश लेकर कार्यालय में उपस्थित हों। साहब भी क्या करते, समय पर तबादला आदेश लेकर पहुंच गए। बता दें कि मंत्रीजी वर्तमान में डंडे वाले विभाग की कमान संभाले हुए है।

नेतापुत्रों की धमक

मप्र में 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन अभी से टिकट के लिए चौसर बिछना शुरू हो गई है। खासकर भाजपा में इसके लिए अभी से सक्रियता दिख रही है। ग्वालियर-चंबल संभाग में नेतापुत्रों की धमक दिखाई और सुनाई देने लगी है। ग्वालियर की दक्षिण, पूर्व व भितरवार सीट पर नेतापुत्र नजर गढ़ाए हैं। दक्षिण पर पूर्व राज्यसभा सदस्य के पुत्र की नजर है तो पूर्व पर राजपरिवार से जुड़े पूर्व मंत्री का बेटा नजर गढ़ाए है। भितरवार सीट पर सरकार के दमदार मंत्री के चिरंजीव ने सक्रियता बढ़ा दी है। इसी बीच युवराज के राजनीति की तरफ पहला कदम बढ़ाने से नेतापुत्रों में खलबली मची हुई है। नेतापुत्रों की सक्रियता से अभी से टिकट के समीकरण बनना शुरू हो गए हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में पहले से सक्रिय भाजपा के नेता भी चिंतित हैं। हालांकि उन्हें भरोसा है कि भाजपा में वंशवाद की बजाय कार्यकर्ता की राय को अहमियत दी जाती है। इसी भरोसे पर यह नेता अपना मन समझा रहे हैं।

अक्स का आईना

देश में जनसंख्या नीति जरूरी है। इस बारे में एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अभी भारत युवाओं का देश है, 30 साल बाद ये सब बुड्ढ़े बनेंगे, तब इन्हें खिलाने के लिए हाथ लगेंगे। और उसके बाद काम करने वाले कितने लोग लगेंगे, इस पर विचार जरूरी है।

● **मोहन भागवत**

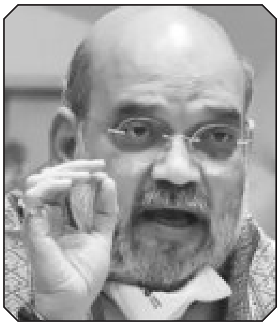

भारत की हमेशा कोशिश रही है कि वह पड़ोसी देशों के साथ समन्वय के साथ रहे। लेकिन पाकिस्तान को यह पसंद नहीं आ रहा है। वह भारत के खिलाफ लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। शायद पाकिस्तान भूल गया है कि एक बार उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करने में भारत देरी नहीं करेगा।

● **अमित शाह**

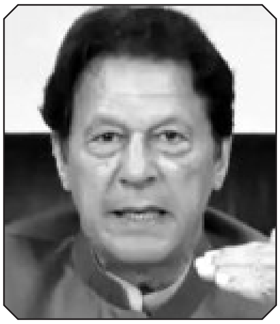

इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इंग्लैंड या दुनिया का कोई दूसरा देश यही काम भारत के साथ करने की हिम्मत कर सकता है। कोई भी ये नहीं करेगा और इसकी वजह यह है कि बीसीसीआई के पास पैसा है। दुनिया की क्रिकेट पर भारत की हुकूमत है। इसलिए पूरा विश्व उसके खिलाफ नहीं जा सकता।

● **इमरान खान**

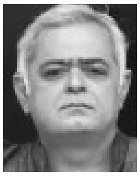

कई देश पहले ही मारीजुआना के उपयोग को लीगल कर चुके हैं। हमारे यहां भी ऐसा होना चाहिए। सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है। क्योंकि कई देशों में इसे गैर अपराधी बना दिया गया है। भारत में इसका उपयोग हैरेसमेंट के लिए किया जाता है।

● **हंसल मेहता**

2012 में संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला-रामलीला के सेट पर मेरी और रणवीर की नजदीकियां बढ़ीं। उसके बाद धीरे-धीरे हम एक-दूसरे को डेट करने लगे और बाद में शादी कर ली। हम दोनों ने एक-दूसरे को पूरी तरह समझ-बूझकर शादी का फैसला किया है। इसलिए आज हमारी जोड़ी लोगों के लिए आदर्श बनी हुई है। मेरा कहना है कि हर स्त्री और पुरुष को अपने जीवनसाथी के चयन में बारीकी रखनी चाहिए। बाद में एक-दूसरे को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने शादी का फैसला काफी सोच-समझकर लिया है, इसीलिए आज मेरा वैवाहिक जीवन खुशहाल है।

● **दीपिका पादुकोण**

वाक्युद्ध

लखीमपुर खीरी में जिस तरह किसानों को रौंदा गया। वह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद भी केंद्र और राज्य सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में किसानों को न्याय कैसे मिलेगा।

● **प्रियंका गांधी**

कांग्रेस तो हर मामले में राजनीतिक रोटी सेंकती है। लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ वह निश्चित रूप से दुखद है। कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले को तूल देकर देश में आग लगा रहे हैं। यह समय आग लगाने का नहीं बल्कि पीड़ितों को राहत और न्याय दिलाने का है।

● **संबित पात्रा**

यूपीएससी में मप्र का दबदबा

मप्र निरंतर प्रगति की उड़ान भर रहा है। मप्र की इस प्रगति में चार चांद लगाए हैं यूपीएससी में चयनित 38 अभ्यार्थियों ने। गौरतलब है कि यूपीएससी में अभी तक बिहार, उप्र और दक्षिण भारतीय राज्यों का दबदबा रहता था। लेकिन इस बार मप्र के युवाओं ने भी यह दिखा दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। विगत दिनों प्रदेश सरकार ने इन युवाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थी कठोर परिश्रम, आत्मविश्वास, एकाग्रता, मजबूत इच्छा-शक्ति और निरंतर प्रयासों से बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मप्र के विद्यार्थियों ने इस वर्ष लगभग दोगुनी संख्या में यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयनित होकर यह सिद्ध कर दिया है। मप्र सरकार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हरसंभव सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे लंबी उड़ान भरें। उड़ने के लिए अनंत आसमान है। यूपीएससी जैसी परीक्षा में चयनित होना गर्व की बात है, लेकिन चयनित विद्यार्थियों को सेवा में आने के बाद ऐसे कार्य करने हैं कि वे सदैव याद रखे जाएं। आम जन के प्रति स्नेह हो और देश और प्रदेश के निर्माण में भरपूर योगदान भी दें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सिविल सर्विसेस धन कमाने का माध्यम नहीं बल्कि देश बनाने का तरीका सीखने और राष्ट्रसेवा का माध्यम है। आज भी बहुत से प्रशासक अपने कार्यों के लिए याद किए जाते हैं। सिविल सेवाएं इतिहास रचने का भी माध्यम बनती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल सेवा और अन्य सेवाओं में तीन तरह के अधिकारी होते हैं। प्रथम जो रूटीन किस्म का कार्य करते हैं, दूसरे जो कार्य को अटकाने में विश्वास रखते हैं और तीसरे जो नियमों की परिधि में निर्णय भी लेते हैं और वांछित लक्ष्य की पूर्ति करते हुए कार्यों से हमेशा याद रखे जाते हैं। मुख्यमंत्री ने आईएएस स्व. एमएन बुच का स्मरण करते हुए उन्हें इस श्रेणी का अफसर बताया जिन्हें जनता हमेशा याद रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद को सुख दे सकें, सदैव ऐसे प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को जरूरी बताया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि सड़क खोदी जाती है तो केबिल बिछाने वाला विभाग अलग होता है, पाइप लाइन सुधारने वाला विभाग अलग और वापस सड़क की मरम्मत करने वाला विभाग अलग। यदि इनमें तालमेल नहीं है तो जनता को कष्ट होता है। इसलिए सिविल सर्विसेस में सकारात्मक एप्रोच की आवश्यकता होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी योग्यता और रूचि के अनुसार कैरियर चुनता है तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि सुरों में माहिर लता मंगेशकर को कोई सरकारी नौकरी का आग्रह करता तो यह बेतुकी बात होती। वे गायन में बेमिसाल हैं इसलिए उस क्षेत्र में आगे बढ़ी और बेहद कामयाब हुईं। मप्र के चयनित छात्र-छात्राएं पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र सेवा कर अपने चयन को सिद्ध करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के महाअभियान पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को आत्मबल और आत्मविश्वास के माध्यम से आत्मनिर्भरता के विजन तक पहुंचाने वाला प्लान माना है। मप्र सक्रिय रूप से इस अभियान से जुड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र सरकार ने विद्यार्थियों के कैरियर निर्माण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ ही आईआईटी और आईआईएम के लिए चुने गए विद्यार्थियों की फीस भरने का कार्य किया है। इसके अलावा छात्रावास उपलब्ध न होने पर विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना में कमरे के किराए की राशि का भुगतान करवाया गया। सरकार इस तरह की सुविधाएं दे सकती हैं, लेकिन मुख्य दायित्व विद्यार्थी का ही होता है, जो अपने व्यक्तिगत प्रयासों से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थियों को इस तरह की परीक्षाओं में चयनित होने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

इस बार इन्होंने मारा मैदान

इस बार यूपीएससी में मप्र के जिन युवाओं ने अपना लोहा मनवाया है, उनमें भोपाल की जागृति अवस्थी ने देश में दूसरा स्थान पाया है। वहीं जबलपुर के अर्थ जैन ने 16वीं, अलीराजपुर की राधिका गुप्ता ने 18वीं, सतना के विनायक चामड़िया ने 47वीं, जबलपुर की अहिंसा जैन ने 53वीं, देवास के आयुष गुप्ता ने 98वीं, सिंगरौली के अरविंद कुमार शाह ने 123वीं, भोपाल के कार्तिक श्रोत्रिया ने 124वीं, ग्वालियर के हिमांशु गुप्ता ने 139वीं, भोपाल के शुभम अग्रवाल ने 153वीं, शिवपुरी के नरेंद्र रावत ने 165वीं, होशंगाबाद के अभिषेक खंडेलवाल ने 167वीं, भोपाल के कृष्ण लालचंदानी ने 216वीं, ग्वालियर के आशुतोष श्रीवास्तव ने 223वीं, इंदौर के सुमित कुमार सिंह ने 229वीं, विदिशा के शुभम बजाज ने 232वीं, भोपाल के साहिल खरे ने 243वीं, बैतूल के श्रेयांश सुराना ने 269वीं, उज्जैन के ऋषभ रूनवाल ने 281वीं, मुरैना के संदीप राजौरिया ने 290वीं, इंदौर की पल्लवी वर्मा ने 340वीं, जबलपुर के रोहित नेमा ने 347वीं, सिंगरौली के मनोज कुमार ने 358वीं, सतना के शिवम प्रजापति ने 407वीं, गुना की जेबा खान ने 423वीं, सिंगरौली के रोहित कुमार शाह ने 448वीं, भोपाल के टी प्रतीक राव ने 459वीं, भोपाल के दीपांशु गीद ने 490वीं, जबलपुर के प्रखर पांडे ने 507वीं, इंदौर के अरजीत महाजन ने 521वीं, ग्वालियर की उर्वशी सेंगर ने 532वीं, चंद्रशेखर मेहरा ने 543वीं, गुना के विशाल धाकड़ ने 579वीं, सागर की दामिनी दिवाकर ने 594वीं, खरगौन की निमिशी त्रिपाठी ने 622वीं, भिंड के विकास सेंठिया ने 642वीं, बालाघाट के विनीत बांसोद ने 692वीं और इंदौर के श्लोक वाल्कर ने 699वीं रैंक हासिल की है।

मप्र में एक लोकसभा के साथ ही तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत-हार से सरकार की सेहत पर भले ही कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टियों की चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसलिए इन उपचुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। उपचुनाव के शंखनाद के साथ ही इस मिशन 2023 का आगाज भी माना जा रहा है। इसलिए चुनावी मैदान में प्रत्याशियों से अधिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की लोकप्रियता दांव पर है।

दांव पर लोकप्रियता

वर्ष 2018 में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस ने अपनों की बगावत के कारण 2020 में सत्ता गंवा दी। ऐसे में वह 2023 में हर हाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। वहीं भाजपा लगातार पांचवी बार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। इसलिए दोनों पार्टियों ने उपचुनाव के शंखनाद के साथ ही मिशन 2023 का भी आगाज कर दिया है। ऐसे में ये उपचुनाव दोनों पार्टियों के साथ ही शिवराज और कमलनाथ की लोकप्रियता का पैमाना भी हैं। यानी इन उपचुनावों में शिवराज और कमलनाथ की लोकप्रियता दांव पर लगी है।

उल्लेखनीय है कि खंडवा लोकसभा सीट के साथ जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन सीटों पर जीत-हार से प्रदेश की राजनीति पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। फिर भी इनकी महता कम नहीं है। दरअसल, इन उपचुनावों में भाजपा और कांग्रेस की रणनीति की अग्निपरीक्षा भी होगी। भाजपा जहां कोरोना, किसानों को राहत, मोदी सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस के बिखराव को मुद्दा बनाकर जनता का अपना बनाने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस बढ़ती महंगाई, कोरोना कुप्रबंधन, किसान आंदोलन, कमलनाथ सरकार के काम गिना रही है। साथ ही दोनों पार्टियां 2023 के विधानसभा का आधार रख रही हैं। इस कारण उपचुनाव काफी रोचक हो गए हैं।

उपचुनाव के मैदान में भाजपा पूरी तरह संगठित नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तो हैं ही पूरा मंत्रिमंडल, पूरा संगठन, विधायक मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं कमलनाथ अलग-थलग नजर आ रहे हैं। उपचुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने अपनी पूरी जमावट कर ली थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी है। वहीं मंत्रियों और विधायकों ने कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं के बीच अपनी बात पहुंचा दी है। जबकि मैदानी मार्चे पर कांग्रेस भाजपा से काफी पिछड़ी नजर आ रही है।

भाजपा पूरी तरह सचेत

दमोह उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी सत्तापक्ष को हार झेलनी पड़ी थी। इसी से भाजपा सचेत है। कांग्रेस पार्टी देशभर में अपनी बिखरी छवि को समेटते हुए चुनावी मैदान में कूद रही है। उसके लिए भी राह आसान नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो तीन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा 26,680 वोटों से पिछड़ी हुई है। वर्ष 2018 के चुनाव में आलीराजपुर जिले की जोबट और निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर सीट कांग्रेस ने जीती थीं, वहीं सतना जिले की रैगांव सीट पर भाजपा का कब्जा हुआ था। लोकसभा की बात करें तो खंडवा सीट पर कांग्रेस के अरुण यादव को भाजपा के नंदकुमार सिंह चौहान ने करीब पौने तीन लाख मतों से परास्त किया था। अब इस बार दोनों दल तैयारी तेज करते हुए अपना पक्ष मजबूत करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के घोषणा के पहले ही इन सभी क्षेत्रों के दौरे कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल उपचुनाव की यह जंग किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं लग रही है। यही कारण है कि दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही अपना पूरा दमखम दांव पर लगा दिया है।

खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा-कांग्रेस के अपने-अपने दांव हैं। भाजपा ने ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट देने के साथ दबाव की राजनीति भी की है। इस सीट पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, नंदकुमार सिंह के बेटे हषवर्धन और वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे की दावेदारी थी। तीनों पिछले दो महीने से पूरे जोर-शोर से दावेदारी के लिए भोपाल से दिल्ली तक लॉबिंग करने में लगे रहे, लेकिन पार्टी ने झटका देकर टिकट ज्ञानेश्वर को दे दिया। यानी एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। अब पार्टी के तीनों दावेदार ज्ञानेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। यदि तीनों में से किसी एक को टिकट दे दिया जाता, तो बाकी दोनों धड़े नाराज होकर बैठ जाते। लेकिन, अब तीनों ही दमदार धड़े एक जैसी हालत में हैं। इस कारण तीनों भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी मैदान में उतर गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने राजनारायण पूरनी पर भरोसा जताया। पूरनी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खेमे से माने जाते हैं। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के चुनाव से हटने के बाद पूरनी को मौका मिला। दिग्विजय खेमे से होने के कारण अरुण यादव भी उनकी मदद को मजबूर हैं। इस कारण कांग्रेस यहां पूरनी के सहारे जीत का मंसूबा बनाए है। भाजपा ने यहां ओबीसी कार्ड खेला है। इस सीट पर 26 फीसदी ओबीसी आबादी है। वहीं कांग्रेस ने यहां सामान्य वर्ग का कार्ड खेला है। इस सीट पर 20 फीसदी सामान्य वर्ग आबादी है। गौरतलब है कि छह बार के सांसद नंदकुमार सिंह चौहान का इसी

वर्ष मार्च में कोरोना से निधन हो गया। इस सीट पर अब तक हुए 7 बार भाजपा, 9 बार कांग्रेस को जीत मिली। इस सीट पर दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है। वर्ष 1977 में लोकदल पार्टी के परमानंद ठाकुर दास जीते। असामायिक निधन पर 1979 में उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा के कुशाभाऊ ठाकरे जीते।

कांग्रेस के कब्जे में रही जोबट विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को भितरघात का खतरा है। यहां कांग्रेस से भाजपा में आई सुलोचना रावत को भाजपा ने टिकट दिया है। यह सीट भाजपा के लिए मुश्किलों से भरी थी, क्योंकि परंपरागत रूप से यह कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन से इस पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सुलोचना को टिकट देकर भाजपा ने कांग्रेस में फूट को और बढ़ाने के साथ खुद को यहां जमाने की कोशिश की है। कांग्रेस इस सीट को बचाने के लिए महेश पटेल पर दांव खेल रही है। पटेल परिवार के नेटवर्क को यहां मजबूत माना जाता है। इसलिए कांग्रेस ने महेश पर दांव चला। यहां कांग्रेस के सर्वे में भी महेश का नाम था। पार्टी को यहां परंपरागत वोटबैंक पर भरोसा है। सुलोचना के जाने से यहां महेश पर भरोसा जताया गया।

भाजपा ने जोबट में कांग्रेस की परंपरागत सीट पर कांग्रेस नेता को लाकर जंग मजबूत की है। पार्टी का मानना है कि कांग्रेस का एक खेमा सुलोचना रावत के साथ आ गया है। सुलोचना रावत पूर्व मंत्री हैं और क्षेत्र में इनकी पकड़ है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल अलीराजपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनके भाई मुकेश पटेल कांग्रेस विधायक हैं। क्षेत्र में परिवार का तगड़ा नेटवर्क है। इनका वोटबैंक मजबूत हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय खेमे से माने जाते हैं। लेकिन यहां इन्हें भितरघात का खतरा है। आदिवासी बहुल इस सीट की विधायक कलावती भूरिया का निधन 24 अप्रैल को हुआ था। उन्होंने भाजपा के माधोसिंह डावर को परास्त किया। 2018 में कांग्रेस के बागी विशाल रावत ने कांग्रेस के वोटों में लंबी सेंध लगाई, फिर भी भाजपा जीत नहीं पाई।

पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने जहां सपा के बागी शिशुपाल सिंह यादव को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र राठौर को। इसलिए यहां की चुनावी फिजा में बागी बनाम परिवारवाद का नारा बुलंद है। यह सीट भी भाजपा के लिए मुश्किल भरी है। यह भी कांग्रेस की सीट रही है, जिस पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर विधायक थे। उनके निधन से सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब यहां सपा से आए शिशुपाल को टिकट देकर जंग मजबूत की गई है। शिशुपाल यहां मजबूत नेताओं में से एक हैं। भाजपा का काडर यहां कमजोर था, जिस कारण बाहरी को टिकट दिया गया। इस सीट पर कांग्रेस नितेंद्र के सहारे ही पूरा दांव चल रही है। नितिन पहले भी अपने पिता बृजेंद्र सिंह राठौर की राजनीतिक नेटवर्किंग देखते थे। इसलिए पूरी मेहनत उनकी है। कांग्रेस को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर काबिज रहे बृजेंद्र सिंह राठौर का 2 मई को निधन हुआ था। 2008 में बृजेंद्र ने भाजपा प्रत्याशी सुनील नायक को हराया था। हालांकि मतदान के दिन ही नायक पर फायरिंग हुई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई। तब बृजेंद्र सिंह राठौर और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2013 में सुनील नायक की पत्नी अनिता ने बृजेंद्र सिंह को हरा दिया। भाजपा ने 2018 में अभय प्रताप सिंह को टिकट दिया, जो चौथे नंबर की पार्टी रहे।

भाजपा ने रैगांव सीट से प्रतिमा बागरी को उम्मीदवार बनाया है। प्रतिमा महिला मोर्चा में लंबे समय से सक्रिय रही। इसी वजह से उन्हें जुलाई में जिला महामंत्री बनाया गया था। प्रदेश संगठन ने पुष्पराज बागरी का नाम भी दिल्ली भेजा था, **लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व** ने प्रतिमा के नाम पर मुहर लगाई। यह सीट कांग्रेस के लिए मायने रखती है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां कल्पना वर्मा को टिकट देकर जंग दिलचस्प की है। रैगांव पूर्व में कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में शामिल था, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस को यहां शिकस्त मिली। कांग्रेस अब इस सीट पर वापसी की उम्मीद संजोए है। क्षेत्र में पूर्व मंत्री अजय सिंह प्रमुख नेता है। कल्पना को उनके खेमे का माना जाता रहा है, लेकिन अब कमलनाथ खेमे के साथ है। इसलिए कल्पना को दोनों खेमों से यहां मदद मिल सकेगी।

● कुमार राजेन्द्र

कांग्रेस को हर सीट पर चुनौती

एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। हर सीट की चुनौती अलग है। मुख्यतः दो चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। पहली चुनौती गुटबाजी की है। दूसरी बड़ी चुनौती पार्टी के नेतृत्व को लेकर है। पिछले साढ़े तीन साल से कमलनाथ राज्य में कांग्रेस को अपने हिसाब से चला रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पंद्रह साल बाद सत्ता में वापस लौटी तो कमलनाथ ने इसे अपनी रणनीति की जीत के तौर पर लिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव सरकार बनने के बाद हाशिए पर डाल दिए गए। सिंधिया, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अजय सिंह और अरुण यादव अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अजय सिंह के पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। जबकि अरुण यादव के पिता स्वर्गीय सुभाष यादव दिग्विजय सिंह सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे हैं। वे बड़े किसान नेता माने जाते थे। कमलनाथ से पहले अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के साढ़े चार साल तक अध्यक्ष रहे हैं। केंद्र में मंत्री भी रहे। हाल ही में कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अरुण यादव के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने तंज कसा था कि उनके कई कॉलेज और हजार एकड़ कृषि जमीन है। पूर्व मंत्री का अपनी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पर यह तंज इस बात को लेकर था क्योंकि वे उपचुनाव की बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे। सज्जन सिंह वर्मा उस कमेटी के समन्वयक हैं, जो चार सीटों के उपचुनाव के लिए बनाई गई है।

प्रमोशन में आरक्षण का पेंच

मप्र में सरकारी पदों पर प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट 21 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगा। शीर्ष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने लिखित पक्ष सुन लिया है, चूंकि न्यायालय में अवकाश घोषित हो गया है, इसलिए आगे की सुनवाई के दौरान मप्र सहित अन्य राज्य अपनी-अपनी दलील कोर्ट के समक्ष रखेंगे। मप्र सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट मनोज गोरकेला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में 21 अक्टूबर को (कोर्ट नंबर-5) सुनवाई दोबारा शुरू होगी। सबसे पहले मप्र सरकार पक्ष रखेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले में 10 अक्टूबर को फैसला देंगे, लेकिन अवकाश के चलते अब त्योहार के बाद सुनवाई होगी।

इधर, सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि सभी 52 विभागों से बैकलॉग (रिक्त पदों) की जानकारी विभागों से मंगाई है। जिनमें से अब तक 38 विभागों ने ही जानकारी भेजी है। शेष विभागों को जानकारी भेजने के लिए कहा गया है। विभागों से अभी तक आई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कर्मचारियों के एक लाख 15 हजार 756 पद खाली हैं। प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिसमें सरकार को प्रदेश में कर्मचारियों की वर्गवार संख्या बतानी है। इसकी तैयारी के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से वर्गवार कर्मचारियों के स्वीकृत, भरे और खाली पदों की जानकारी मांगी है। ये निर्देश विभाग ने तीन सितंबर को जारी करते हुए 20 सितंबर तक जानकारी मांगी थी, पर अब तक 38 विभागों ने जानकारी दी है। बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सहित सभी राज्यों का पक्ष सुनने के बाद कहा था कि मामले में आगे सुनवाई नहीं होगी। सभी राज्य 2 सप्ताह में अपना पक्ष लिखित में पेश करें।

शीर्ष अदालत ने 5 अक्टूबर से लगातार केंद्र और राज्य सरकार को आधा-आधा घंटे पक्ष रखने के लिए समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा था कि कई वर्षों से यह मामला लंबित है। इसकी वजह से कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। अब आगे तारीख नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मामले के फैसले में इंदिरा साहनी और नागराज के केस को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में फैसला दे चुका है। हाईकोर्ट ने पदोन्नति नियम में आरक्षण, बैकलॉग के खाली पदों को कैरिफारवर्ड करने और रोस्टर संबंधी प्रावधान को संविधान के विरुद्ध मानते हुए इन पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इस पर फैसला होना बाकी है।

प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति होती थी, लेकिन 2016 में उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। दरअसल, अनारक्षित वर्ग की ओर से अनुसूचित जाति-जनजाति को दिए जा रहे आरक्षण की वजह से उनके अधिकार प्रभावित होने को लेकर हाईकोर्ट में 2011 में 24 याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें सरकार द्वारा बनाए मप्र पब्लिक सर्विसेज (प्रमोशन) रूल्स 2002 में एससी-एसटी को दिए गए आरक्षण को कठघरे में रखा गया था। मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को राज्य में एससी-एसटी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय यादव की बेंच ने कहा है कि यह नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 व 335 के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को दिए गए दिशा-निर्देश के खिलाफ है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए। ऐसे में अब पदोन्नति तभी हो सकती है, जब कोर्ट इसकी अनुमति दे। सरकार ने इसको लेकर कोर्ट से अनुरोध भी किया था पर अनुमति नहीं मिली। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन कर्मचारियों व अधिकारियों को हुआ, जो पिछले 5 साल में रिटायर हो गए। जिसकी संख्या करीब 1 लाख बताई जाती है।

● **प्रवीण कुमार**

1 लाख शासकीय सेवक बिना प्रमोशन रिटायर हो गए

प्रमोशन में आरक्षण मामले में 30 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद से मप्र में अभी तक एक लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। इनमें से अधिकांश को प्रमोशन मिलना था। 20 हजार से ज्यादा को प्रमोशन का इंतजार है। सरकार प्रमोशन में आरक्षण के पक्ष में है। उसने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर स्टे ले लिया है। इसी कारण किसी भी विभाग में डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) की बैठक नहीं हुई। यही वजह है कि अधिकारी-कर्मचारी बिना प्रमोशन रिटायर होते जा रहे हैं। मप्र के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की योजना सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। हालत यह है कि हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति पाए रिटायर हो गए और सरकार को चार साल में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लग गई। इस सप्ताह फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई के आसार हैं। इस पेशी में प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को सशर्त पदोन्नति देने की अर्जी दाखिल करने की तैयारी की है। दरअसल अप्रैल 2016 में मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।

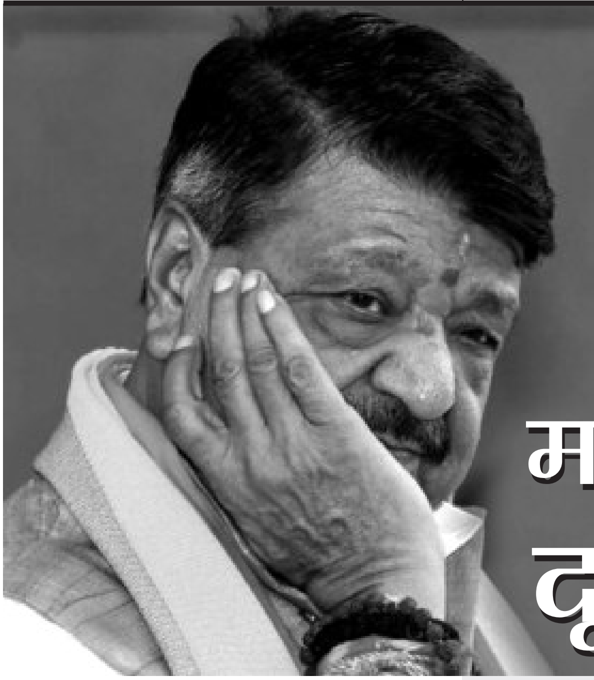

पिछले कुछ महीनों के दौरान भाजपा के अंदर सत्ता और संगठन में जिस तरह फेरबदल हुए हैं, उससे मप्र के कुछ नेताओं को लगा था कि यहां भी ऐसा परिवर्तन हो सकता है, इसके लिए नेताओं ने जमकर लॉबिंग भी शुरू कर दी थे। इन नेताओं में सबसे आगे कैलाश विजयवर्गीय रहे। उन्होंने दिल्ली से लेकर भोपाल तक जमकर मेल मुलाकात की थी, लेकिन केंद्रीय संगठन ने एक बार फिर उन्हें मप्र की राजनीति से दूर कर दिया है।

मप्र की राजनीति से दूर रहेंगे कैलाश

भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यसमिति में महासचिव की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही विजयवर्गीय की अगली भूमिका को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उन पर विराम लग गया है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि पार्टी उन्हें अब चुनाव नहीं लड़ाना चाहती। पहले उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। आने वाले चुनाव में फिर उन्हें किसी राज्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

इस बार मप्र में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री के लिए दावेदार भी कहा जा रहा था। जीत कांग्रेस की हो गई। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के साथ कांग्रेस से भाजपा में आए तो कमलनाथ सरकार गिर गई, तब दोबारा विजयवर्गीय को लेकर अटकलें लगने लगीं, लेकिन पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को ही मप्र की बागडोर सौंपी। इसके पूर्व लोकसभा चुनाव के दौरान जब शंकर लालवानी का नाम तय नहीं हुआ था, तब भी उनके समर्थकों को विश्वास था कि विजयवर्गीय को इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। तब विजयवर्गीय के पास पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी थी। हालांकि, एक-दो मौके पर उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी जो आदेश देगी, उसका पालन करेंगे। टिकट लालवानी को मिला और उन्होंने 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज कर अपनी जगह मजबूत बना ली।

पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में आ गए और इससे भी विजयवर्गीय का कद बढ़ा। चुनाव में भाजपा की हार के बावजूद विजयवर्गीय का मजबूत पक्ष यह था कि कई हारी हुई सीटों पर वोटों का अंतर बहुत कम था। इस बीच स्मृति ईरानी को भी पश्चिम बंगाल भेजा गया। इस तरह के समीकरणों के बीच पार्टी में विजयवर्गीय की अगली भूमिका को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। इधर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनते ही तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए विधायकों ने फिर अपना पाला बदला और ममता सरकार के साथ हो गए। इस तरह उतार-चढ़ाव के बीच विजयवर्गीय की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे। वैसे कुछ समय पहले ही पार्टी के एक धड़े ने यह भी प्रचारित किया कि राज्यसभा की एक सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव में मप्र कोटे से विजयवर्गीय का नाम तय किया जा सकता है, लेकिन पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने डॉ. एल मुरुगन के नाम पर मोहर लगा दी, जो अब केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री है। बहरहाल, अब राजनीतिक समीकरण काफी बदल रहे हैं और अब यह तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है कि विजयवर्गीय की मप्र की राजनीति में दखल नहीं होगा और उन्हीं कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी।

मप्र से नए चेहरों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को शामिल किया गया है। सिंधिया लगभग डेढ़ साल पहले ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। 80 सदस्यीय कार्यसमिति में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, डॉ. वीरेंद्र खटीक को भी सदस्य बनाया गया है। यह पहला अवसर है जबकि राष्ट्रीय कार्यसमिति में मप्र का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। कार्यसमिति में 50 विशेष आमंत्रित सदस्य और 179 स्थाई आमंत्रित (पदेन) सदस्य बनाए गए हैं। कार्यसमिति में भी सामाजिक और **भौगोलिक संतुलन** बनाए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहले भी राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के कार्यकाल में तोमर राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कैलाश विजयवर्गीय, कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, राष्ट्रीय मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी कार्यसमिति में शामिल किए गए हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

हाल ही में कई नेताओं की घनिष्ठता से भी जोड़ा

वैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद विजयवर्गीय की मप्र में ज्यादा सक्रियता रही। खासकर इंदौर में। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के गृहमंत्री व इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर आगमन पर उनके निवास पर भेंट की और खाना भी खाया। तोमर तो हाल ही में विजयवर्गीय के एक पारिवारिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इंदौर के कार्यक्रम में भी विजयवर्गीय साथ थे। इस तरह इन मुलाकातों के कई अर्थ निकाले गए। वैसे वर्तमान स्थिति में सांसद शंकर लालवानी व जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की इंदौर में ज्यादा सक्रियता है। यह सक्रियता कोरोनाकाल से ही है और इंदौर से जुड़ी उन्हीं की राय व निर्णय पार्टी स्तर पर लिए जा रहे हैं। इनके साथ भी अब स्थानीय अन्य नेता मधु वर्मा, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता की भी सिंधिया गुट से नजदीकी बढ़ती जा रही है।

फिर धड़ों में बंटी मप्र कांग्रेस

मप्र कांग्रेस में गुटबाजी फिर सतह पर है। वजह टिकट की खींचतान, वर्चस्व का खेल और अनसुनी। चर्चा में है खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव में टिकट के लिए अरुण यादव का दावेदारी से खुद को पीछे हटाना। यादव जो मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, फिर मप्र कांग्रेस की कमान संभाली और नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन खुद टिकट नहीं मांगा, जैसा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कहते हैं कि यादव ने मुझसे कभी टिकट नहीं मांगा। हालांकि यादव ये ऐलान कर चुके हैं कि वह टिकट नहीं चाहते। इसी इनकार को उनकी नाराजगी माना जा रहा है। साथ ही कांग्रेस में गुटबाजी के दौर की वापसी भी। 2018 में जब कमलनाथ मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, तब उन्होंने पार्टी के कई धड़ों को एक करने में सफलता हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह भी यही मानी गई थी। हालांकि 2020 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद पार्टी में गुटबाजी कई मौकों पर सतह पर आई है।

दरअसल, अरुण यादव को पिता सुभाष यादव से सियासी विरासत में कांग्रेस पार्टी में बड़ा कद और खंडवा क्षेत्र में जमीनी पकड़ मिली, जिसके बूते वह केंद्रीय मंत्री से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर कर चुके हैं। मप्र कांग्रेस में बड़ा ओबीसी चेहरा भी हैं। लेकिन 2018 में कमलनाथ के मप्र कांग्रेस में दखल देने के बाद से उनके सियासी ग्राफ में गिरावट महसूस की जा रही है। कमलनाथ सरकार के विदा होने के बाद से कांग्रेस अपनी गुटबाजी को ढंक पाने में भी कमजोर साबित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस को अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। उनकी कोशिशें कभी अजय सिंह, तो कभी अरुण यादव और कभी-कभी दिग्विजय सिंह को भी नागवार गुजर जाती है। यह अलग बात है कि नाराजगी पार्टी स्तर तक ही रहती है **और नेता** सार्वजनिक रूप से इसका खंडन कर देते हैं। इस बीच कोरोना के चलते भाजपा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव में यादव ने वापसी का अवसर देखकर तैयारियां शुरू कर दीं। इधर, करीब दो माह पूर्व कमलनाथ की निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा से मुलाकात और उनका ये कहना कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, यादव की उम्मीदों को धूमिल कर गया। कमलनाथ ने दो टूक ये भी बता दिया था कि यादव ने तो मुझसे टिकट की बात ही नहीं की। इन घटनाक्रम से मप्र कांग्रेस नाथ बनाम यादव की चर्चाओं से घिर गया। भाजपा को भी यादव की नाराजगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे निर्णय की संभावनाएं दिखने लगी। हालांकि यादव ने कांग्रेस में ही रहने की बात दोहराई।

पार्टी सूत्र बताते हैं कि यादव टिकट को लेकर खंडवा में कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की स्थिति को भाप चुके थे। उन्हें अंदाजा था कि दावेदारी की स्थिति में स्थानीय स्तर पर अपेक्षित समर्थन में मुश्किल आ सकती है। ऐसे में परिणाम आशाजनक नहीं हुए तो सियासी भविष्य पर असर पड़ सकता है। सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ के सर्वे में अरुण यादव का नाम ही नहीं था। सूत्रों की मानें तो यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा था। ऐसे में उन्हें संकेत मिल गए थे कि यदि दबाव बनाकर टिकट हासिल भी कर लेते हैं, तो मैदानी स्तर पर पार्टी की ओर से अपेक्षित सहयोग न मिले, जिसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने दावेदारी से खुद को अलग कर लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जानते हैं कि पार्टी सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में मप्र में मौजूद है। सत्ता वापसी की संभावना बोलती हुई संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लाजमी है कि ऐसी कोशिशों में कुछ नाराजगी भी झेलनी ही पड़ती है।

मप्र कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव में टिकट की अपनी दावेदारी वापस ले ली है। यादव वजह पारिवारिक बता रहे हैं। लेकिन, कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि वे रूठकर घर बैठने जा रहे हैं। यादव के अचानक यूं रूठ जाने से कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? यादव दो बार सांसद रह चुके हैं। पिछला लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद कमलनाथ ने पूरी तरह से उन्हें हाशिए पर डाल रखा है। उपचुनाव में उनकी उम्मीदवार को भी कमलनाथ खारिज कर चुके हैं। माना जा रहा है कि यादव ने अपना सम्मान बचाने के लिए टिकट की दावेदारी से कदम पीछे खींचे हैं।

राज्य में कांग्रेस की मौजूदा राजनीति अभी भी वैसे ही है, जैसी पिछले चार दशक से भी अधिक समय से चली आ रही है। राजनीति के कुछ मुख्य पात्र अभी भी अंगद के पांव की तरह मजबूत हैं। चार दशक पहले की राजनीति में शुक्ल बंधुओं (श्यामाचरण शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल) को छोड़ दिया जाए तो कमलनाथ के अलावा अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया गुट के बीच कांग्रेस बंटी हुई थी। अस्सी के दशक में कमलनाथ ने अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया। नब्बे के दशक में दिग्विजय सिंह का साथ दिया। अर्जुन सिंह के गुट में दिग्विजय सिंह के अलावा सुभाष यादव भी कद्दावर नेता थे। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े होने के कारण उनकी पकड़ किसानों पर थी। यादवों के वे सर्वमान्य चेहरा थे।

● **अरविंद नारद**

दावेदारी छोड़ने के पीछे की राजनीतिक वजह

कांग्रेस पार्टी में अरुण यादव की उपेक्षा के साथ-साथ यह चर्चाएं भी चलीं कि वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इसका खंडन भी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कहते हैं कि पार्टी की विचारधारा से सहमत हर व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले हैं। यादव के मैदान से हटने की घोषणा से भाजपा उत्साहित है। गत दिनों भाजपा ने आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस की नेता सुलोचना रावत और उनके बेटे विकास रावत को इंट्री दी थी। इसके बाद यादव ने दावेदारी वापस ले ली। हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति के लिहाज से यादव वोटर बेहद महत्वपूर्ण हैं। उप्र और बिहार में मुलायम सिंह और लालू यादव को अपनी जाति का लाभ भी मिला। 2014 में जब अरुण यादव को मप्र कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त उप्र के यादवों को साधने की रणनीति का वे हिस्सा थे। दिग्विजय सिंह ने ही उनका नाम आगे बढ़ाया था। इसके बाद भी उप्र के यादव कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। मप्र में जरूर अरुण यादव को अपने पिता की विरासत का लाभ मिला। विरासत में उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी मिले। मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता कहते हैं कि अरुण यादव को जिम्मेदारी के साथ हर नेता का साथ भी मिला। कांग्रेस कमेटी ने जब भी कोई आंदोलन किया हर नेता ने उसमें भागीदारी कर सफल बनाया।

मप्र में रहते हैं 25 प्रतिशत नशेड़ी!

आश्चर्य नहीं कि नशाखोरी से कलंकित बालीवुड फिर से विवादों में है। जिस बालीवुड को देश के युवा आदर्श मानते हैं वहां नशाखोरी चरम पर है। इसका असर भारतीय समाज पर भी पड़ रहा है। मप्र की बात करें तो यहां की एक चौथाई आबादी नशेड़ी हो गई है। राज्य में शराबबंदी के जब तब उठते मुद्दे के बीच यह विषय भले ही बहस का मुद्दा नहीं बना है। बावजूद इसके राज्य की 23.94 प्रतिशत आबादी भांग व शराब जैसे मादक पदार्थों की शिकार है। लत की वजह से सरकार के राजस्व इजाफे में करीब 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग देने वाले इन व्यक्तियों को दरकिनार यदि नशे की चपेट में फंसे बच्चों को भी शामिल कर लिया जाए, तो यह संख्या बढ़कर करीब 28 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। खास बात है कि नशे से नष्ट हो रहे बचपन को बचाने सरकार के पास न कोई आंकड़ा है और न ही इनकी लत छुड़ाने नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि ड्रग्स सेवन और अश्लीलता को बालीवुड के साथ समाज का एक वर्ग न केवल पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर प्रगतिशीलता, उदारवादिता और संपन्नता का प्रतीक मान रहा है, बल्कि आर्यन से सहानुभूति भी जता रहा है। क्या भारत में ड्रग्स लेना अपराधमुक्त और प्रतिष्ठा का परिचायक है?

वजह यह भी है कि बीते दो साल पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई मैग्रीट्यूड सब्सटेंस यूज इंडिया रिपोर्ट में भी नशे के शिकार बच्चों का अलग से शामिल नहीं किया गया है। मप्र में भी यही स्थिति है। नशे की गिरफ्त में फंसे बच्चों के इलाज व पुर्नवास के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। इन बच्चों के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं पर विश्वास किया जाए तो महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ ही सामाजिक न्याय विभाग इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं। यही वजह है कि करोड़ों रुपए दूसरे मदों में खर्च करने वाले यह विभाग अब तक इन बच्चों के लिए प्रदेश के किसी जिले में नशामुक्ति केंद्र तक नहीं बना पाए हैं। जबकि अकेले भोपाल में ही इन बच्चों के नशे से जुड़े करीब 60 से 70 मामले जिला बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आ जाते हैं।

मप्र सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने से भी नहीं हिचक रहा है। बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ 14 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट बच्चों में नशीले और मादक पदार्थों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर की कार्ययोजना बनाने के लिए कह चुका है। इसमें बच्चों की पहचान, नशा मुक्ति, परामर्श और पुनर्वास जैसे प्रावधान और इंतजाम के निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं स्कूलों में नशीली दवा और मादक पदार्थ के दुरुपयोग से जुड़े पाठ्यक्रम में शामिल करने को कहा था, लेकिन यह सिर्फ 8वीं व 11वीं में ही सिमट गए हैं। इसके अलावा देश के सभी जिलों में एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने के भी निर्देश दिए गए थे। वर्तमान में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नीमच, उज्जैन, सीहोर, रीवा, शाजापुर, श्योपुर, राजगढ़, सीधी एवं जबलपुर में नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 14 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं। नशे के शिकार लोगों को देखते हुए यह संख्या पर्याप्त नहीं है।

5 करोड़ 30 लाख मतदाताओं वाले इस प्रदेश में 23.94 प्रतिशत यानी 1 करोड़ 25 लाख शराब व भांग के नशे की चपेट में है। जबकि 2.55 प्रतिश यानी 13.35 लाख लोग नशे के दूसरे माध्यमों की चपेट में है। इसमें 6.51 लाख सिर्फ सार्वजनिक रूप से प्रबंधित अफीम के शिकार हैं। यही नहीं आजकल मप्र नशीले पदार्थों की तस्करी का प्रमुख केंद्र हो गया है। पिछले कुछ महिनों में सामने आए मामलों ने यह संकेत दिया है की मप्र में नशीले पदार्थों की खेप पूरे देश से पहुंच रही है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रियंक कानूनगो का कहना है कि हम इस मामले में नारकोटिक्स विभाग के साथ मिलकर विस्तृत योजना तैयार कर रहे हैं। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से देश के 272 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना भी शामिल है। इसमें मप्र के करीब 8 जिले शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वयस्कों की आबादी 5,22,20,675 है। इनमें से करीब 26.49 प्रतिशत यानी 1,38,39,492 लोग नशे के शिकार हैं। इन लोगों में से 23.94 प्रतिशत यानी 1,25,04,000 लोग शराब-भांग का सेवन करते हैं, जबकि 2.55 प्रतिशत यानी 13,35,492 लोग अन्य तरह के नशा यानी अफीम, इन्हेलर व ड्रग्स आदि का उपयोग करते हैं।

● **नवीन रघुवंशी**

सरकार के लिए फायदेमंद है नशेडी

सरकार के लिए नशेड़ी आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो रहे हैं। आंकलन इसी से किया जा सकता है कि बीते 5 सालों में सरकार का राजस्व दो गुना बढ़ गया है। 2016-17 में जहां सरकार शराब व भांग से जहां 5772 करोड़ रुपए कमा रही थी। वहीं मौजूदा समय में यह बढ़कर 10,711 करोड़ रुपए हो गया है। जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य कृपा शंकर चौबे कहते हैं कि नशे के शिकार बच्चों के साल में 60-70 मामले तो आ ही जाते हैं। भोपाल में हमने 2 केंद्र हायर किए हैं। जबकि इनके पुनर्वास के लिए राज्य के किसी दूसरे जिले में में कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। आवाज संस्था के निदेशक प्रशांत दुबे कहते हैं कि हमारी संस्था ने लॉकडॉउन के दौरान नशे के शिकार बच्चों का सर्वेक्षण किया था। पता चला बचपन नष्ट हो रहा है। दुख है यह गंभीर विषय हमारी सरकार के विभागों के लिए पॉलिसी मैटर नहीं है।

कोरोना संक्रमण काल में देशभर की अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे गिरी थी। नीचे गिरी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह के बूस्टर डोज दिए। इसके बावजूद देश के कई राज्यों की अर्थव्यवस्था आज भी चिंताजनक स्थिति में है। वहीं मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को कोविड दौर से उबारते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। इस कारण मप्र की अर्थव्यवस्था वी शेप में तेजी से आगे बढ़ रही है। जबकि उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (अब पूर्व), दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आदि आर्थिक मोर्चो पर कमजोर साबित हो रहे हैं।

आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हुआ मप्र

देश में पहली बार मुख्यमंत्रियों के सामने अपने राज्य को कोरोना संक्रमण से बचाने के साथ ही आर्थिक मोर्चे पर अपने प्रदेश को मजबूत करने की चुनौती है। इस चुनौती के बीच मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे सफल मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के साथ ही शिवराज ने प्रदेश को आर्थिक संकट से उभारने में सफलता पाई है। जबकि देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री उनसे काफी पीछे हैं। शायद वैकल्पिक नैरेटिव (कड़ी मेहनत, बुनियादी ढांचा, कल्याणकारी कदम, पहचान की राजनीति) बनाने के उनके कौशल ने काफी असर डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी नीति पर काम करते हैं।

दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण के दौरान ही भांप लिया था कि गिरती अर्थव्यवस्था को थामने और उसे ऊपर लाने के लिए अभी से रणनीति जरूरी है। इसलिए उन्होंने **संक्रमणकाल** के दौरान ही प्रदेश में निवेश लाने का प्रयास शुरू कर दिया था। यही नहीं मप्र के हिस्से का फंड लाने के लिए दिल्ली का दौरा भी तेज कर दिया था। मुख्यमंत्री स्वयं तो केंद्रीय मंत्रियों से मिले ही, साथ ही अपने मंत्रियों और अधिकारियों को भी दिल्ली भेजा और विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं के लिए मप्र के हिस्से का फंड मांगा। इसका परिणाम यह हुआ कि केंद्र से प्रदेश को बराबर फंड मिल रहा है। आज भले ही प्रदेश सरकार हर माह दो हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस साल अब तक प्रदेश सरकार ने पात्रता की तुलना में अब तक 75 फीसदी कर्ज कम लिया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि कोरोना संक्रमण काल में सरकार की आय गिरने के बाद भी प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। दरअसल बीते साल प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही राज्य सरकार को तत्काल ही नया कर्ज लेना पड़ा था, लेकिन अब हालात लगभग पूरी तरह से बदल चुके हैं।

वहीं दूसरी तरफ देश के कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं, जो लोकप्रिय तो खूब हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर कमजोर साबित हो रहे हैं। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (अब पूर्व), दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (अब पूर्व), छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदि आर्थिक मोर्चों पर कमजोर साबित हो रहे हैं। दरअसल, इन

वी शेप में बढ़ रही मप्र की अर्थव्यवस्था

कोविड दौर से उबरते हुए मप्र की अर्थव्यवस्था वी शेप में तेजी से आगे बढ़ रही है। अप्रैल से सितंबर माह में वैट और जीएसटी के तहत कुल राजस्व 22,014 करोड़ आ चुका है, जबकि बीते साल अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान यह केवल 14,744 करोड़ रुपए था यानी छह माह में ही 7,270 करोड़ रुपए अधिक मिल चुका है, जो बीते साल से 49 फीसदी अधिक है। सितंबर माह में कुल टैक्स 3,674 करोड़ रुपए मिला है, जबकि बीते साल सितंबर में 2503 करोड़ रुपए ही मिले थे। अप्रैल से सितंबर 2019 की बात करें तो इस दौरान 16,956 करोड़ का राजस्व मिला था। इसके बाद कोविड दौर में बीते साल अप्रैल से सितंबर 2020 में कम होकर 14,744 करोड़ रुपए हुआ और अब अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान यह बड़कर 22,014 करोड़ रुपए हो गया।

मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक मोर्चे पर अपनी सक्रियता कम दिखाई। वैसे राज्य दर राज्य मुख्यमंत्री तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक विमर्श में एक यह बात उल्लेखनीय है कि इसका अर्थशास्त्र से कोई खास लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक मोर्चे पर सबसे अधिक सक्रियता दिखाई।

वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को ही ले लीजिए, जिन्होंने अपमानित महसूस करने की वाजिब शिकायत के बाद में इस्तीफा दे दिया। लेकिन अगर जनता यह जानना चाहे कि क्या अमरिंदर ने राज्य में अगले कुछ ही महीनों में होने जा रहे चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व करने का अधिकार हासिल किया था, तो सबसे पहले उनकी सरकार के प्रदर्शन को आंकना होगा। और यहां तथ्य कुछ ऐसे हैं। प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में मार्च तक पिछले चार सालों में पंजाब के हर नागरिक ने राज्य के उत्पादन में अपने हिस्से में औसतन 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। यह सालाना एक फीसदी से भी कम वृद्धि है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि निश्चित तौर पर आंकड़ों पर महामारी का असर पड़ा है, और समग्र रूप से भारत ने भी कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन कई राज्यों ने ऐसा कर दिखाया है। पश्चिम बंगाल (जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने फिर जीत हासिल की है) में 19.1 फीसदी की दर से सुधार दर्ज किया गया है। अब जरा इसकी तुलना उप्र से कीजिए, जहां योगी आदित्यनाथ आए दिन अपनी सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियां गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री राज्य को उत्तम प्रदेश बताने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी योगी के चार सालों के कार्यकाल के दौरान उप्र में प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद में कुल मिलाकर 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब बात शौचालयों की संख्या अथवा यहां बने एक्सप्रेसवे की आती है तो शायद एक अलग ही तस्वीर उभरती है।

विडंबना यह है कि, उप्र के स्थिर आर्थिक उत्पादन के बावजूद अगले साल राज्य चुनावों के बाद मजबूत योगी के फिर सत्ता में लौटने की उम्मीद है, जिस तरह पंजाब में कांग्रेस को चुनाव

के लिहाज से अच्छी स्थिति में देखा जा रहा था। यह हाल तब था जबकि अमरिंदर सिंह को सिखों की पवित्र धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी से जुड़े मामलों में निष्क्रियता के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। उनके सामने बड़े पैमाने पर बिजली की कमी का संकट भी था, जिसके कारण उद्योग-धंधे बंद तक हो गए थे। लेकिन बस एक झटके के आगे यह सब बेअसर हो गया, जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधार के मुद्दे पर भाजपा और अकाली के रास्ते अलग हो गए। तो क्या कमजोर प्रदर्शन कोई मायने रखता है? ऐसा तो तब होता है जब आप चुनाव नतीजों से परे कुछ देखना चाहते, और यह जानना चाहते कि देश के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा है। दक्षिण के पांच बड़े राज्यों में से तेलंगाना ने अपने प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद में चार वर्षों के दौरान 26.2 प्रतिशत की भारी-भरकम वृद्धि हासिल की, जबकि तमिलनाडु में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तीन अन्य दक्षिणी राज्यों का औसत करीब 15 फीसदी रहा। ये दो बड़े पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत अलग नहीं रहे, जहां तीन साल में हुई वृद्धि क्रमश: 14.1 प्रतिशत और 26.7 प्रतिशत रही है। दोनों राज्यों (साथ में केरल भी) के पास केवल मार्च 2020 तक के आंकड़े हैं; कोविड से प्रभावित 2020-21 के आंकड़े उपलब्ध होने पर यह आंकड़ा घट जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे गरीब पूर्वी राज्यों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। 19.1 फीसदी के साथ पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार ने 21.8 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की और ओडिशा में यह आंकड़ा 16.7 प्रतिशत रहा है। इस लिहाज से आगे बढ़ने में मध्य क्षेत्र के राज्य ही विफल रहे हैं, जैसे राजस्थान चार वर्षों में 1.3 प्रतिशत प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि ही हासिल कर पाया। इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत के आसपास सिमटा हुआ है।

मप्र सरकार पर बीते कुछ सालों में तेजी से कर्ज बड़ा है। इसकी वजह से हालत यह हो गई है कि प्रदेश सरकार पर अब तक 2 करोड़ 53 लाख 335 करोड़ से अधिक कर्ज हो चुका है। इसमें एक लाख 54 हजार करोड़ का कर्ज खुले बाजार का है। शेष कर्ज में सरकार को पावर बांड सहित अन्य बांड का कंपनसेशन का 7360 करोड़, वित्तीय संस्थाओं की देनदारी 10,901 करोड़, केंद्र सरकार के ऋण एवं अग्रिम के 31 हजार 40 करोड़ सहित अन्य दायित्व 20 हजार 220 करोड़ रुपए शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 52 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

मप्र के खजाने की हालत सुधरी

कोरोना संक्रमणकाल में देश के अन्य राज्यों की तरह मप्र की अर्थव्यवस्था भी नीचे चली गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के लिए खजाना खोल दिया था। लोगों के इलाज के साथ ही भोजन की व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए। चुनौतीपूर्ण समय में भी मप्र सरकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रम जारी रहे। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना, श्रम सिद्धि अभियान, रोजगार के प्रयास, विशेष पिछड़ी जनजातियों और वनवासियों को सहायता, विद्यार्थियों को सहायता, प्रधानमंत्री स्वनिधि पथ विक्रेता योजना, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, पात्र परिवारों को नि:शुल्क राशन, जल जीवन मिशन आदि जारी रखे गए। इस कारण प्रदेश को न चाहते हुए भी लगातार कर्ज लेना पड़ा। लेकिन इस दौरान सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास निरंतर जारी रहे। इस दौरान प्रदेश में उद्योगों में निवेश संवर्द्धन के लिए निरंतर प्रयास चलते रहे, जिसके कारण इन्वेस्ट इंडिया के सर्वे में मप्र को 97 प्रतिशत अंक मिले।

कोरोना संक्रमण काल में श्रमिकों के लिए संजीवनी बनी मनरेगा में अब लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश को मनरेगा का पर्याप्त बजट नहीं मिल पाया है। इस कारण 10 लाख से अधिक कार्य रुके पड़े हैं। जिसके चलते मनरेगा में पंजीकृत 1.19 करोड़ श्रमिकों में से मात्र 11.65 लाख को ही प्रतिदिन रोजगार मिल पा रहा है।

जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश में जिन लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला है उनमें से लाखों की मजदूरी का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही ठेकेदारों को भी उनके काम का पैसा नहीं मिला है। इस कारण जहां काम रुके पड़े हैं, वहीं श्रमिकों का शहरों की ओर पलायन शुरू हो गया है। मंदसौर के ग्राम ढाबला माधौ सिंह के कन्हैयालाल भील मजदूरी के लिए दूसरों के खेत में काम कर रहे हैं। उन्हें गांव में मनरेगा के अंतर्गत काम नहीं मिल रहा है। वहीं मजदूरी कम होने से गांव के लोग जयपुर सहित अन्य बड़े शहरों में जाने लगे हैं। यही हाल धार जिले के कुक्षी अंतर्गत ग्राम ढोलिया में हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड, ग्वालियर-चंबल और विंध्य क्षेत्र में भी काम का संकट बन गया है।

मप्र मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में अन्य राज्यों से आगे रहता है। लेकिन वर्तमान में मनरेगा का बजट गड़बड़ाने से प्रदेश को पर्याप्त फंड नहीं मिल पाया है। इस कारण वर्तमान में 10 लाख से अधिक काम रुके हैं। इसके पीछे ठेकेदारों का बकाया भुगतान नहीं होना और मजदूरों की मजदूरी समय पर नहीं मिलना प्रमुख कारण सामने आए हैं। प्रदेश में दो साल के भीतर 989 करोड़ से अधिक का भुगतान अटका है। इसमें मजदूरी का 64 करोड़ रुपए है। इसका असर रोजगार पर भी पड़ा है। प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत 1.19 करोड़ से अधिक क्रियाशील मजदूर हैं। इनमें 8 अक्टूबर की स्थिति में 11.65 लाख श्रमिकों को ही रोज काम मिल रहा है। कोरोना की पहली लहर में अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के **वापस आने पर एक दिन** में 22 लाख से अधिक तक मजदूरों को रोजगार दिया गया था।

मनरेगा का पर्याप्त बजट नहीं मिलने का असर यह हुआ है कि वर्ष 2021-22 में 12.12 लाख कार्य खोले गए इनमें से इस माह 1,12,990 कार्यों में ही मस्टर रोल जारी किए गए हैं। वहीं पिछले साल 71,85,242 मजदूरों को काम मिला जबकि इस साल 75,58,689 को। मनरेगा आयुक्त सूफिया फारूकी का कहना है कि इस साल लंबे समय तक बारिश हुई। इससे कहीं-कहीं काम प्रभावित हुए। वैसे पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा काम खोले गए। पिछले साल की औसत मजदूरी 179 रुपए से बढ़कर इस साल 186.46 रुपए यानि 6 रुपए अधिक हो गई। इस समय धान का उपार्जन होने से मजदूरों की संख्या में कमी देखी जा रही है। काम को गति देने का प्रयास जारी हैं।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के दौर में मजदूरों के लिए मनरेगा योजना बेहद लाभकारी साबित हुई है। मप्र में 20 लाख मजदूरों को हर रोज काम मिला। प्रदेश में कोरोनाकाल के दौरान 59 फीसदी मजदूरों को रोजगार दिया गया। इस मामले में मप्र केंद्र की रैंकिंग में टॉप पर था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक प्रदेश के 22 हजार 162 ग्राम पंचायतों के मजदूरों को जोड़ने के लिए 12 लाख 18 हजार 864 काम शुरू कराए गए। कोरोना संक्रमणकाल में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस लौटे। ऐसे तमाम मजदूरों को गांव में ही रोजगार देने के लिए मनरेगा बड़ा सहारा बनी। बड़ी संख्या में मनरेगा के तहत काम शुरू कराए गए। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा का लाभ देने के लिए व्यापक स्तर पर रोजगार कार्ड वितरण अभियान भी चलाया गया। हालांकि कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ ही मनरेगा के कामों में भी कमी आई है। इसलिए मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है।

● **राकेश ग्रोवर**

कोरोना संक्रमणकाल के दौरान मनरेगा प्रवासी श्रमिकों के लिए सबसे बड़ा संबल बना था। दूसरे प्रदेशों और शहरों से पलायन करके मप्र पहुंचे श्रमिकों को सरकार ने तत्काल मनरेगा में रोजगार मुहैया कराया था, लेकिन अब फंड के अभाव में काम बंद हो गए हैं। इसका असर यह हुआ है कि गांव छोड़कर बाहर न जाने की कसम खाने वाले मजदूर अब एक बार फिर से पलायन को मजबूर हो रहे हैं।

मजदूर पलायन को मजबूर

मप्र में मजदूरों के पलायन की वजह

प्रदेश में बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं। इसकी वजह है काम का अभाव और कम मजदूरी। वर्तमान में मजदूरों के पलायन की कई वजहें हैं। पीएम आवास योजना में काम नहीं चलने से हितग्राहियों की संख्या घटी है। आवास निर्माण में 90 दिन काम करने पर रोज 193 रुपए से कम मिलते हैं। जबकि ओडिशा में 220 रुपए रोज। अधिक मजदूरी देने के लिए ठेकेदारी प्रथा है। इसलिए लोग मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। निर्माण मटेरियल महंगा होने और भुगतान बकाया होने से ठेकेदार हाथ खींच रहे हैं। गांवों में सरपंच और सचिवों की मनमानी से काम नहीं मिल रहा। मजदूरी दर प्रदेश में 193 रुपए है लेकिन वास्तव में 185 रुपए मिलते हैं। एक मजदूर परिवार को 100 दिन काम देने पर सालभर में महज 18,500 रुपए मिलते हैं। इसलिए मजदूर पलायन का मजबूर हो रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मप्र में मनरेगा की मजदूरी कई राज्यों से अधिक है।

अफसरों की गलती...भुगत रहे किसान

मप्र के आंकड़ेबाज अफसरों ने सरकार से अपनी पीठ थपथपवाने के लिए बिना जांच-पड़ताल के ऐसे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ दिया जो पात्र थे ही नहीं। मप्र के ऐसे 2.51 लाख अपात्र किसान के खातों में 19.57 करोड़ रुपए डाल दिए गए। फिर जांच-पड़ताल की गई और इन किसानों को गुनहगार मान लिया गया। अब सरकार इन किसानों पर रकम वापस करने का दबाव बना रही है। हैरानी की बात यह है कि इन किसानों में से 80 हजार ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई तो प्रदेश सहित देशभर के किसानों को इस योजना से जुड़ने को कहा गया। उस दौरान अफसरों ने किसानों को नियमों की जानकारी नहीं दी। जिन किसानों ने आवेदन किया उन्हें योजना से जोड़ दिया गया। मप्र में 2 लाख 51 हजार 391 ऐसे किसान हैं, जिनके खातों में योजना के तहत 19 करोड़ 57 लाख 38 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए गए। पैसा आते ही लोगों ने इन्हें खातों से निकाल लिया। बड़ी बात ये है कि इन लाभार्थियों में कई लोग इनकम टैक्स देते हैं तो कहीं एक ही परिवार के कई लोगों के खातों में पैसे आए हैं। 80 हजार से ज्यादा ऐसे किसान मिले हैं, जिनकी मौत हो गई है। भोपाल में ये संख्या 2570 है। फिलहाल इन सभी से जिला प्रशासन ने वसूली शुरू कर दी है।

दरअसल, यह योजना 2018 में लागू हुई थी। तब अफसरों ने जिन किसानों की जानकारी शासन को दी थी, उसके हिसाब से उनके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। बाद में जब समग्र और आधार कार्ड के डाटा से इसका मिलान हुआ तो गड़बड़ी सामने आई। कुछ महीने पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी कि देशभर में 42 लाख 16 हजार 643 किसान जो पात्र नहीं थे, उनके खाते में 29 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हुई है।

मप्र में तो कई किसान ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं की उनके खाते में रकम कैसे आई है। जब किसानों को नोटिस मिला जब जानकारी सामने आई। टीलाखेड़ी के शंकरलाल वर्मा सरकारी शिक्षक हैं। दो महीने पहले उनके खाते में पीएम सम्मान निधि के 10 हजार पहुंचे थे। जब उनके पास बैंक का नोटिस लेकर पटवारी पहुंचा तो उन्होंने ये राशि लौटा दी। उनको पता ही नहीं है कि खाते में ये रुपए कैसे और कब आ गए। ओमप्रकाश त्यागी फंदा के शाहिस्ताखेड़ी में रहते हैं। वे सरकारी शिक्षक हैं। उनके नाम पर 8 एकड़ जमीन हैं। आयकर की श्रेणी में आते हैं। पीएम सम्मान निधि के 10 हजार रुपए उनके पास आए थे। तहसील से नोटिस मिला। इसके बाद उन्होंने तहसील में राशि जमा कराई। भगवत प्रसाद तूमड़ा निवासी को 8 हजार रुपए सम्मान निधि की राशि चार बार में मिली थी। चूंकि वो इनकम टैक्स देते हैं। इसलिए उन्होंने ये राशि लौटा दी। प्रसाद का तर्क है कि गलती से राशि उनके खाते में पहुंच गई थी, तहसील से सूचना मिलने के बाद लौटा दी है।

भोपाल जिले में 63 हजार 430 पात्र किसानों को 73 करोड़ 98 लाख 64 हजार रुपए का भुगतान 2018 से अब तक किया जा चुका है। भोपाल में कुल रजिस्टर्ड किसानों की संख्या 1 लाख 26 हजार है। इसमें से सिर्फ 2570 किसानों से सम्मान निधि की गाइडलाइन के दायरे में नहीं आने के कारण राशि वसूली जाएगी। आयुक्त भू-अभिलेख ज्ञानेश्वर पाटिल कहते हैं कि जिलों में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि हर व्यक्ति को बुलाकर सुनवाई करें। जांच में कई मामले ऐसे भी मिले हैं, जो किसान पहले आयकर की श्रेणी में नहीं आते थे, लेकिन बाद में उनकी जमीन किसी प्रोजेक्ट में चली गई। उनको मुआवजा मिल गया। इसलिए उस समय यदि उसने निधि ली होगी तो वो अपात्र नहीं होगा। एक परिवार में एक व्यक्ति को लाभ देने की योजना है।

● धर्मेंद्र कथूरिया

तीन गुना महंगा बीज खरीदकर दिया जाएगा किसानों को

सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने पर जोर दे रही है। लेकिन उद्यानिकी विभाग के अफसर सरकार की नीतियों को दरकिनार कर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ताजा मामला एससी-एसटी वर्गों को बांटे जाने वाले बीज का है। जानकारी के अनुसार उद्यानिकी विभाग निविदा में नाकाम रही कंपनी नाफेड से दो-तीन गुना महंगा बीज खरीदकर दलितों-और आदिवासियों में बांटने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, उद्यानिकी विभाग ने जिलों को बीज आदेश जारी कर किया है। इस आदेश के अनुसार जिस कंपनी नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित) के बीजों की दर जिलों को भेजी गई, वह बीज कंपनी पूर्व में एमपी एग्रो की दर निविदा में तकनीकी अर्हता पूरी नहीं कर सकी है। फिर भी एससी-एसटी वर्गों को बांटे जाने वाले बीज एमपी एग्रो के बजाय नाफेड से दो से तीन गुना ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ेंगे। गौरतलब है कि विशेष केंद्रीय सहायता से एससी-एसटी वर्ग के लिए वर्ष 2019-20 में योजना की स्वीकृति इस वर्ष मिली। अब उद्यानिकी संचालनालय द्वारा अपने ही विभाग की संस्था एमपी एग्रो को दरकिनार करके तीन गुना अधिक कीमत पर केंद्रीय संस्थान नाफेड से खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संचालनालय की ओर से जिलों को नाफेड, एनएससी या एमपी एग्रो से बीज लेने के आदेश के साथ सिर्फ नाफेड के हाइब्रिड सब्जी बीजों की दर सूची भेजी गई है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन एसीएस इकबाल सिंह बैंस ने मप्र के लिए अनुकूल बीज ट्रायल के बाद एमपी एग्रो से ही बीज खरीदी के लिए निर्देश दिए थे।

जबलपुर और इटारसी के बाद इंदौर में भारतीय सेना के लिए हथियार बनेंगे। गौरतलब है कि जबलपुर में बनने वाली तोपें भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती हैं। अब प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में भारतीय सेना में शामिल अर्जुन टैंक और एंटी-ड्रोन सिस्टम के कम्पोनेंट पार्ट्स सहित कई अन्य एसेम्बलिंग पार्ट्स बनाए जा रहे हैं।

सेना के हथियार इंदौर में बनेंगे

दुश्मन देशों के छक्के छुड़ाने व होश उड़ाने वाले भारतीय सेना में शामिल अर्जुन टैंक और एंटी-ड्रोन सिस्टम के कम्पोनेंट पार्ट्स सहित कई अन्य एसेम्बलिंग पार्ट्स इंदौर में बनाए जा रहे हैं। इंदौर की कंपनी ने मेक इन इंडिया अभियान की तर्ज पर यह मेक इन इंदौर, मिशन पोकरण में परमाणु बम विस्फोट परीक्षण के बाद शुरू किया था, जो लगभग 22 सालों से आज तक जारी है।

इंडियन आर्मी, एयरफोर्स सहित नेवी में शामिल एंटी-ड्रोन सिस्टम जैसे आधुनिक हथियारों के वास्ते हाईटेक्निक कम्पोनेंट्स पार्ट्स बनाने की यह जिम्मेदारी बिना किसी पब्लिसिटी के शहर की लाइट गाइड ऑप्टिक्स कंपनी और उसके टैलेंटेड इंजीनियर बड़ी खामोशी से निभाते आ रहे हैं। इंदौर में यह सीक्रेट प्रोजेक्ट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन की निगरानी में वर्ष 1999 से चल रहा है।

एंटी-ड्रोन सिस्टम दुश्मन देश के एयर ड्रोन का न सिर्फ तत्काल पता लगा सकता है, बल्कि उसे जाम कर लेजर तकनीक के जरिए खत्म कर देता है। देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए इस सिस्टम को आर्मी, वायुसेना और नौसेना, यानी नेवी में शामिल कर लिया गया है। यह पहला स्वदेशी एंटी-ड्रोन सिस्टम है। यह एंटी-ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री की सभाओं से लेकर देश की सभी सीमाओं पर काम कर रहा है। यह एंटी-ड्रोन सिस्टम डीआरडीओ की देखरेख में स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है।

कैट के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट पर काम चल ही रहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, रक्षामंत्री जार्ज फर्नांडीस की तिकड़ी ने 11 मई 1998 को पोकरण में परमाणु बम विस्फोट परीक्षण कर अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस सहित सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। इससे दुनिया की सारी परमाणु महाशक्तियां बौखला गईं और भारत पर आर्थिक प्रतिबंध सहित कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके चलते हथियारों की कमी हुई और फिर देश में हथियार बनने लगे।

लाइट गाइड ऑप्टिक्स कंपनी के अनुसार हम आर्मी टैंक व एंटी-ड्रोन सिस्टम को अत्याधुनिक बनाने के लिए माइक्रो, स्माल, मीडियम कम्पोनेट पार्ट्स बनाने के लिए लास्टेक, यानी लेजर एंड साइंस टेक्नोलॉजी, मेटल मिरर मेकिंग टेक्नोलॉजी सहित इजराइल के आयरन डोम से मिलती-जुलती स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।

पोलोग्राउंड स्थित लाइट गाइड ऑप्टिक्स कंपनी ने चुनौती और जोखिम भरे कामों की शुरुआत राजा रमन्ना एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर से लेजर एंड साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित प्रोजेक्ट से की थी। इसी दौरान कैट के अधिकारियों के माध्यम से डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय की स्पेशल विंग के साथ काम शुरू किया।

हाल ही में 1 अक्टूबर को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के डॉ. जी सतीश रेड्डी ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों से आह्वान किया था कि वह मेक इंडिया अभियान के तहत रक्षा विभाग से जुड़ी सामग्री व उपकरण बनाने के लिए आगे आएं। इस अभियान से जुड़ने पर न सिर्फ आपके उद्योगों का विकास होगा, बल्कि हमारा देश इस मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। इसी दौरान लाइट गाइड ऑप्टिक्स कंपनी के एमडी सिद्धार्थ धावले भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया अभियान तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में इंदौर में लगभग 22 साल पहले शुरू हो चुका है। वह तभी से हथियारों के कम्पोनेंट्स पार्ट्स बनाते आ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि मप्र में तेजी से औद्योगिक विस्तार हो रहा है। प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार का भी फोकस मप्र पर है। केंद्र सरकार मप्र में सैन्य सामग्री बनाने के लिए कई प्रयोग करने जा रही है। पूर्व में अनिल अंबानी ने मप्र में सैन्य हथियार बनाने के लिए जमीन मांगी थी। मप्र सरकार ने इस दिशा में कदम भी बढ़ाया था, लेकिन बाद में अनिल अंबानी ने अपने हाथ खींच लिए। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार मप्र के ग्वालियर-चंबल अंचल और इंदौर संभाग में नई संभावना तलाश रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में सैन्य सामग्री बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है।

● विकास दुबे

स्वदेशी तकनीक से अमेरिका, रूस हैरान

भारत के मित्र राष्ट्र रूस ने भी देश को कई टेक्निकल पार्ट व कम्पोनेंट देना बंद कर दिए। इस वजह से कई रक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अटकने लगे। तब अटल सरकार ने मेक इन इंडिया मिशन शुरू किया। तब डीआरडीओ के सहयोग से वर्ष 1999 से स्वदेशी तकनीक पर काम शुरू किया, जिसके सुखद परिणाम सामने आने लगे। अंततः परमाणु बम विस्फोट परीक्षण के बाद लगाए गए प्रतिबंध भारत राष्ट्र सहित स्वदेशी तकनीक अपनाकर आत्मनिर्भर बनने वाली हमारी जैसी कंपनियों के लिए वरदान साबित हुए। इससे हम पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका, रूस सहित सारी दुनिया हैरान रह गई।

कब्जाधारी को स्थायी पट्टा

प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। कब्जाधारियों को सरकार 30 साल के लिए पट्टा देगी। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं, जिसके अनुसार यह सुविधा दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में भू-माफिया के खिलाफ सरकार सख्ती से कार्य कर रही है।

शासन के निर्देश पर सरकारी यानी नजूल जमीनों पर जो कब्जे या निर्माण हैं उन्हें 30 साल का स्थायी पट्टा दिया जाएगा। शर्त यह है कि 31 दिसंबर 2014 से सरकारी जमीन पर निरंतर कब्जा होना चाहिए। यानी 25 साल से अगर कब्जा है तो स्थायी पट्टे की पात्रता रहेगी। जिला प्रशासन को अभी तक जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उन पर दावे-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शासन नियमों के मुताबिक स्थायी पट्टा देते वक्त आवासीय और व्यवसायिक प्रीमियम दरों की तय की गई राशि जमा करवाई जाएगी और उसी के मान से सालाना भू-भाटक भी 2018 के नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा।

पिछले दिनों राज्य शासन ने अर्बन सीलिंग और सरकारी जमीन पर मकान, दुकान बनाने वालों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया, जिनके कब्जे का रिकार्ड 1989 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक का है। यानी 25 साल तक अगर सरकारी जमीन पर निरंतर कब्जा और निर्माण है तो ऐसे धारकों को ही 30 साल के स्थायी पट्टे की पात्रता होगी। इस संबंध में तहसीलों में आने वाले आवेदनों की सार्वजनिक उद्घोषणा की जा रही है, जो कि राजस्व के साथ-साथ कलेक्टर की अधिकृत वेबसाइट पर भी होगी और प्रमुख समाचार-पत्रों में भी इसका प्रकाशन किया जाएगा, ताकि दावे-आपत्तियां ली जा सके।

शासन ने तय किया है कि आवासीय जमीन पर अगर 1500 स्क्वेयर फीट में कब्जा है तो कलेक्टर गाइडलाइन की 5 प्रतिशत राशि प्रीमियम के रूप में जमा करना होगी। अगर दो हजार स्क्वेयर फीट तक निर्माण है तो 10 प्रतिशत प्रीमियम की राशि और दो हजार स्क्वेयर फीट से अधिक होने पर 100 फीसदी कलेक्टर गाइडलाइन के मान से प्रीमियम राशि जमा करना होगी। इसी तरह अगर **व्यवसायिक निर्माण** है तो 200 स्क्वेयर फीट तक के भूखंड पर वर्तमान बाजार मूल्य की 25 प्रतिशत राशि और अगर उससे अधिक क्षेत्रफल है तो 50 प्रतिशत और एक हजार स्क्वेयर फीट से अधिक क्षेत्रफल में 100 प्रतिशत बाजार मूल्य की राशि ली जाएगी और भू-राजस्व संहिता की धारा के तहत जो वार्षिक भू-भाटक बनेगा वह हर साल स्थायी पट्टेदार को जमा करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2014 की स्थिति में सरकारी जमीन के अधिभोगियों के आधिपत्य के भूखंडों को पृथक-पृथक दर्शाते हुए नक्शा तैयार किया जाएगा और इसके लिए 31 दिसंबर 2014 के सैटेलाइट नक्शे की सहायता ली जाएगी। आवेदन के बाद जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर और जो 30 दिन की समय सीमा दावे-आपत्तियों की है उसकी जांच-पड़ताल के बाद अधिभोगियों को 30 साल का स्थायी पट्टा व आधिपत्य के प्रमाण के रूप में आवेदन के साथ लिए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक

शहरी क्षेत्र में जहां धारणा अधिकार के तहत स्थायी पट्टे देकर मालिकाना हक दिया जा रहा है, तो इसी तरह का अभियान ग्रामीण आबादी का सर्वे कर स्वामित्व योजना के तहत अधिकार दिए जाएंगे। अभी 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में इस अभियान की शुरुआत की और मप्र के भी कुछ जिलों में ये स्वामित्व योजना के मालिकाना हक ग्रामीणों को दिए गए पिछले दिनों प्रमुख राजस्व आयुक्त डॉ. संजय गोयल और आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त बी. ज्ञानेश्वर पाटिल ने सभी जिलों के अपर कलेक्टरों से चर्चा की थी और उन्हें निर्देश दिए कि सभी जिलों में स्वामित्व योजना का निराकरण करें।

भू-स्वामी प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इसके आधार पर वह बैंक लोन लेने से लेकर भविष्य में जमीन का क्रय-विक्रय भी कर सकेगा। बिजली बिल, जल प्रदाय बिल या अन्य

शासन के राजस्व विभाग ने 24 सितंबर 2020 को परिपत्र इस संबंध में जारी किया उसमें सार्वजनिक प्रयोजन की जमीनों पर काबिज लोगों को ये स्थायी पट्टे नहीं मिलेंगे। ग्रीन बेल्ट, बगीचे, खेल के मैदान, सड़क, गली, नदी-नाले या जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में चिन्हित जमीनों के अलावा धार्मिक स्थल की जमीन, राजस्व, वन भूमि या संहिता की धारा 233 क के अधीन आरक्षित जमीनों पर ये पट्टे नहीं दिए जा सकेंगे। अगर किसी जमीन का विवाद न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चल रहा है तो भी उसका निराकरण अभी नहीं किया जाएगा और इस नीति का लाभ एक परिवार एक ही बार में उठा सकेगा। विवाद के मामले में कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

कई जमीनें ऐसी हैं जो पहले निजी थी और बाद में फिर सरकारी घोषित कर दी गई। लिहाजा ऐसे प्रकरणों में भी अभी इस धारणा अधिकार नीति के तहत जो आवेदन प्राप्त होंगे उसका निर्णय स्थानीय स्तर पर प्रशासन नहीं करेगा, बल्कि ऐसे प्रकरणों को शासन के पास यानी भोपाल भेजा जाएगा। शासन जांच-पड़ताल के बाद अधिसूचित करते हुए पट्टे देने की पात्रता या अपात्रता निर्धारित करेगा। उसके आधार पर प्रशासन अंतिम निर्णय लेगा। यानी पहले निजी और फिर सरकारी हो चुकी जमीनों के संबंध में स्थानीय स्तर पर फिलहाल निर्णय नहीं लिया जाएगा। आबादी के अधिभोगियों के प्रकरणों में स्वत्व अधिभोग की जांच अत्यंत बारीकी से करने के निर्देश इसीलिए शासन ने दिए हैं।

● श्याम सिंह सिकरवार

न सब्सिडी मिली, न फंड खर्च हुआ

मप्र में सरकार उद्यानिकी फसलों का बढ़ावा देने के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों के लिए उद्यानिकी फसलों की खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। दरअसल उद्यानिकी विभाग के अधिकारी न तो किसानों की सब्सिडी दे पा रहे हैं और न ही फंड खर्च कर पा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में आम, संतरा, अमरुद, आंवला, पपीता, केला, अनार, धनिया, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन सहित फूलों की खेती जैसे कट फ्लॉवर, बल्बस तथा लूज फ्लॉवर का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। इन फसलों की खेती करने वाले करीब 5000 किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी देने का टारगेट तय किया गया था, लेकिन फायदा 400 को भी नहीं हुआ है। गौरतलब है कि प्रदेश में खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। सरकार प्रतिवर्ष 21 हजार करोड़ रुपए की बिजली पर सब्सिडी देती है। इसमें 16 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को दी जाती है। फसल बीमा के प्रीमियम के तौर पर सरकार दोनों फसल सीजन को मिलाकर एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा अंशदान देती है तो शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिलाने के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष सहकारी बैंकों को दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में किसानों की स्थिति चिंताजनक है।

सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पांच साल पहले निर्धारित किया था, लेकिन आज तक न तो फसलों का उत्पाद बढ़ा और न ही आय बढ़ी। इसके पीछे उद्यानिकी विभाग के अफसरों की लापरवाही सबसे बड़ी वजह बनी है। विदिशा निवासी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने 11 एकड़ में मसाला उत्पादन से जुड़ी फसलें लगाई थीं। सरकारी सहायता यानि सब्सिडी लेने के लिए आवेदन भी किया, लेकिन फसल का उत्पादन बढ़ा न **आय में दोगुनी वृद्धि** हुई। सरकार से सब्सिडी भी नहीं मिली। किसान अनूप सिंह ने बताया कि उन्हें उद्यानिकी से संबंधित किसी योजना की जानकारी ही नहीं है। यह हाल अकेले किसान विनोद और अनूप के साथ नहीं है बल्कि प्रदेश के हजारों किसान पांच साल में अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाए और न ही आय में बढ़ोत्तरी हुई, जबकि बढ़ती महंगाई से उनकी कमर और टूट रही है।

एकीकृत बागवानी विकास के तहत योजना के लिए 40 जिलों में विशेष फोकस किया जाना था। विभाग के अनुसार भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगौन, खंडवा, मंडला, डिंडौरी, बुरहानुपर, बड़वानी, रीवा, सतना, हरदा, राजगढ़, गुना, नीमच, ग्वालियर, छतरपुर, सीहोर, विदिशा, सीधी, अलीराजपुर, सिंगरौली, अशोकनगर, रायसेन, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया तथा आगर-मालवा में किसानों को प्रशिक्षण देकर इन फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाना था। लेकिन न तो किसानों का प्रशिक्षण मिला और न ही उन्हें योजना के बारे में जानकारी है। किसानों का कहना है कि उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास के तहत फसलों का उत्पादन बढ़ाने और सब्सिडी दिए जाने की हमें कोई जानकारी नहीं है।

एक तरफ किसान सब्सिडी की आस लगाए बैठे हैं वहीं दूसरी तरफ उद्यानिकी विभाग के भी आंकड़े बताते हैं कि मेन में एकीकृत बागवानी विकास को लेकर केंद्र से मिलने वाले फंड का उपयोग उद्यानिकी विभाग नहीं कर पा रहा है। इसके तहत प्रदेश में आम, संतरा, अमरुद, आंवला, पपीता, केला, अनार, धनिया, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन सहित पुष्प की खेती जैसे कट फ्लॉवर, बल्बस तथा लूज फ्लॉवर का उत्पादन दोगुना किया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार से 60 फीसदी और राज्य से 40 फीसदी अंश राशि खर्च की जाती है। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बीते 5 सालों में 337 करोड़ रुपए का आवंटन मप्र को मिला था, लेकिन इसमें से उद्यानिकी विभाग सिर्फ 169 करोड़ रुपए ही खर्च कर सका है। यदि टारगेट के हिसाब से किसानों को लाभ दिया जाता तो हर साल 4 से 5 हजार किसानों को फायदा मिलता।

● सिद्धार्थ पांडे

गांवों में तैनात होंगे 26 हजार कृषक मित्र

प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने, उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार 26 हजार कृषक मित्र तैनात करेगी। 25 साल से अधिक आयु के स्थानीय ग्रामीणों को इसमें मौका दिया जाएगा। इन्हें एक हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय भी मिलेगा। इनका मुख्य कार्य योजनाओं की निगरानी करने के साथ किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का होगा। शिवराज सरकार ने तय किया है कि कृषक मित्रों के माध्यम से किसानों तक उनके हित में संचालित सभी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाएगी। कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी उन्हें प्रत्येक योजना की जानकारी देंगे, जो उनके मोबाइल में रहेगी। वे किसानों के बीच जाएंगे और उन्हें योजनाओं के बारे में बताएंगे। यदि उन्हें किसी योजना का लाभ मिला है तो उसका सत्यापन भी करेंगे। इसी तरह फसल बीमा, बीज ग्राम, फसल चक्र परिवर्तन, बीज अनुदान योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। इस दौरान वे किसानों को यह भी बताएंगे कि सरकार कृषि की लागत घटाने के लिए उन्हें बिजली, खाद-बीज सहित अन्य माध्यमों से कितनी वित्तीय सहायता अनुदान के तौर पर उपलब्ध करा रही है।

किस साल कितना फंड हुआ खर्च

वर्ष	आवंटन	खर्च करोड़ में
2016-17	75.59	26.07
2017-18	50.50	48.01
2018-19	56.52	53.21
2019-20	64.16	35.42
2020-21	91.08	13.47

स्त्रोत उद्यानिकी विभाग, मार्च 2021

नर्मदा कोरीडोर को हरी झंडी

नर्मदा सौंदर्य को निखारने और लोगों की आस्था को मजबूत करने वाला नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर का काम जल्द शुरू होगा। नर्मदा नदी के तिलवारा घाट से भिटौली तक लगभग 8.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को बनाने के लिए भोपाल से स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद जबलपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) से इस महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले इस काम की जिम्मेदारी जबलपुर नगर निगम के पास थी, लेकिन फिर इसे बनाने का जिम्मा जबलपुर विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया। जेडीए ने नर्मदा किनारे बनने वाले इस कोरिडोर का प्रस्ताव और डिजाइन स्वीकृति के लिए भोपाल भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। अब जेडीए इसका फील्ड सर्वे करेगा।

जेडीए के मुताबिक इस कॉरिडोर की स्वीकृति मिलने के बाद इसका फील्ड सर्वे होना है। इसकी जिम्मेदारी देख रहे अरूण खर्द ने बताया कि जिस जगह पर इसे बनाया जाना है, वहां की मौजूदा स्थिति क्या है। कहां पर सड़क बनाने के लिए जगह है और कहां नहीं। किस और कितने क्षेत्र में अतिक्रमण है। इन सभी बातों का अध्ययन फील्ड सर्वे के दौरान किया जाएगा। हालांकि पहले इस कॉरिडोर में बनने वाली सड़क की चौड़ाई 60 मीटर थी, लेकिन अब इसे 30 मीटर कर दिया गया है। इस वजह से सर्वे का काम जल्द हो जाएगा।

इस कॉरिडोर को नर्मदा से 300 मीटर दूरी पर बनाया जाएगा। जानकार बताते हैं कि इसकी डिजाइन को बहुत कुछ अहमदाबाद के साबरमती रिव्यू की तरह बनाया है, जिससे नर्मदा के दर्शन करने वालों के साथ यहां आने वाले अन्य लोगों को मनोरंजन का एक नया स्थल मिल सके। इसी वजह से इस कॉरिडोर को पर्यटन की दृष्टि से ध्यान रखकर भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी पहले चरण में फील्ड सर्वे के बाद सड़क बनाने का काम शुरू होगा। नर्मदा नदी के तटीय हिस्से तिलवारा से शुरू होकर भटौली यानी ग्वारीघाट के बीच प्रस्तावित नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर की सड़क को लेकर संशय भी खत्म हो गया है। पहले यह सड़क 60 मीटर चौड़ी बनानी थी, लेकिन अब इसे 30 मीटर चौड़ा बनाने का निर्णय लिया गया। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने 3 जनवरी 2020 को नए एलायमेंट वाला नोटिफिकेशन जारी किया था। पौने दो साल बाद इसे स्वीकृति मिली है।

कॉरिडोर बहुत कुछ अहमदाबाद के साबरमती रिव्यू व्यू की तरह तैयार होगा। इसमें नर्मदा के दर्शन के अलावा लोग मनोरंजन के लिए पहुंच सकते हैं। बच्चों और बड़ों के लिए वक्त बिताने के लिए भरपूर इंतजाम होंगे। मुख्यालय से करीब 10 किमी दूरी पर भटौली गांव है। यहां से टूरिस्ट कॉरिडोर में प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा ग्वारीघाट, तिलवारा से भी जाने के रास्ते होंगे। करीब 2386 एकड़ जमीन में इसका निर्माण होगा। 655 एकड़ सरकारी जमीन अधिग्रहण की जाएगी। मौजूदा विकसित क्षेत्र 421 एकड़ है। नर्मदा से लगकर 300 मीटर तक चौड़ाई में आरक्षित हरित क्षेत्र है। इस कॉरिडोर में सात गांव की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इनमें तिलवारा, ललपुर, ग्वारीघाट, जिलहरी घाट, भटौली, परसवारा, गौरेया घाट गांव है। जेडीए सीईओ प्रशांत श्रीवास्तव कहते हैं कि नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर की स्वीकृति भोपाल से मिल गई है। जेडीए जल्द ही इसका फील्ड सर्वे करेगा। इसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। इसकी चौड़ा 30 मीटर और लंबाई लगभग साढ़े आठ किमी होगी।

नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर के बनने से जबलपुर के अराजक यातायात को सुधारने और पवित्र नर्मदा में नाले-नालियों की गंदगी को मिलने से रोका जाएगा। नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव जबलपुर-मंडला एनएच-12ए का शून्य किलोमीटर स्थानांतरित होने से भी पुराना है। वर्ष-1995 में टीएनसीपी को यह कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया गया। तत्कालीन टीएनसीपी अधिकारियों ने यह कॉरिडोर बनाने लंबा विचार करने के बाद मंजूरी दे दी। वर्ष-2005 के शहर के मास्टर प्लान में कॉरिडोर को शामिल कर लिया गया। इस प्रस्तावित कॉरिडोर की चौड़ाई 60 मीटर और नाले-नालियों की गंदगी नर्मदा नदी में मिलने से रोकने की योजना रही। यह निर्माण कार्य होने से पहले प्रस्तावित नर्मदा कॉरिडोर निर्धारित जगह से कुछ नीचे सरक गया। वहीं केंद्र के निर्देश पर मप्र सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने एनएच-12ए के शून्य किलोमीटर को शहर से हटाकर एनएच-7 (नया एनएच-30) के चूल्हा गोलाई मोड़ पर स्थानांतरित कर दिया। यह नई सड़क बनने से रायपुर-नागपुर आने-जाने वाले वाहनों को बायपास मिल गया। इससे नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर को बायपास बनाने का औचित्य खत्म हो गया। फिर भी टीएनसीपी ने संस्कारधानी के यातायात को व्यवस्थित बनाने और पवित्र नर्मदा में गंदगी मिलने से रोकने यह कॉरिडोर (नगरीय मार्ग) बनाने को जरूरी बताकर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजा था। इस पर शासन ने रुचि लेकर नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी। नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर पर नागरिकों के लिए तिलवारा से ग्वारीघाट या मंडला रोड पर आने-जाने का सीधा रास्ता मिलेगा। साथ ही इस कॉरिडोर के नाले-नालियों के लिए सीवरेज प्लांट से जोड़ा जाएगा। इस सीवरेज प्लांट में नाले-नालियों के गंदे पानी को साफ करके नर्मदा नदी में मिलने दिया जाएगा।

● **सुनील सिंह**

बढ़ेगा धार्मिक पर्यटन

साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर नर्मदा दर्शन पथ विकसित करने के लिए बनाई गई नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर योजना का रास्ता साफ हो गया है। भटौली से ग्वारीघाट होते हुए तिलवाराघाट के बीच कई धार्मिक स्थल हैं। इन तटों पर नर्मदा महोत्सव, प्रत्येक माह की पूर्णिमा, अमावस्या सहित अन्य अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जानकारों के अनुसार नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर विकसित होने पर यहां दुनियाभर से पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शहरी सीमा में स्थित नर्मदा के सभी प्रमुख तट एक परिपथ में जुड़ जाएंगे।

अन्नदाता इतना आक्रामक क्यों?

लखीमपुर खीरी और सिंघु बॉर्डर के हत्याकांड कर रहे अन्नदाता की छवि खराब...

बातचीत की पटरी से पूरी तरह उतरा आंदोलन...

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून के विरोध में नवंबर 2020 से किसान आंदोलन चल रहा है। बातचीत की पटरी से उतर चुका आंदोलन अब तक कई मोड़ देख चुका है। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उप्र में आंदोलन का ज्यादा प्रभाव है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने रणनीति बदली है। सिंघु व टीकरी बार्डर पर धरनों के साथ बड़ी-बड़ी महापंचायत की जा रही हैं। यही नहीं अन्नदाता अब आक्रामक होता जा रहा है।

● राजेंद्र आगाल

धरती को अपने पसीने से सींचकर फसल उगाने वाला अन्नदाता पिछले 10 महीने से ज्यादा समय से खेती-किसानी छोड़कर आंदोलन की राह पर है। ये किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार कृषि कानून वापस ले। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को होल्ड करा दिया है। यानी फिलहाल देश में कृषि कानून लागू नहीं होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर किसान आंदोलन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार के तरफ से आरोप लग रहे हैं कि किसानों के इस आंदोलन के पीछे कुछ देश विरोधी ताकतें भी काम कर रही हैं। सरकार के इन आरोपों को उस समय बल मिलता है जब 26 जनवरी में किसान लालकिले पर हल्ला बोलते हैं। फिर लखीमपुर खीरी हादसा और उसके बाद दिल्ली के **सिंघु बॉर्डर पर निहंगों** द्वारा एक व्यक्ति की हत्या। सवाल उठता है कि आखिर अन्नदाता इतना आक्रामक क्यों हो रहा है।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन जल्द ही 11वां महीना भी पूरा कर जाएगा। यह आंदोलन लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। सरकार और किसान अपनी-अपनी बात पर अडिग हैं। ऐसे में नजदीक भविष्य में इस आंदोलन का हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। आंदोलन जितना लंबा खिंचता जा रहा है, उतना ही नहीं आंदोलन स्थल पर मायूसी साफ देखी जा रही है। वहीं आंदोलन में किसानों की कमी खेतों में काम होने के चलते भी देखी जा रही है। हालांकि आंदोलनकारियों का जज्बा कम नहीं हुआ है लेकिन 10 माह से ज्यादा समय से आंदोलन चला आ रहा है ऐसे में किसान भी थक चुके हैं। उनके चेहरे पर उदासियां साफ देखी जा रही हैं। यहीं कारण है कि अब आंदोलन में पहले जैसी बात नहीं रही है। अब टीकरी बॉर्डर की मेन सभा पर वक्ताओं की संख्या भी कम हो गई है। पहले जहां वक्ताओं को बोलने का समय ही नहीं मिल पाता था वहीं अब 10-12 वक्ता ही मंच से बोल रहे हैं। उनमें भी अधिकांश वक्ता कुछ किसान नेता ही हैं। पहले तो हर रोज नए-नए वक्ता भारी संख्या में टीकरी बॉर्डर पहुंचते थे लेकिन अब उनकी संख्या कम है। साथ ही अब सभा में आंदोलनकारी भी कम ही आ रहे हैं। सभा स्थल पर अब हाजिरी 100-120 तक ही सिमट कर रह गई है।

अराजक हो रहा आंदोलन

संयुक्त किसान मोर्चे का कृषि कानून विरोधी आंदोलन न तो गैर-राजनीतिक रहा और न ही अहिंसक साबित हुआ। यह आंदोलन अराजकता और हिंसा के नए कीर्तिमान बना रहा है। आम किसान के समर्थन से वंचित यह आंदोलन मोदी विरोधी दलों के जनाधारहीन होने की कहानी भी कहता है। भारतीय राजनीति में अब सभी वर्जनाएं टूट गई हैं। संविधान की व्याख्या अब कानून के मुताबिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की जरूरत के मुताबिक होती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल में भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र ने सरकार और गुंडागर्दी दोनों का इस्तेमाल किया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य सरकार ने एक संगठन द्वारा बुलाए बंद की अपील को कामयाब बनाने के लिए बाकायदा कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया। संविधान निर्माताओं ने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी, मगर इस पर किसी विपक्षी दल को संविधान और जनतंत्र खतरे में नजर नहीं आया।

इस आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के दो दावे या वादे बेमानी साबित हुए हैं। पहला यही कि यह गैर राजनीतिक है और दूसरा यह कि आंदोलन अहिंसक होगा। सोते-जागते गांधी की दुहाई देने वालों को अब गांधी नहीं याद आते। चौरीचौरा में हिंसा के बाद गांधी ने अपना आंदोलन रोक दिया था। इसके विपरीत संयुक्त किसान मोर्चा का आचरण देखिए। गणतंत्र दिवस पर लाल किले और दिल्ली के दूसरे इलाकों में अराजकता का जो नंगा नाच हुआ वहीं इस कथित अहिंसक आंदोलन को रोकने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह और खतरनाक है।

पंजाब में भाजपा विधायक के कपड़े फाड़ दिए, पश्चिमी उप्र में विधायक की गाड़ी पर हमला, हरियाणा में विधायक को बंदी बना लिया। हरियाणा और पंजाब में जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में नहीं जाने दिया जा रहा। फिर लखीमपुर खीरी में चार लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उप्र में ब्राह्मणों और गरीबों की चिंता से दुखी होने वालों में घटना के इस पक्ष पर गजब का सन्नाटा है। इन सब बातों से भी ज्यादा चिंता की बात है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का यह बयान कि लखीमपुर खीरी में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या गलत नहीं है। उनके इस बयान पर किसी विपक्षी दल की कोई **प्रतिक्रिया** नहीं आई। किसी अदालत ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। हिंसा के लिए खुल्लम-खुल्ला उकसाने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो क्या मान लिया जाए कि देश में खून के बदले खून का कानून लागू हो गया है।

राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं

इस आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं है, ऐसे सवाल भी देशभर में उठ रहे हैं। दरअसल, होता यह आया है कि किसान हितैषी होने का दावा करके कई लोगों ने अपना राजनीतिक हित साधा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के पीछे किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं है। विगत दिनों संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढूनी राजनीतिक नेताओं से मिले और फिर किसानों

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर लगा दी है रोक

सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए अदालत एक समिति गठित करेगी, लेकिन किसानों की तरफ से इस समिति की चर्चा में शामिल होने की उम्मीद कम लग रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीनों नए कृषि कानून फिलहाल देश में कहीं भी लागू नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन्हें निरस्त नहीं किया जाएगा। आदेश देते हुए पूर्व चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, हम तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं। अदालत ने इसके साथ तीनों कानूनों और उन्हें लेकर किसानों की मांगों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का भी आदेश दिया। समिति के सदस्य नियुक्त करने से पहले अदालत ने सरकार से विशेषज्ञों के नाम सुझाने को कहा है। चीफ जस्टिस ने अपनी तरफ से जाने माने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी संस्था के दक्षिण एशिया निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और शेतकारी संगठन के अनिल घनवत को समिति के सदस्यों के रूप में मनोनीत किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप गतिरोध को अंत करने में कितना सहायक सिद्ध होगा यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ी संख्या में धरने पर बैठे किसानों ने कानूनों पर रोक लगाने और समिति गठित करने के आदेश को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि उनकी मांग तीनों कानूनों को निरस्त करने की है और सिर्फ रोक लगाए जाने से वे संतुष्ट नहीं हैं। किसान किसी भी समिति के आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को यह स्वीकार्य नहीं है और हर वो व्यक्ति जो दिल से इस समस्या के समाधान में रूचि रखता है वो समिति के आगे जाएगा।

से पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने की अपील की। उन्हें कुछ दिन के लिए मोर्चे से निलंबित करने का नाटक किया गया। संगठन ने अब यह नाटक-आडंबर भी त्याग दिया है। टिकैत से किसी ने सवाल भी नहीं पूछा। किसान आंदोलन के नाम पर एक ऐसा युद्ध लड़ा जा रहा है जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री से सारी नैतिकता, संविधान के प्रविधानों के अनुसार काम करने, हिंसा के खिलाफ संयम बरतने जैसी तमाम अपेक्षाएं हैं। दूसरे पक्ष के लिए इन सब बातों के विरुद्ध आचरण की छूट है।

किसान नेता किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं। उनका संविधान में भी कोई यकीन नहीं दिखता। वे नहीं बताएंगे कि सरकार ने जो तीन कृषि कानून बनाए हैं उनमें क्या खराबी है? उनकी बस एक ही जिद है कि कानून रद्द करो। क्यों रद्द करो? क्योंकि उसके बिना जिन राजनीतिक दलों का खेल वे खेल रहे हैं उन्हें फायदा नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार का विरोध कर रहे विपक्षी दलों ने सारी ताकत लगा दी, लेकिन इस कथित आंदोलन को ढाई राज्यों से बाहर नहीं पहुंचा सके।

लखीमपुर जैसी घटनाएं और

लखीमपुर खीरी में चार लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर मार दिया गया। क्या यह सुनियोजित था या बदहवासी में ऐसा हुआ? इसकी जांच हो रही है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष पर आरोप लगा तो पुलिस ने हत्या और अन्य धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया। चार दिन बाद गिरफ्तारी भी हो गई। 15 घंटे में योगी सरकार ने किसानों की सभी मांगें भी मान लीं। राकेश टिकैत ने उप्र के एडीजी कानून व्यवस्था के साथ साझा प्रेस कांफ्रेंस में इसकी घोषणा कर दी। लगा कि मामला ठंडा हो गया और कानून

कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या किसानों के हित में नहीं है?

कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों की चिंता खासकर दूसरे एक्ट को लेकर है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती को अनुमति दी गई है। यानी कोई पहले ही किसानों को पेशगी रकम देकर किसी खास कृषि उपज को उगाने के लिए प्रेरित करे और उपज का मूल्य तय कर ले। इसके विरोध में तर्क है कि पूंजीपति सस्ती में कोई उपज खरीद लेंगे और अपने भंडारण क्षमता के दम पर स्टोर कर लेंगे और जब मार्केट में रेट बढ़े तब किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर नहीं रह जाएगा। पूरा फायदा पूंजीपति उठाएंगे। इससे शहरी आम आदमी भी पिसेगा। क्योंकि उपज को स्टॉक करके रखने को सरकार ने अनुमति दे दी है। लेकिन बारीकी से देखें तो दूसरे एक्ट में ही प्राइस एश्योरेंस की बात की गई है। यानी किसानों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ जो रेट तय किया है उसमें बाद में कोई व्यापारी उससे मुकर नहीं सकता। जिस प्राइस में कोई किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी उसे गारंटी है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक साल से लेकर पांच साल तक दोनों की सहमति के हिसाब से एग्रीमेंट तय होगा। किसान अगर ना चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे ना बढ़ाए, उसकी मर्जी है। किसानों के हक में यह भी बात है कि वो हर तरह के एग्रीमेंट कर सकता है। वो चाहे तो पचास प्रतिशत गारंटी रकम तय कर ले और पचास प्रतिशत फसलों पर यह तय कर ले कि फसल तैयार होने के बाद उस वक्त का जो बाजार मूल्य होगा वो उसे मिले।

अपना काम करने लगा। इससे दूसरे खेमे में बेचैनी नजर आने लगी। इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकते हैं। पहले टिकैत को लानत भेजी गई। टिकैत को तो जिधर फायदा दिखता है, उधर झुक जाते हैं। सो पलट गए। अब भारत बंद, अरदास, अस्थि कलश यात्र, रेल रोको और लखनऊ में महापंचायत जैसे कार्यक्रमों की घोषणा की गई।

संयुक्त किसान मोर्चा का यह आंदोलन अराजकता और हिंसा के नए कीर्तिमान बना रहा है। महाराष्ट्र हमेशा से किसान आंदोलनों के लिए विख्यात रहा है। उस महाराष्ट्र में मोर्चा नेताओं के आंदोलन को पिछले एक साल में कभी समर्थन नहीं मिला। बंद करवाने के लिए सरकार की मदद लेनी पड़ी। इस आंदोलन की किसानों के बीच अविश्वसनीयता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? ऐसा हश्र किसी भी आंदोलन का हो सकता है, पर इस आंदोलन का हुआ, जो कहीं ज्यादा गंभीर बात है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इस आंदोलन को देश के सभी मोदी विरोधी राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। आम किसान के समर्थन से वंचित यह आंदोलन मोदी विरोधी दलों के जनाधारहीन होने की कहानी भी कहता है। तो दो शून्य मिलकर क्या बनते हैं? यह बताने के लिए आपको गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं है।

कायदे से कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन का 26 जनवरी की दिल्ली की घटना के बाद ही पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि दोनों पक्ष (सरकार और किसान संगठन) बातचीत शुरू करने की जरूरत जताते रहे, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। सरकार कहती रही कि किसान संगठन कृषि कानूनों की खामियां बताएं, तो वह उन्हें दूर करने के लिए आगे बढ़े। इसके जवाब में किसान संगठन यह कहते रहे कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार इस पर राजी नहीं हुई, तो किसान संगठन भी अपना आंदोलन जारी रखने पर अड़ गए। उनकी ओर से कभी यह कहा गया कि 2024 तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और कभी 10 साल तक धरने पर बैठे रहने के इरादे प्रकट किए गए। फिलहाल 10 महीने बीत चुके हैं और दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू होने के कोई आसार नहीं दिखते। शायद दोनों पक्षों ने यह तय कर लिया है कि कोई भी अपने रवैये से टस से मस नहीं होगा। अपने-अपने रवैये पर अडिग दोनों पक्ष बातचीत की जरूरत भले जताते रहे हों, लेकिन साथ में एक-दूसरे के खिलाफ बयान भी दागते रहे। इसके नतीजे में तर्क की जगह कुतर्क लेते रहे। इससे कुल मिलाकर कटुता और वैमनस्यता ही बढ़ी। लखीमपुर खीरी की घटना की जड़ में यही कटुता और वैमनस्य है। इसी बैर भाव ने 26 जनवरी के दिन लाल किले से देश को शर्मिंदा

करने वाली घटना को अंजाम दिया था।

विपक्ष का खुला समर्थन

सरकार और किसान आंदोलनकारियों के बीच जारी लंबे गतिरोध के बीच एक काम यह भी हुआ कि एक के बाद एक विपक्षी राजनीतिक दल किसान संगठनों के साथ खुलकर खड़े होने के लिए आगे आते रहे। वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए सरकार को कोसते रहे और किसान संगठनों की पीठ थपथपाते रहे। विपक्षी दलों के किसान संगठनों के साथ खड़े होने से उनके और सरकार के बीच जारी गतिरोध कम होने के बजाय और बढ़ गया। यह गतिरोध कहां तक पहुंच गया है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि अभी जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए तो राकेश टिकैत ने ट्वीट कर जो बाइडन से भारत सरकार की शिकायत की। इस गतिरोध से न तो सरकार का कुछ बिगड़ा और न ही किसान संगठनों का, लेकिन उसका भुगतान देश करता रहा और शायद आगे भी करता रहेगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी की खौफनाक घटना के बाद भी ऐसे कहीं कोई संकेत नहीं कि दोनों पक्ष बातचीत करने के लिए आगे आएंगे।

सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध टूट सकता था, यदि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सक्रियता और साहस दिखाता, लेकिन उसे तो करीब 9 माह बाद यह याद आया कि किसान संगठन उन कृषि कानूनों के खिलाफ धरना-प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, जिनके अमल पर उसने इस वर्ष जनवरी में ही रोक लगा दी थी। ऐसा तब हुआ जब किसान संगठन दिल्ली को ही यानी जहां सुप्रीम कोर्ट स्थित है, घेर कर बैठे हैं। किसान संगठनों के इस लंबे आंदोलन के दौर में केवल लाल किले में उपद्रव से लेकर लखीमपुर खीरी में रक्तरंजित उत्पात तक ही नहीं हुआ, बल्कि अन्य अनेक घटनाएं हुईं।

पंजाब में सैकड़ों मोबाइल टावर तोड़े गए, हरियाणा में कई बार सड़कों को घेरकर धरना-प्रदर्शन करने के साथ भाजपा नेताओं के साथ मारपीट की गई, आंदोलन में शामिल होने आई एक युवती से दुष्कर्म हुआ, किसान संगठनों की रीति-नीति से नाराज एक शख्स को जलाकर मार दिया गया, कई जगह टोल प्लाजा पर कब्जा किया गया, धरना दे रहे कई किसानों की मौत हुई और तमाम रास्तों को बाधित किया गया। इस सबके बीच उन लाखों-करोड़ों आम लोगों की किसी ने सुध नहीं ली, जो किसान संगठनों के धरना-प्रदर्शन के कारण अपने गंतव्य तक आने-जाने में परेशान होते रहे और अपने समय एवं संसाधन की बर्बादी होते देखते रहे। इन असहाय और निरुपाय लोगों पर कोई नहीं पसीजा-न किसान संगठन, न सरकार और न ही न्यायपालिका। ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से यह सुनने को मिलता रहा कि लोग यह जानते हैं कि जब उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो शीर्ष अदालत उनकी मदद के लिए आगे आती है। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला।

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

किसान आंदोलन के कारण रास्ते बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी स्वाभाविक है। कई महीने गुजर जाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। इसका नतीजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। रास्ते खुलवाने के लिए सर्वोच्च अदालत पहले भी केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को आदेश दे चुकी है। लेकिन अदालत के बार-बार कहने के बाद भी इन राज्य सरकारों की ओर से रास्तों को खुलवाने के ठोस प्रयास होते नहीं दिखे, बल्कि सरकारें किसानों पर दोष मढ़ती रहीं कि वे बातचीत के लिए राजी नहीं हैं। इसलिए किसानों के साथ ही सरकारों के रुख को लेकर भी अदालत कम नाराज नहीं है। किसान दिल्ली में न घुस पाएं, इसके लिए पुलिस ने सीमाओं को बंद कर दिया था और जगह-जगह लोहे और सीमेंट के अवरोधक खड़े कर दिए थे। इसलिए किसान सड़कों पर ही बैठ गए और वहीं अस्थायी ठिकाने भी बना लिए। यही स्थिति अभी तक कायम है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की सीमाएं बंद होने और रोजाना लगने वाले भारी जाम से लोगों को मुश्किलें तो रही हैं। फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत जैसे शहर दिल्ली से सटे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में यहां से लोग दिल्ली आते-जाते हैं। पर पिछले 10 महीने से लोगों को सुबह-शाम भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़कें बंद होने से कई-कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देश का बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। दिल्ली और इसके आसपास हजारों छोटी और मझोली इकाइयां हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाती-बेचती हैं।

आंदोलन बना परेशानी का सबब

किसान संगठनों की धरनेबाजी केवल लोगों को परेशान ही नहीं कर रही, बल्कि उनके पेट पर लात मारने का भी काम कर रही है। बाधित रास्ते के कारण बहादुरगढ़ की औद्योगिक इकाइयां संकट में हैं और पंजाब में कम से कम तीन औद्योगिक प्रतिष्ठान किसान संगठनों की धरनेबाजी के कारण बंद हो चुके हैं। इसके चलते एक हजार से अधिक लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इसके बाद भी किसान संगठनों का दावा है कि वे किसानों के साथ नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वास्तव में तो वे नौजवानों के हितों से खिलवाड़ ही कर रहे हैं। वे छोटे किसानों के हितों की भी चिंता नहीं कर रहे। इसीलिए उनके आंदोलन में उनकी भागीदारी नहीं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन वस्तुत: बड़े किसानों और आढ़तियों का आंदोलन है। और भी गौर से देखें तो यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उप्र के समर्थ किसानों का आंदोलन है। इस आंदोलन की प्रकृति ठीक वैसी ही है जैसी शाहीन बाग आंदोलन की थी। वह जिद और सनक पर सवार है। हर गुजरते दिन के साथ यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि इस आंदोलन का मूल मकसद विभिन्न किसान नेताओं की ओर से अपने राजनीतिक हित साधना है।

इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि किसानों की आड़ में नेतागीरी कर रहे नेता पंजाब और उप्र के आगामी विधानसभा चुनाव में दखल देने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके लिए किसानों को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। कृषि कानून विरोधी आंदोलन में किसान उसी तरह मोहरा बनाए जा रहे हैं, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले आम लोग बनाए गए थे। जैसे इस संगठन का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाकर और अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर राजनीति में कूदना था, वैसे ही किसान संगठनों का मकसद किसानों को मोहरा बनाकर अपने लिए राजनीति का मैदान तैयार करना है। इसी कारण किसानों

आंदोलन में गुम हुआ कृषि सुधारों का संदेश

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उप्र के कुछ इलाकों में इन दिनों कृषि सुधारों के विरुद्ध कुछ किसान संगठनों के विरोध-प्रदर्शन खबरों में बने हुए हैं। इसी क्रम में विगत एक सप्ताह के दौरान ही मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई और हरियाणा के करनाल में किसान संगठनों और राज्य सरकार के बीच संघर्ष और उसके उपरांत उस पर विराम भी लग गया। हालांकि किसान संगठनों की जिस मुहिम से किसानों की बदहाली दूर करने के उपाय सुझाने, फसल विविधीकरण के लिए आवाज उठाने की अपेक्षा थी वह आंदोलन अब गेहूं-धान की गारंटीड सरकारी खरीद और धार्मिक नारों में उलझकर रह गया। अब तो यह अभियान राजनीतिक रूप लेते हुए मोदी-योगी को हटाने पर केंद्रित हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों की बदहाली केंद्र में नरेंद्र मोदी और उप्र में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद शुरू हुई। जबकि सच्चाई यही है कि पिछले कुछ समय से जारी किसान संगठनों के कर्कश कोलाहल में कृषि क्षेत्र की कायापलट करने के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे उन नवोन्मेषी उपायों के सकारात्मक संदेश कहीं गुम से हो गए हैं। वास्तविकता यही है कि मोदी सरकार ने खेती-किसानी की बदहाली दूर करने के लिए कई नवोन्मेषी योजनाएं लागू की हैं। उसने किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजने की पहल की है। इसी का परिणाम है कि किसानों की आत्महत्याओं में उल्लेखनीय कमी आई है।

का ठगा जाना तय है। किसान संगठनों का यह कहना फिजूल है कि वे संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे दरअसल आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कुचल ही नहीं रहे, बल्कि उनकी बेबसी पर अट्टहास भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में यह अट्टहास राकेश टिकैत की ओर से यह कहकर किया गया कि हम संकल्प लेते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर धरना देना नहीं छोड़ेंगे, भले ही वहां हमारी कब्र क्यों न बन जाए? यह ऐलान सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती ही नहीं, इन धरनों से आजिज आए लोगों को यह सख्त संदेश है कि कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें इसी तरह परेशान करते रहेंगे।

किसान संगठनों के धरनों से परेशान हो रहे लोगों के सामने बेबस होकर रह जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं, क्योंकि कोई भी उनकी नहीं सुन रहा- न पुलिस, न सरकारें और न ही अदालतें। पुलिस और सरकारों की मजबूरी समझ आती है, लेकिन आखिर अदालतों को किसका भय है? क्या वे भी किसान संगठनों की मनमानी के आगे असहाय हैं? पता नहीं सच क्या है, लेकिन जब आम आदमी इस तरह परेशान होता है तो वह केवल कुढ़ता ही नहीं है, बल्कि व्यवस्था के विभिन्न अंगों पर उसका भरोसा भी कम होता है और जब ऐसा होता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है।

किसान अब भी परेशान

आजादी के बाद खेती-किसानी को देश की आत्मा मानते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 'सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन खेती नहीं।' दुर्भाग्यवश लोकलुभावन नीतियों और वोट बैंक की राजनीति के कारण खेती का इंतजार खत्म नहीं हुआ और वह बदहाली का शिकार बनती गई। आज स्थिति यहां तक आ गई है कि ग्रामीण मजदूरों की आमदनी किसानों से ज्यादा हो गई है। 2012-13 में एक औसत भारतीय किसान परिवार की खेती से होने वाली मासिक आमदनी 3,081 रुपए थी। 6 साल बाद अर्थात् 2018-19 में यह बढ़कर महज 3,798 रुपए पर पहुंची। दूसरी ओर इन 6 वर्षों में मजदूरी से होने वाली कमाई 2,071 रुपए से बढ़कर 4,063 रुपए हो गई। पुराने कृषि कानूनों की ही देन है कि अब किसानों से ज्यादा मजदूरों की संख्या बढ़ रही है।

उदाहरण के लिए 2013 से 2019 के बीच खेती करने वाले परिवारों की संख्या जहां 9 करोड़ से बढ़कर 9.3 करोड़ हुई, वहीं कृषि कार्य में शामिल नहीं होने वाले परिवारों की संख्या 6.6 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ पर पहुंच गई। 2011 की जनगणना में भी बताया गया है कि हर रोज 2,000 किसान खेती छोड़ रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि पारिवारिक बंटवारे से खेतों का आकार इतना छोटा हो गया है कि उनमें खेती लाभकर नहीं रह गई है। खेती के घाटे का सौदा बनने का ही नतीजा है कि किसान का बेटा खेती करने का इच्छुक नहीं है। इतना ही नहीं कृषि विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले अधिकांश छात्र अन्य व्यवसायों में जा रहे हैं।

एक ओर किसानों की आमदनी में ठहराव आया है तो दूसरी ओर उनके ऊपर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए 2012-13 में एक औसत किसान परिवार पर 47,000 रुपए का कर्ज था, जो कि 2018-19 में बढ़कर 74,121 रुपए हो गया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक ओर किसानों की हालत मजदूरों से भी बदतर होती जा रही है तो दूसरी ओर कृषि उपजों के कारोबार में लगी कंपनियों का मुनाफा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण है कि जब किसान की उपज बाजार में आती है तब उसके दाम गिर जाते हैं और बाद में कई गुना बढ़ जाते हैं। स्पष्ट है भारतीय किसानों की बदहाली की एक बड़ी वजह यह है कि उनकी उपज की वाजिब कीमत नहीं मिलती। इसका कारण है हर स्तर पर बिचौलियों का प्रभुत्व। इनको हटाकर उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने की मुहिम में मोदी सरकार जुटी है। इस दिशा में कारगर कदम है इलेक्ट्रानिक मंडी (ई-नाम) और किसान रेल का संचालन।

लखीमपुर बना चुनावी एजेंडा

लखीमपुर खीरी का मामला उप्र की राजनीति में असर करीब-करीब वैसे ही दिखाने लगा है जैसे बिहार चुनाव के पहले सुशांत सिंह राजपूत केस। हो सकता है राजनीतिक तौर पर ये मामला भी लंबा न खिंच सके, जो हाल बिहार चुनाव में देखने को मिला था। शुरू में सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर ऐसा लगा जैसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, लेकिन पटना से दिल्ली और मुंबई तक भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद वो चुनाव की तारीख आने से पहले ही अप्रासंगिक होने लगा था, लखीमपुर खीरी में चर्चित आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान में लेकर उप्र की योगी सरकार को खरी खोटी सुनाए जाने के बाद उप्र पुलिस ने सख्ती दिखाई और गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर पूछताछ चल रही है। आशीष मिश्रा सहित अब तक लखीमपुर खीरी केस में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चौथा आरोपी अंकित दास है जिसे आशीष मिश्रा का करीबी बताया जाता है और जिस थार जीप से किसानों को कुचले जाने की बात है, उसके ठीक पीछे चल रही फॉर्च्यूनर का रजिस्ट्रेशन अंकित दास के नाम पर ही बताया जा रहा है।

ऐसा लगा था कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के साथ ही सत्ताधारी भाजपा ने अपनी भूमिका की इतिश्री कर ली है, लेकिन तभी उप्र भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नेतागिरी को फॉर्च्यूनर से जोड़ते हुए बयान देकर नया ट्विस्ट ला दिया। मतलब, अजय मिश्रा के मंत्री पद पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। मतलब, ये भी हो सकता है कि भाजपा नेतृत्व को लखीमपुर खीरी केस को किसानों की तरफ मोड़ कर खुद को अलग करने के लिए एक सेफ पैसेज की तलाश हो सकती है और जैसे ही ऐसा कोई मौका मिलता है अजय मिश्रा का केंद्रीय मंत्रिमंडल से पत्ता साफ भी हो सकता है। कुछ-कुछ वैसे ही जैसे मीटू मुहिम के बीच आरोपों के घेरे में फंसे एमजे अकबर से इस्तीफा लेकर केंद्र की भाजपा सरकार ने पीछा छुड़ा लिया था। उप्र में चुनावी माहौल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस रैली, अमित शाह और प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ दौरे, मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन और अखिलेश यादव के वर्क फ्रॉम हो पॉलिटिक्स से बाहर निकलते ही शुरू हो गया था, लेकिन लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद हरकतें काफी तेज हो गई हैं। ध्यान देने वाली एक विशेष बात ये भी है कि साथ में किसान आंदोलन भी नए सिरे से जोर पकड़ने लगा है जो भाजपा की डबल मुश्किल की तरफ इशारे कर रहा है।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने बनारस रैली के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप दिया है और अखिलेश यादव भी रथयात्रा लेकर निकल पड़े हैं। अब देखना ये है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा डायल करते हैं या नहीं, जैसे जुलाई, 2021 की एक सुबह अचानक कई तत्कालीन मंत्रियों की सुबह की चाय का जायका भी बिगाड़ दिया था।

लखीमपुर खीरी केस को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास ठीक उसी अंदाज में पहुंचा जैसे दिल्ली दंगों के बाद गया था। तब कांग्रेस डेलिगेशन की अगुवाई कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद की थी, लेकिन इस बार नेतृत्व का जिम्मा बेटे-बेटी के पास रहा। वैसे भी पंजाब कांग्रेस संकट से जूझने में दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को ही कांग्रेस की नई लीडरशिप के रूप में देखा जाने लगा है। सोनिया गांधी तो अपने साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी साथ लेकर गई थीं, लेकिन राहुल-प्रियंका के साथ गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड्गे और एके एंटनी जैसे सीनियर नेता ही रहे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी के साथ-साथ प्रियंका गांधी ने भी मीडिया से बात की जिसमें बस एक ही बात पर जोर रहा, ये डेलीगेशन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उनकी तरफ से मिला है।

सोनिया गांधी और राहुल-प्रियंका के डेलीगेशन दोनों ही के निशाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ही है, तब सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की थी और अभी अमित शाह के जूनियर सहयोगी अजय मिश्रा को हटाने की मांग की गई है। तब पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ये भी बताया था कि राष्ट्रपति से मोदी सरकार को राजधर्म की याद दिलाने की भी गुजारिश की गई थी। जैसे ही राष्ट्रपति के सामने कांग्रेस की अमित शाह को हटाने की मांग सामने आई भाजपा की तरफ से 2020 के दिल्ली दंगों के समानांतर 1984 के सिख दंगों का मुद्दा उठाकर हमला बोल दिया गया और ये तो कांग्रेस की ऐसी कमजोर नस है जो सवाल उठते ही खामोश कर देता है, तब भी ऐसा ही हुआ, देखना होगा भाजपा के पास कांग्रेस के खिलाफ काउंटर करने का वैसा ही कोई सियासी औजार है या नया नुस्खा अपनाया जाता है?

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

बैकफुट पर आ चुकी भाजपा को मौके का इंतजार

उप्र में प्रियंका गांधी की सक्रियता का असर अखिलेश यादव पर वैसा ही हुआ लगता है जैसा ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के वक्त राहुल गांधी पर हुआ था। अखिलेश यादव के साथ-साथ उनके चाचा शिवपाल यादव भी एक्टिव हो गए हैं। समाजवादी विजय रथ के साथ ही सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकल पड़े हैं। हालांकि, अखिलेश यादव नहीं मानते कि प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होने वाला है। अखिलेश यादव कहते हैं - भाजपा और कांग्रेस में कितना फर्क है, दोनों की नीतियां एक हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर भाजपा को उप्र से नहीं हटाया गया तो ये टायरों से संविधान को कुचल देंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिए जाने के बाद से अखिलेश यादव लगातार टायरों की वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे उप्र भाजपा अध्यक्ष ने फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल किया है।

सबके निशाने पर कांग्रेस

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज सबसे कमजोर स्थिति में है। इसकी वजह यह है कि पार्टी में लगातार टूट हो रही है। कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं।

2014 में भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। लेकिन देखा यह जा रहा है कि सभी पार्टियां कांग्रेस को खंड-खंड करने में जुटी हुई हैं। यानी सभी पार्टियों ने कांग्रेसी नेताओं के लिए अपने द्वार खोल रखे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कांग्रेस खोखली होती जा रही है। चुनावों में भाजपा हो या अन्य पार्टियां सभी से केवल कांग्रेस को ही नुकसान होता है। आने वाले समय में पंजाब, उप्र, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा में चुनाव होने हैं और वहां कांग्रेस में टूट शुरू हो गई है।

आम आदमी पार्टी (आप) भी पंजाब, उप्र, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा में चुनावी बिगुल फूंक चुकी है और कई तरह के मुफ्त उपहारों का वादा कर रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शिवसेना कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी हैं, लेकिन दोनों ही कांग्रेस की कीमत पर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। यही नहीं केरल में तो माकपा भी कांग्रेस के दलबदलुओं को अपने खेमे में ला रही है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) ने एक राज्यसभा सीट देने से इनकार करके कांग्रेस को आइना दिखा दिया है, जबकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 25 सीटों पर लड़ने के लिए राजी करने के बदले इसका वादा किया था। कांग्रेस अब राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में द्रमुक के साथ समझौते से कतरा रही है। वहीं, उप्र में समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में से कोई भी कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाने में इच्छुक नहीं है।

यह स्थिति तब है जब सोनिया गांधी भाजपा से मुकाबले के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों का मोर्चा **बनाने की कोशिशों में जुटी** हैं। विपक्षी एकजुटता की ऐसी किसी व्यवस्था की सफलता इसमें निहित अंतर्विरोधों और परस्पर विरोधी महत्वाकांक्षाएं खुलकर सामने आने के कारण हमेशा संदेह से घिरी रही है। लेकिन देश के अधिकांश हिस्से में हाशिये पर धकेली जा चुकी जीओपी या ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपना अस्तित्व बचाए रखने की कवायद के तहत यह रणनीति आजमा रही है क्योंकि यह नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा को हराने में असमर्थ है। एक मायने में सोनिया गांधी ने तमिलनाडु में अपनी सास दिवंगत इंदिरा गांधी के नक्शेकदम पर चलते हुए वह करने की कोशिश की है, जो उन्होंने वहां 1971 के चुनाव में किया था। केंद्र में अपनी स्थिति सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्होंने एक समझौते के तहत लोकसभा चुनाव द्रमुक के साथ गठबंधन में लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में मोर्चा पूरी तरह अपने द्रविड़ सहयोगी दल को सौंप दिया था। यह दक्षिणी राज्य में कांग्रेस के ताबूत में कील ठोंकने जैसा साबित हुआ। सोनिया और फिर राहुल गांधी ने केंद्रीय राजनीति में बने रहने के लिए कई राज्यों में पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी दलों के साथ इसी तर्ज पर कुछ संशोधित फॉर्मूले आजमाए। इससे कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो गई, जो पहले ही मंडल-कमंडल की राजनीति के झटके से उबरने के लिए संघर्ष कर रही थी।

हाल ये है कि क्षेत्रीय दलों (हालांकि, उनमें से कुछ तकनीकी रूप से 'राष्ट्रीय दल' हैं जिनका आधार एक राज्य तक ही सीमित है) को अब कांग्रेस का अस्तित्व में बना रहना कतई सुहा नहीं रहा है। भाजपा को अपना दुश्मन नंबर-1 घोषित करके ये दल विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के वोट-शेयर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अन्यथा प्रमुख विपक्षी दल के नाते उसके खाते में जाते। उदाहरण के तौर पर टीएमसी या आप, पूर्वोत्तर या गुजरात या द्विध्रुवी राजनीति वाले किसी अन्य राज्य (जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आदि) में केवल प्रमुख विपक्षी दल (जो कि कांग्रेस है) की कीमत पर ही आगे बढ़ेंगे।

सबसे पहली बात तो यह है इन पार्टियों में से अधिकांश (चाहे वह टीएमसी, आप, एनसीपी, एसपी, बसपा, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) हो या फिर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी) का कोर वोट बैंक कांग्रेस से ही छिटककर बना था। आज भी इनकी जंग उसी वोट बैंक की होती है। लोकनीति-सीएसडीएस नेशनल इलेक्शन स्टडीज के मुताबिक, जैसा संजय कुमार ने कहा है, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल दोनों राष्ट्रीय चुनावों में अपना वोट शेयर गंवा रहे हैं। पिछले सात लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस का वोट शेयर 20 से 30 प्रतिशत के बीच रहा है, जो 2014 और 2019 में 20 प्रतिशत से भी थोड़ा नीचे आ गया। क्षेत्रीय दलों के मामले में यह गिरावट ज्यादा तेज रही है। 2019 में उन्हें 26.4 फीसदी वोट मिले जबकि उससे पहले

राहुल की राजनीति कांग्रेसी नेताओं को नहीं आ रही रास

अब यह और साफ है कि राहुल गांधी की राजनीति खुद कांग्रेसी नेताओं को भी रास नहीं आ रही है। इसका प्रमाण केवल पंजाब की उठापटक ही नहीं, बल्कि जी-23 गुट के नेताओं की ओर से उन पर निशाना साधना है। राहुल की मनमानी और चाटुकारों को तरजीह देने वाली राजनीति के कारण ही कांग्रेस के एक के बाद एक नेता बाहर जा रहे हैं। पिछले दिनों केरल और गोवा के कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं। सचिन पायलट भी नाराज हैं। अभी पंजाब का झगड़ा सुलझा नहीं है और उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी विधायकों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है।

खुद को कमजोर करती कांग्रेस

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह अपमानित होकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, वह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। एक ऐसे समय जब देश में कांग्रेस का जनाधार लगातार गिर रहा, तब उसके लिए पंजाब एक अहम राज्य है। अमरिंदर सिंह को अपमानित कर जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू को महत्ता दी गई, उससे कांग्रेस और गांधी परिवार की खोखली सोच ही उजागर होती है। प्रियंका गांधी के कहने पर उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वह इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद अमरिंदर सिंह के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। चूंकि इस अभियान को गांधी परिवार ने अपना समर्थन दिया इसलिए अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। यह बात और रही कि मुख्यमंत्री बनने की लालसा रखने वाले सिद्धू चैन से नहीं बैठे। उनकी यह लालसा बहुत पुरानी है। भाजपा में रहते हुए भी वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे। वह जब कांग्रेस में आए तो उनकी महत्वाकांक्षा आसमान छूने लगी। अमरिंदर के न चाहते हुए भी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद वह बेलगाम हो गए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमरिंदर सिंह की राहुल-प्रियंका से कभी नहीं बनी। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक उन्होंने अपने हिसाब से राजनीति की। अपने इस्तीफे के बाद उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि राहुल-प्रियंका अनुभवहीन हैं और उनके सलाहकार उन्हें गुमराह करते रहते हैं। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद दलित सिख चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने। पहले तो सिद्धू ने चन्नी के मुख्यमंत्री बनने का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने जैसे ही फैसले लेने शुरू किए, वह बिदक गए। दरअसल सिद्धू ने यह सोचा था कि वह चन्नी को अपने हिसाब से नियंत्रित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

पांच चुनाव में इनका वोट शेयर 30 फीसदी से ऊपर रहा था। जाहिर है कि इन दोनों की कीमत पर फायदा भाजपा को हो रहा है।

कांग्रेस के और पतन की ओर जाने के संकेतों के बीच क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की कीमत पर अपने नुकसान की भरपाई की कोशिश करने का एक अच्छा अवसर मिल गया है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वोट बैंक टीएमसी और भाजपा के बीच बंट गया है। इधर, दिल्ली में कांग्रेस का ही एक बड़ा वोट शेयर आप के खाते में गया जबकि तेलंगाना में यह टीआरएस को मिला, और यही हाल अन्य जगहों का भी है। ये इन पार्टियों के लिए अच्छा मौका है कि बचे-खुचे जनाधार पर भाजपा कब्जा जमा ले, इससे पहले वही इसे अपने खाते में लाने की कोशिश करें।

दूसरा, इनमें से कुछ क्षेत्रीय-राष्ट्रीय दलों को अब अपने घरेलू मोर्चे पर भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है, जैसे बंगाल में टीएमसी, दिल्ली में आप, तमिलनाडु में डीएमके आदि। ऐसे में राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभरने के लिए उनकी कोशिश अन्य राज्यों में अपने विस्तार के लिए कांग्रेस के वोट शेयर में सेंध लगाने की है। इसका श्रेय घरेलू मैदान पर उनके भाजपा से जीतने को जाता है, और इन छोटे दलों को भरोसा है कि अगर अन्य राज्यों में कांग्रेस उनके रास्ते से हट जाए तो वह वहां भी ऐसा प्रदर्शन दोहरा सकते हैं। असम में कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे सुष्मिता देव और गोवा में लुइजिन्हो फलेरियो का टीएमसी में शामिल होना और यहां तक कि पूर्व **कांग्रेसी प्रद्योत** देबबर्मन का ममता के साथ बातचीत करना इसी ट्रेंड को दर्शाता है।

तीसरा, इन छोटे दलों का एक ऐसी पार्टी के तौर पर कांग्रेस के ऊपर कोई भरोसा नहीं रह गया है जो भाजपा के खिलाफ किलेबंदी में सक्षम हो। इसलिए, उन्हें सिर्फ अपने बलबूते पर भगवा पार्टी को सत्ता से हटा पाने का भरोसा भले ही न हो लेकिन पूरी तरह पस्त पड़ चुकी कांग्रेस का कंधा बनकर इस लड़ाई में उसका अस्तित्व बचाए रखने में भी उन्हें कोई औचित्य नजर नहीं आता है। इसके बजाय कांग्रेस का खत्म हो जाना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

चौथा, कांग्रेस का फिर से मजबूत होना उनमें से कई के लिए आगे उसी तरह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जैसा आज भाजपा से है। उदाहरण के तौर पर टीआरएस के चंद्रशेखर राव के लिए आज भाजपा के साथ लड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि तेलंगाना में कांग्रेस के फिर मजबूत होने की स्थिति में वह दोहरे मोर्चे पर जंग लड़ें। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के मामले में भी स्थिति यही है।

आखिर में, सबसे अहम बात यह कि जब तक कांग्रेस किसी भी संभावित गठबंधन में प्रमुख खिलाड़ी बनी रहती है, क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं (प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित पद पर काबिज होना) पूरी कर पाना मुश्किल होगा। ऐसे में और कुछ नहीं तो अस्तित्व बचाने के लिए हाथ-पैर मारती कांग्रेस उनके लिए उम्मीदों को बढ़ाने वाली ही है।

कांग्रेस की दिक्कत यह है कि केंद्र में उसकी सात साल से सरकार नहीं और जिन राज्यों में है, वहां मुख्यमंत्री पद के लिए नेता आपस में लड़ रहे हैं। आलाकमान लाख चाहकर भी इस संकट का हल नहीं निकाल पा रहीं। भाजपा इसे अपने लिए मुफीद मान रही है और उसके क्षेत्रीय नेता अपने भाषणों में कांग्रेस की इस लड़ाई को खूब भुना रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह संकट की स्थिति इसलिए भी है; क्योंकि उसे अगले साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव लड़ने हैं। कांग्रेस की इस लड़ाई का जनता में निश्चित ही उलटा संकेत जाने के भय से कांग्रेस घिरी है।

पंजाब कांग्रेस में उठापटक के बीच जिस तरह जी-23 समूह के नेता सक्रिय हुए, उससे यही पता चलता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। जहां इस समूह के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने यह सवाल पूछा कि जब कोई अध्यक्ष नहीं तो फैसले कौन ले रहा है, वहीं गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाने की मांग की। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक समूह सिब्बल के घर जा धमका। हालांकि इस घटना की कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आलोचना की, लेकिन लगता नहीं कि इससे गांधी परिवार अपनी रीति-नीति बदलेगा। यह साफ है कि राहुल गांधी परोक्ष रूप से कांग्रेस को चला रहे हैं और सोनिया गांधी उनका हर तरह से साथ दे रही हैं।

● **रजनीकांत पारे**

उलटे पड़ते दांव

एक बार फिर भाजपा उप्र के रास्ते 2024 में केंद्र की सत्ता में काबिज होने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इस कोशिश में उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने भी दांव चल रहे हैं, वे उलटे पड़ रहे हैं। बताया जाता है कि भाजपा में योगी अलग ही लाइन पर काम कर रहे हैं इसका परिणाम यह हो रहा है कि पार्टी में समन्वय नहीं बन पा रहा है। हालांकि कई मौकों पर योगी ने अपना लोहा भी मनवाया है।

उप्र भाजपा और योगी सरकार के बीच क्या सब कुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। जानकार समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों संगठन और सरकार के हुक्मरानों द्वारा ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें सरकार और पार्टी के उद्धार की जगह आपसी वैमस्य नजर आता हो। इसीलिए तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उप्र भाजपा के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी, जो उसे पिछड़े समाज के वोटरों की नाराजगी को दूर करने के लिए एक दलित नेत्री और पूर्व सांसद प्रियंका रावत का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि भाजपा के पास उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर पिछड़े समाज के नेता मौजूद हैं। केशव प्रसाद को कोई कैसे भूल सकता है जब उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व अक्टूबर 2018 में प्रदेश भर में पिछड़ा वर्ग समाज सम्मेलन कराकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया था। तब पिछड़ा वर्ग के वोटरों ने दिल खोलकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। केशव प्रसाद मौर्य की तरह ही पूर्व बसपाई और अब योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा में इंट्री ही इसलिए मिली थी क्योंकि उनकी पिछड़ा वर्ग समाज में काफी अच्छी और मजबूत पकड़ थी। भाजपा चाहती तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का भी इस्तेमाल पिछड़ों को मनाने के लिए कर सकती थी, लेकिन न जाने क्यों भाजपा आलाकमान ने पिछड़ों को मनाने की जिम्मेदारी किसी पिछड़ा समाज के नेता की जगह अपनी दलित नेत्री और बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका रावत के कंधों पर डालना ज्यादा उचित समझा। भाजपा ने प्रियंका रावत के कंधों पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी डाली है। यहीं से पिछड़ा समाज की नाराजगी भाजपा से कम होने की बजाय बढ़ने लगी है, जिस तरह से प्रियंका रावत ने पिछड़ों को मनाने के लिए सम्मेलन आयोजित किए हैं, उसमें कई खोट नजर आ रहा है। ऐसा लगता है प्रियंका रावत ने पिछड़ा वर्ग समाज का आंदोलन करने से पूर्व पिछड़ा समाज के बारे में कोई अध्ययन ही नहीं किया। अगर ऐसा न होता तो प्रियंका रावत पिछड़ा समाज की 79 जातियों में से सिर्फ 17 जातियों का 'पिछड़ा वर्ग सम्मेलन' नहीं करातीं। इतना ही नहीं जिन 17 पिछड़ी जातियों को प्राथमिकता दी गई है, उसमें से कई जातियों का तो वजूद ही **बहुत सीमित** है, जबकि तमाम ऐसी जातियों को छोड़ दिया गया है जिनकी अच्छी खासी आबादी है।

सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि प्रियंका रावत हैं कौन और इनकी संगठन में क्या हैसियत है। अगस्त 2021 से पूर्व प्रियंका की पार्टी में कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन जब

योगी से खुश नहीं एमपी-एमएलए

उप्र में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं तब से लेकर आज तक उप्र के सांसदों-विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का एक ही रोना रहा है कि योगी सरकार में जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। योगी को अपने नेताओं से अधिक भरोसा ब्यूरोक्रेसी पर है। योगी ने 'टीम-11' बना रखी है। यही टीम-11 हर बड़ा फैसला लेती है। यह 'टीम-11' और कोई नहीं 11 सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। इनकी सलाह पर ही योगी महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, इसी के चलते भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधि करीब पांच सालों तक मूलदर्शक बने रहने को मजबूर रहे। इन नेताओं की न जिलाधिकारी कार्यालय में सुनवाई होती थी, न थाने-चौकी पर कोई इनकी सुनता था। क्षेत्र में कौन से विकास कार्य कैसे चलने और पूरे किए जाएंगे, यह भी अधिकारी ही तय करते हैं, जिसके चलते उक्त नेताओं और जनप्रतिनिधियों को जनता के कोपभाजन का भी शिकार बनना पड़ता है। अपनी व्यथा कई बार यह सांसद-विधायक और सभासद आलाकमान तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का।

2017 को नहीं भूले लोग

2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को जनता के सामने ऐसे पेश किया था, जैसे यदि भाजपा की सरकार बनेगी तो केशव ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो अचानक योगी का पर्दापण हुआ और वह मुख्यमंत्री बन गए। केशव खून का घूंट पीकर उपमुख्यमंत्री बनकर ही रह गए। इसी के चलते योगी और केशव के रिश्ते कभी मधुर नहीं रह पाए। इस बात का अहसास तब एक बार फिर हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पिता की कौशाम्बी में हुई मौत के समय केशव के घर जाकर सांत्वना देना उचित नहीं समझा। इस पर काफी विवाद हुआ। भाजपा आलाकमान को भी इस बात की जानकारी हुई तो वह डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आई। 21 जून 2021 को योगी को केशव प्रसाद के यहां जाना ही पड़ा। साढ़े चार साल में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री के घर गए थे, जबकि दोनों के आवास में सिर्फ 100 मीटर की ही दूरी है। मुख्यमंत्री लंच के लिए गए थे। इस मौके पर उनके साथ आरएसएस के सह सर कार्यवाह कृष्णगोपाल, महामंत्री संगठन बीएल संतोष सहित कोर कमेटी के सदस्य मौजूद थे।

उप्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 22 अगस्त को अपनी बहुप्रतीक्षित टीम घोषित की तो इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम प्रियंका सिंह रावत का ही था। बाराबंकी की 35 वर्षीया पूर्व सांसद प्रियंका ने उप्र भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में धमाकेदार एंट्री मारते हुए सीधे प्रदेश महामंत्री के रूप में जगह बना ली थी, जबकि पार्टी के कई पुराने वफादार नेता महामंत्री बनने के लिए आलाकमान का मुंह ही देखते रह गए, जो कई सालों से पार्टी के लिए पसीना बहा रहे थे। प्रियंका को यह पद तब मिला था, जबकि करीब सवा दो साल पहले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बाराबंकी (सुरक्षित) संसदीय क्षेत्र से प्रियंका को उनकी विवादित छवि के कारण टिकट नहीं मिल पाया था, जबकि प्रियंका 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट से जीती थीं। टिकट कटने से आहत रावत ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से टिकट पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भाजपा ने जब आडवाणी, जोशी और सुमित्रा महाजन जैसी हस्तियों के टिकट काट दिए तो मैं तो एक दलित महिला हूं। ऐसे में सवाल यही है कि क्यों प्रियंका अचानक से भाजपा की आंख का तारा बन गई हैं तो कुछ लोग इसके पीछे की वजह उनके इनकम टैक्ट ऑफिसर पति को मान रहे हैं जिनकी दिल्ली में पोस्टिंग है और उनके भाजपा के कई बड़े नेताओं से निकट के संबंध हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी में 8 दलित नेताओं को जगह दी है जिसमें पासी जाति से संबंध रखने वाली प्रियंका सबसे युवा थीं। यह तब हुआ जबकि 219 में लोकसभा का टिकट कटने से नाराज भाजपा की सांसद प्रियंका रावत ने बगावती सुर अख्तियार कर रखे थे। प्रियंका का अपना कोई खास जनाधार भी नहीं है। हां, विवादों से उनका गहरा नाता है। एक बार प्रियंका रावत को दिल्ली एयरपोर्ट पर जांच के दौरान पर्स में रखी छुरी के साथ पकड़ा गया था। इस पर अपनी गलती मानने की बजाय प्रियंका रावत एयरपोर्ट के स्टाफ को ही धमकाने लगी थीं। इसी प्रकार दिसंबर 2017 में सांसद प्रियंका सिंह रावत की वीडियो एक प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी को कथित रूप से धमकाते हुए कैमरे में कैद हुई थी। इस घटना का फुटेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। घटना सफदरगंज थाना क्षेत्र के चौला गांव में सरकारी जमीन पर राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर गांव वालों से हुए विवाद से जुड़ी थी। तब भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित ने सांसद प्रियंका रावत की शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। सात बिंदुओं पर की गई शिकायत में आईएएस एसडीएम सिरौलीगौसपुर अजय कुमार द्विवेदी को धमकी दिए जाने का प्रकरण भी शामिल था।

वहीं एक बार सांसद रहते प्रियंका रावत पर एक पुलिस अधिकारी की खाल उतरवाने की धमकी देने का भी आरोप लगा था। उन्होंने न केवल पुलिस अधिकारी को यह धमकी दी बल्कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह धमकी दोहराई जो कि कैमरे में कैद हो गई। तब की सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इनको (पुलिस अधिकारी) जितनी मलाई काटनी थी काट ली इन्होंने। यह भाजपा की सरकार है, मलाई तो क्या इनकी खाल उतार ली जाएगी अगर काम नहीं करेंगे तो। कुल मिलाकर प्रियंका रावत का विवादों से गहरा नाता रहा है। यह विवाद उनके पिछड़ा वर्ग समाज सम्मेलन के आयोजन के तौर-तरीकों में भी दिखाई दे रहा है। जब भाजपा आलाकमान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक-एक वोट के लिए रणनीति बना रहे हैं, तब न जानें क्यों प्रियंका रावत ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को मात्र 17 जातियों के बीच ही समेट दिया है, जबकि 62 और पिछड़ा समाज की जातियां भी भाजपा से मिलकर अपनी कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहती हैं। यह वह जातियां हैं जो भाजपा की मजबूत वोट बैंक मानी जाती हैं। यदि भाजपा सभी पिछड़ी जातियों को अपने बैनर तले एकजुट करने की कोशिश नहीं करती है तो यह वोट बैंक छिटक कर सपा की झोली में जा सकता है।

बहरहाल, समय रहते पार्टी आलाकमान और योगी सरकार नहीं चेती तो उसे इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। वैसे भी ऐसे ही विवादित फैसलों के चलते योगी सरकार और संगठन की साख पर बट्टा तो लग ही रहा है। समाज के कई वर्गों के वोटरों के बीच भी मैसेज सही नहीं जा रहा है। पहले गुजरात के पूर्व नौकरशाह अरविंद शर्मा को जिस तरह से अपमानित किया गया था, अब वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य आहत नजर आ रहे हैं। केशव के लिए यह स्थिति काफी परेशान करने वाली होगी कि उनके रहते पिछड़ों को मनाने की जिम्मेदारी किसी दलित नेता की कंधों पर डाली जाए। इसका क्या रिएक्शन होगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, परंतु इस तरह के फैसलों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख पर भी चोट तो पहुंच ही रही है। वैसे भी योगी-केशव प्रसाद मौर्य के बीच संबंध कभी अच्छे नजर नहीं आते हैं।

● इन्द्र कुमार

कांग्रेस के दर्द की दवा क्या?

एक दिन गुजरता नहीं, कि जब तक कांग्रेस संभलती हुई दिखती है तब तक एक नई गुटबाजी सामने आ जाती है। 15 सालों के बाद बंपर बहुमत के साथ सत्ता में आई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां काफी समय से नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। जून 2021 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ढाई साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे, इसके बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की बात सामने आई। सिंहदेव खेमे ने दावा किया कि बघेल सरकार द्वारा अपना आधा कार्यकाल पूरा करने के बाद ही 2018 में आलाकमान ने उन्हें पद सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी। इस कार्यकाल के पूरा होने के बाद सिंहदेव खेमे के विधायक सक्रिय हो गए हैं। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में कुर्सी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी को फिलहाल इस दर्द की दवा नहीं मिल रही है।

अगस्त में जब सिंहदेव अपना पक्ष लेकर दिल्ली पहुंचे तो मामला गरमा गया और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बघेल तथा सिंहदेव को तलब किया। दोनों नेताओं के साथ राहुल गांधी ने लंबी बातचीत की। उन्होंने अलग-अलग भी दोनों नेताओं से बात की। बघेल से आखिरी दौर की वार्ता के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वह एक सप्ताह बाद खुद रायपुर जाकर सारा विवाद सुलझा देंगे लेकिन उसके बाद कई सप्ताह बीत गए पर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ नहीं गए। भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता का विषय क्या हो सकता है कि भारत में कोई सशक्त विरोधी दल नहीं है। इस खाली जगह को कांग्रेस भर सकती थी लेकिन वह निरंतर कमजोर होती जा रही है। भाजपा के बाद यही एकमात्र अखिल भारतीय पार्टी है लेकिन इसकी प्रांतीय सरकारें और पार्टी शाखाएं भी अस्थिरता की शिकार हो रही हैं। पंजाब का मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है और राजस्थान व छत्तीसगढ़ के बारे में लगातार अफवाहें उड़ती रहती हैं। संसद के दोनों सदनों में उसकी संख्या और गुणवत्ता इतनी घट गई है कि हमारा लोकतंत्र मूक-बधिर-सा हो गया है।

कांग्रेस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी रही है। इसी को श्रेय दिया जाता है कि इसने भारत को आजाद करवाया और इसने ही सारी दुनिया को अहिंसक आंदोलन की राह दिखाई। आज भी संसद और विधानसभा में इसका अस्तित्व चाहे सिकुड़ गया हो लेकिन भारत के लगभग हर जिले में इसके कार्यकर्त्ता मौजूद हैं। लेकिन इसकी दुर्दशा देखकर शंका होती है कि इस पार्टी की स्थापना 1885 में विदेश में जन्मे एओ ह्यूम ने की थी, कहीं इसका विसर्जन भी विदेश में जन्मी सोनिया गांधी के हाथों तो नहीं होगा? भारतीय लोकतंत्र के लिए यह इंदिरा गांधी के आपात्काल से भी अधिक खतरनाक घटना होगी।

यदि हम पिछले 50-55 साल के इतिहास को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो हमें पता चलेगा कि कांग्रेस कोई संकरा संगठन नहीं था। वह एक विशाल मंच था। एक ऐसा मंच जिसमें विविध, विभिन्न और विरोधी विचारों के लोग एकजुट होकर आजादी के लिए लड़ते रहे। आजादी के बाद भी नेहरु और शास्त्री-काल में पार्टी में यह वैचारिक और वैयक्तिक सहिष्णुता बनी रही लेकिन अब कांग्रेस के पास क्या है? विचार के नाम पर उसके पास शून्य है। न तो वह अपने को समाजवादी कह सकती है, न पूंजीवादी और न राष्ट्रवादी! उसकी अपनी न तो कोई राष्ट्रीय दृष्टि है और न ही अंतरराष्ट्रीय दृष्टि!

जहां तक नेतृत्व का सवाल है, उसका स्वरूप बिल्कुल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हो गया है। क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी रही है, सभी पार्टियां इसी की नकल पर चलने लगी हैं। यदि कांग्रेस मां-बेटा पार्टी है तो उसकी टक्कर में भाई-भाई पार्टी है। प्रांतों में बाप-बेटा पार्टी, चाचा-भतीजा पार्टी, बुवा-भतीजा पार्टी, पति-पत्नी पार्टी, साला-जीजा पार्टी आदि खड़ी हो गई हैं। यानी हमारे देश में पार्टियों ने अपने आंतरिक लोकतंत्र को सहज बिदाई दे दी है। कांग्रेस से ही अन्य दलों ने भी सीखा है कि कोई भी सांसद संसद में अपनी स्वतंत्र राय प्रकट नहीं करता। उससे कोई पूछे कि तुम किसके प्रतिनिधि हो? अपने मतदाताओं के या अपनी पार्टी के? तुम्हें संसद में चुनकर किसने भेजा है? जनता ने या तुम्हारी पार्टी ने? जब हमारे सांसद अपनी पार्टी की बैठकों में ही खुलकर नहीं बोलते हैं तो वे संसद में कैसे बोलेंगे?

इस प्रवृत्ति का असर मंडिमंडल की बैठकों में भी साफ-साफ दिखाई देता है। यदि ऐसा नहीं होता तो 1975 में आपात्काल थोपने का कोई एक मंत्री तो विरोध करता। यदि नोटबंदी पर मंत्रिमंडल में खुलकर बहस होती तो क्या इतनी नादानी का फैसला कोई सरकार कर सकती थी? इंदिरा गांधी के जमाने में चली यह परंपरा आज भी कांग्रेस में ज्यों की त्यों कायम है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

नेताओं की बोलती बंद करने से नहीं निकलेगा समाधान

जब कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर अगस्त 2020 में कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई तो राहुल गांधी की डांट-फटकार ने सभी वरिष्ठ नेताओं की बोलती बंद कर दी। उसके बाद सालभर गुजर गया लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष पद अब भी अधर में लटका हुआ है। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष की व्हीलचेयर पर बैठी हुई हैं और राहुल और प्रियंका उसे धकाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में योग्य नेताओं का अभाव है। ऐसे दर्जनभर कांग्रेसी नेता हैं जो कांग्रेस को इस लकवाग्रस्त स्थिति से मुक्ति दिला सकते हें लेकिन वे भी हकला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मुंह में जुबान नहीं है लेकिन जो जिंदगी भर अपने मालिकों को झुकझुक कर सलाम बजाते रहे, अब उनके सामने खम ठोक कर वे कैसे खड़े होंगे? उर्दू शायर मोमिन के शब्दों में 'इश्के-बुतां में जिंदगी गुजर गई मोमिन! आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमां होंगे?' कांग्रेस में इस समय कोई शरद पवार और ममता बेनर्जी जैसा नहीं है, जो पारिवारिक नेतृत्व को चुनौती दे और अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ले। जो भी योग्य नेता हैं, वे बिखरती कांग्रेस को देखकर बेहद दुखी हैं लेकिन यह उनकी मजबूरी है। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन परेशान हैं।

वसुंधरा को किनारे लगाने की तैयारी

भाजपा आलाकमान की निगाहें क्या अब पूर्व मुख्यमंत्री तथा राज्य में पार्टी की निर्विवाद नेता वसुंधरा राजे पर ज्यादा ही तीखी होने लगी हैं? यह सवाल 'जन आशीर्वाद यात्रा' के दौरान केंद्रीय मंत्री तथा पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव के भाषण से नए सिरे से उठ खड़ा हुआ है। भूपेंद्र यादव राजस्थान के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करीबी टोली के सदस्य हैं। लेकिन, वसुंधरा राजे गुट की तरफ से भी मुकाबले की पुख्ता तैयारी के संकेत उभर रहे हैं।

दरअसल, यादव ने पिछले दिनों एक रैली में कहा था, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 2023 में सतीश पूनिया के नेतृत्व में तीन चौथाई बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। उसके बाद वसुंधरा समर्थकों की भौंहें तन गई हैं। वसुंधरा के कट्टर समर्थक, राज्य के पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत कहते हैं, राज्य में तालमेल अच्छा नहीं है, लेकिन, आलाकमान को झुकना पड़ेगा। राजे की लोकप्रियता का भाजपा में कोई विकल्प नहीं है। हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। पूनिया के नेतृत्व में पार्टी का क्या हाल है, यह सभी ने उपचुनाव, पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव में देख लिया है।

दरअसल, अरसे से राजे गुट को मलाल है कि उनकी नेता को नजरअंदाज किया जा रहा है और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शायद नए चेहरे को मौका दिया जाए। इसमें प्रमुख दावेदार मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और भूपेंद्र यादव को माना जा रहा है। यही कारण है कि यादव ने 'जन आशीर्वाद यात्रा' के जरिए राजनीतिक नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। हालांकि, सतीश पूनिया का मानना है, राज्य में मौका हर किसी को मिलना चाहिए। पार्टी का सर्वमान्य चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं और मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। पूनिया कहते हैं, अलग से किसी भी तरह का संगठन बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है।

लेकिन, राजे समर्थकों ने अब 'टीम वसुंधरा' नाम से संगठन बनाने शुरू कर दिए हैं। छोटे-छोटे स्तर पर कार्यालय खोलकर राजे के पक्ष में अभी से माहौल तैयार किया जा रहा है। जनवरी में भी 'वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच' के गठन का ऐलान किया गया था। तब पूनिया ने कहा था, ये तीर-कमान सोशल मीडिया पर ही चल रहे हैं। संगठन में शामिल कार्यकर्ता भाजपा के नहीं है। लेकिन, अब 'टीम वसुंधरा' ने पार्टी के भीतर की कलह को उजागर कर दिया है।

लंबे समय बाद भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुईं वसुंधरा

भाजपा आलाकमान के निर्देश पर राजस्थान में पार्टी के नेताओं के बीच चल रही खींचतान समाप्त करने के प्रयास तेज हो गए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में पहुंचीं। वसुंधरा ने यहां राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया से नाराजगी के कारण वसुंधरा लंबे समय से राज्य की सक्रिय गतिविधियों से दूर थी। आलाकमान के निर्देश पर सतीश पूनिया बैठक से पहले वसुंधरा के घर जाकर लंबी मुलाकात की। गौरतलब है कि इससे पहले कुंभलगढ़ में हुए भाजपा के चिंतन शिविर में वसुंधरा राजे नहीं शामिल हुई थीं। इस चिंतन शिविर में शामिल हुए एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं को आमजन तक पहुंचाने की योजना बनाई गई। इस नेता ने बताया कि दो दिन चले शिविर में वसुंधरा भी मुद्दा रही। कांग्रेस के साथ वसुंधरा को लेकर लगभग प्रत्येक नेता ने संतोष के समक्ष व्यक्तिगत मुलाकात में अपनी बात रखी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के अतिरिक्त शिविर में शामिल होने वाले अधिकांश नेता वसुंधरा विरोधी खेमे के थे। शिविर में आमंत्रित नहीं किए गए उदयपुर संभाग के कुछ नेताओं ने वसुंधरा को पार्टी के लिए जरूरी बताया। इन नेताओं ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों से अलग से मुलाकात की थी।

प्रदेश भाजपा ने इसे संगठन विरोधी गतिविधि बताते हुए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को रिपोर्ट भेजी है। लेकिन राजावत कहते हैं, अरुण सिंह जानते हैं कि शक्ति किसके पास है। उम्मीद है, दिल्ली इस बात को जल्द समझेगी।

पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने तो बीते दिनों मंच से ही वसुंधरा राजे को अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। भाजपा से निष्कासित और राजे के कट्टर समर्थक शर्मा ने अपने जन्मदिन पर जुटी भारी भीड़ के सामने अलवर के बानसूर से 'मिशन वसुंधरा राजे 2023' का ऐलान कर दिया। शर्मा को इसी साल जुलाई में पार्टी विरोधी बयान देने के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। शर्मा ने कहा था, पार्टी के प्रदेश नेता कार्यालय में बैठकर पार्टी चला रहे हैं, वे गांवों में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में से दो पर मिली हार के लिए पूनिया को जिम्मेदार ठहराया था।

भाजपा में राजे और पूनिया के समर्थक पोस्टर से एक-दूसरे की तस्वीर हटा रहे हैं। पहले पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर से वसुंधरा को गायब कर दिया गया। उसके बाद वसुंधरा समर्थकों ने राजे के पोस्टर से पूनिया को गायब कर दिया। इस विवाद पर पहली बार खुद वसुधंरा राजे ने झालावाड़ में चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोग मुझे याद करते हैं। पोस्टर क्या करेगा मेरा? अब राजे समर्थकों ने ऐलान कर रखा है कि दिल्ली में मोदी हैं तो जयपुर में वसुंधरा। राज्य में मेवाड़ इलाके की वल्लभनगर और धरियावाद में कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं। यहां भाजपा हारती है तो राजे समर्थकों को मौका पूनिया के खिलाफ एक और मिल सकता है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

455 फीसदी बढ़ा ड्रग्स का बाजार

देश में महाराष्ट्र ड्रग्स का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। बॉलीवुड में ड्रग्स की लत ने इसे और बढ़ा दिया है। एक अनुमान के तहत बॉलीवुड का हर चौथा व्यक्ति ड्रग्स का आदी है। अभी हाल ही में एनसीबी ने मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में एक क्रूज पोत से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए जाने के सिलसिले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और सात अन्य को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आर्यन खान के अलावा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, नूपुर सारिका, इसमीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा के तौर पर हुई है। आर्यन खान, धमेचा और मर्चेंट को यहां एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। लेकिन जमानत नहीं मिली। अब तक तीन-चार बार की सुनवाई के बाद भी जमानत नहीं मिली है। इसी से मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है।

गौरतलब है कि सुशांत सिंह की मौत के बाद बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। तभी से एनसीबी ने मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में सतर्कता बढ़ा दी थी। एनसीबी को लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र सहित देशभर में ड्रग्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सूत्र बताते हैं कि संगठित तरीके से ड्रग्स की तस्करी का कारोबार देश में फैल रहा है। इन तस्करों को राजनीति का भी संरक्षण मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर एनसीबी की सख्त कार्रवाई हुई है। पिछले साल बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीबी ने कई पैडलर्स को गिरफ्तार करके कड़ी पूछताछ की है। वहीं, इस अपराध से जुड़े अपराधियों को सजा देने के मामले पिछले 4 सालों में 11 प्रतिशत तक बढ़े हैं। 2020 में नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े अपराधों में 81.6 प्रतिशत अपराधियों को सजा मिली है। वहीं, दुनियाभर में नशे की वजह से तकरीबन दो लाख मौतें हर साल होती हैं और भारत में पिछले तीन सालों में ही ड्रग्स का बाजार 455 फीसदी तक बढ़ गया, जो कि चिंतित करने वाला आंकड़ा है।

देश के 2.1 प्रतिशत लोग गैरकानूनी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें मिजोरम पहले, पंजाब दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर हैं। 44 प्रतिशत ड्रग एडिक्ट्स नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से 25 प्रतिशत को ही इलाज मिल पाता है। करीब एक करोड़ 3 लाख लोग गांजा या चरस का सेवन करते हैं। नशा करने वाले सबसे ज्यादा लोग सिक्किम में हैं। दूसरे नंबर पर ओडिशा और लिस्ट में तीसरा नंबर दिल्ली का है।

दुनिया के मुकाबले भारत में अफीम से बनने वाले गैरकानूनी नशीले पदार्थों का सेवन ज्यादा होता है। यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016 में पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल गांजे का 6 प्रतिशत यानी लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया था। यही नहीं, साल 2017 में यह मात्रा बढ़कर 353 टन हो गई थी। वहीं, अगर चरस की बात की जाए तो 2017 में 3.2 टन चरस जब्त की गई थी। हालांकि, नशे के कारोबार का सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलग-अलग एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का अनुमान है कि भारत में इसका सालाना अवैध कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है।

पिछले तीन वर्षों में भारत में ड्रग्स का बाजार 455 फीसदी बढ़ा है। देश में ड्रग्स का बढ़ता कल्चर गंभीर समस्या बन चुका है। यूएनओडीसी के वर्ष 2015 के आंकड़ों के मुताबिक, दुनियाभर में करीब 23.4 करोड़ लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। हर साल ड्रग्स के कारण करीब 2 लाख लोग जान गंवा बैठते हैं। जुलाई 2016 में राज्यसभा में पेश किए गए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के नशे संबंधी आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन ड्रग्स या शराब के चलते 10 मौतें या आत्महत्याएं होती हैं। इनमें से केवल एक मौत पंजाब में होती है। इन आंकड़ों के मुताबिक ड्रग्स की लत से जुड़ी सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र, मप्र, तमिलनाडु और केरल में होती हैं।

अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल से हेरोइन, कोकीन और मॉर्फीन भारत के रास्ते दुनियाभर में सप्लाई की जाती है। अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां सालाना 5000 से 6000 टन अफीम पैदा होती है। अफगानिस्तान से नाटो सेनाओं की वापसी के बाद इसके उत्पादन में और बढ़ोतरी हुई है। अमेरीका और एशिया यहां की अफीम के सबसे बड़े खरीदार हैं। 2016 में महाराष्ट्र में पुलिस ने 18.5 टन एफेड्रिन बरामद की थी। ब्लड प्रेशर को कम करने वाली इस दवा का इस्तेमाल नशे के लिए भी किया जाता है।

● बिन्दु माथुर

हेरोइन की तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया था कि साल 2017 में देशभर से करीब 3.6 लाख किलो नशीली दवा जब्त की गई थी। इसमें बड़ी मात्रा में गांजा मिला है, लेकिन हेरोइन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2017 में देशभर से 2551 किलो अफीम, 2146 किलो हेरोइन, 3.52 लाख किलो गांजा, 3218 किलो चरस और 69 किलो कोकेन बरामद हुई थी। वर्ष 2013 के बाद कोकेन की ये सबसे बड़ी मात्रा बरामद हुई थी। कोकेन को हाई प्रोफाइल पार्टी ड्रग्स माना जाता है। इसलिए इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसकी तस्करी मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका से होती है।

लालू के घर में सत्ता संघर्ष

लालू यादव के घर में झगड़ा अब सारी हदें पार कर चुका है, ये तो ऐसा लगता है कि झगड़े में तेज प्रताप यादव पूरी तरह अकेले भी पड़ चुके हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को निशाना बनाने के चक्कर में बड़ी बहन मीसा भारती का भी ख्याल नहीं रखा है। सबकुछ भले ही सामने दिखाई पड़ रहा हो। सामने से नजर आ रहा हो कि दोनों भाई एक-दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन खास बात ये भी है कि दोनों में से कोई भी किसी का सीधे-सीधे नाम नहीं ले रहा है।

मीडिया के सवाल पर दोनों ही मुद्दे पर अपना-अपना पक्ष भी रख रहे हैं, लेकिन नाम कोई नहीं ले रहा है। हां, एक फर्क जरूर है और वो ये कि बड़े भाई तेज प्रताप चाहे कितने भी आक्रामक क्यों न हो चुके हों, लेकिन लालू यादव के व्यक्तित्व के बहाने छोटे होकर भी तेजस्वी यादव बड़े आराम से अपनी बात कह रहे हैं। चेहरे पर तनाव भी न दिखे ऐसी भी कोशिश होती है, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाते।

तेज प्रताप के आरोप बिलकुल सीधे-सीधे हैं। कह रहे हैं दिल्ली में उनके पिता को बंधक बना लिया गया है और करीब साल भर से उनको पटना नहीं जाने दिया जा रहा है। तेज प्रताप ये भी बताते हैं कि उनके पिता बीमार हैं, इसलिए वो उनको किसी तरह का तनाव नहीं देना चाहते, लेकिन ये आरोप जरूर लगाते हैं कि कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और लगे हाथ दोहराते भी हैं- 'मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।' ऐसा भी नहीं कि ये झगड़ा कोई हाल फिलहाल शुरू हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सब तब हो रहा है जब लालू यादव जमानत पर जेल से बाहर और पूरे परिवार के साथ हैं और ये उप्र के मुलायम सिंह यादव के परिवार और पार्टी जैसा तो कतई नहीं है।

तेज प्रताप खुद को कृष्ण और छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन तो पहले से ही बताते रहे हैं, लेकिन आपस में भी महाभारत भी शुरू हो जाएगी ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तो किसी भी तरह के राजनीतिक विवाद की संभावना को पहले ही खत्म कर दिया था, जो कसर बाकी रही वो भी बीते विधानसभा चुनावों में पूरी हो गई थी। तेज प्रताप यादव का कहना है कि उन्होंने अपने पिता लालू यादव से बात की थी और पटना चलने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तेज प्रताप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उसकी वजह से आरजेडी से लोग दूर होने लगे हैं। 'पहले हमारे घर का दरवाजा खुला रहता था। आप आउटहाउस में बैठे रहते थे और जनता से मिलना-जुलना होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, रस्सा लगा दिया गया है... जनता हमसे दूर हो गई है।' तेज प्रताप के ऐसे आंकलन का जो भी आधार हो, लेकिन एक सीट से ही सही लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। आरजेडी के बाद भाजपा का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का। तेज प्रताप यादव ने अपने ही परिवार पर अपने पिता को बंधक बना लेने का बहुत बड़ा आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव का सीधा-सीधा इल्जाम है, 'मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। चार-पांच लोग हैं पार्टी में और वो राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देखना चाहते हैं। उनका नाम लेने या बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई उनको जानता है। करीब सालभर पहले वो जेल से रिहा हुए थे लेकिन दिल्ली में बंधक बने हुए हैं।'

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जैसे ही दिल्ली से पटना पहुंचते हैं मीडिया उनका पक्ष जानना चाहता है। मीडिया की तरफ से तेज प्रताप के आरोपों को दोहराया जाता है। तेजस्वी यादव बड़े आराम से सुनते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। तेजस्वी यादव न तो आरोपों का जिक्र कर खारिज करने की कोशिश करते हैं, न अपनी तरफ से कोई और बात जोड़ते हैं, बल्कि नपे-तुले शब्दों में अपनी बात कहते हैं और ये पूरी तरह राजनीतिक बयान होता है। तेजस्वी यादव मीडिया से कहते हैं, 'देखिये अब... हम इतना जरूर कह सकते हैं... लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे... रेल मंत्री रहे... दो-दो प्रधानमंत्री इन्होंने बनाया... आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया... तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं करता।' सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप की प्राथमिकता बदल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी को अर्जुन बताते-बताते तेज प्रताप ये भूल गए हैं कि वो खुद को कृष्ण मानते रहे हैं, लेकिन जो अभी-अभी अपने जिस राजनीतिक फोरम का तेज प्रताप ने रजिस्ट्रेशन कराया है, चुनाव निशान तो उसके लिए बांसुरी ही चुना है।

तेज प्रताप के निशाने पर अब भी आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही रहते हैं और अध्यक्ष बनने का सपना देखने को लेकर तेज प्रताप अगर कभी नाम लेते हैं तो जगदानंद सिंह से ही काम चलाते हैं। भले ही उनके निशाने पर तेजस्वी यादव हुआ करते हों। तेज प्रताप की ताजा मुश्किल ये है कि अब मीसा भारती ने भी उनका सपोर्ट करना छोड़ दिया है और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तेज प्रताप के पिता लालू यादव को बंधक बनाने के दायरे में मीसा भारती भी स्वाभाविक तौर पर शुमार हो जा रही हैं। बल्कि, इसलिए क्योंकि तेज प्रताप के साथ जाना मीसा भारती के लिए घाटे का सौदा हो सकता है।

● **विनोद बक्सरी**

भाई-बहन में भी दरार

देखने में तो यही आया है कि शुरू से ही तेज प्रताप और मीसा भारती दोनों भाई-बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते आए हैं, लेकिन बीच में जब राजनीति आड़े आने लगती है तो रिश्ते पीछे यूं ही छूट जाते हैं। बीती बातों को याद करें तो 2015 में जब लालू यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन की जीत हुई तो तेजस्वी को तो डिप्टी सीएम बनना ही था, लेकिन शुरू में तेज प्रताप का मंत्री बनना नहीं तय था। तभी सुनने में आया था कि मीसा भारती ने लड़कर तेज प्रताप को भी मंत्री बनवाया था और जब मीसा भारती के राज्यसभा जाने की बारी आई तो ठीक वैसे ही तेज प्रताप भी खंभे की तरफ पीछे खड़े हो गए। क्योंकि तब ये भी सुनने में आया था कि लालू यादव, बेटी मीसा की जगह पत्नी राबड़ी देवी को राज्यसभा भेजना चाहते थे। चारा घोटाले में रांची जेल में सजा काट रहे लालू यादव जमानत मिलने के बाद से दिल्ली में राज्यसभा सांसद बेटी मीसा भारती के आवास पर ही रह रहे हैं। लालू यादव के पटना जाने का भी कार्यक्रम बना था जब राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना समारोह होना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। आधिकारिक तौर पर बताया तो यही गया था।

न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण जरूरी

ग्रामीण न्यायालयों के न्यायाधीश अब भी पंच

वैदिक अदालतें न्याय करते समय केवल तकनीकी या कानूनों के आधार पर ही नहीं, अपितु संदर्भानुसार मध्यस्थता और समझौते का व्यापक प्रयोग करती थीं। ग्रामीण न्यायालयों के न्यायाधीशों को तो पंच के ही पदनाम से आज भी संबोधित किया जाता है। मध्यस्थता की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें मुकदमे के दोनों पक्षों में से कोई हारता नहीं, अपितु दोनों ही अपने को विजेता मानते हैं। दोनो संतुष्ट हो जाते हैं और अपील की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ऊपर की अदालतों पर मुकदमों का बोझ नहीं बढ़ता। हमारे पास इस समय सैद्धांतिक तौर पर मध्यस्थता, सुलह तथा पंचनिर्णय के विकल्प मौजूद हैं, किंतु उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। मुहिम चलाकर उनका प्रचार-प्रसार करने तथा अदालतों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने फिर अदालती व्यवस्था में सुधार पर चर्चा शुरू की है। इस बार उन्होंने उसके भारतीयकरण पर बल दिया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि अदालती भाषा और प्रक्रिया आम आदमी के लिए इतनी दुरुह है कि वह उसे जानने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इतना ही नहीं इसका अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अपनी पांच हजार साल पुरानी पारदर्शी और उन्नत अदालती व्यवस्था होने के बावजूद हम अपने निर्णयों में विदेशी सिद्धांतों की मदद लेते हैं, जो आम आदमी की समझ में नहीं आते।

वैदिक काल में अदालतों को सभा कहा जाता था। वे स्थानीय स्तर पर एक गांव या आसपास के कुछ गांवों के विवादों का निपटारा अपने स्तर पर कर देती थीं। इस न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा इस कदर था कि बहुत कम मुकदमे ऐसे होते थे, जिन्हें राजधानी ले जाना पड़ता था, जहां दो तरह की अदालतें होती थीं। राजा की अदालत सबसे बड़ी होती थी, किंतु उसके नीचे भी एक न्यायालय होता था, जिसमें एक न्यायाधीश तथा आम नागरिकों के बीच से लिए गए कुछ लोग होते थे, जिन्हें आज की भाषा में ज्यूरी कहा जा सकता है। ज्यूरी विवेचक की भूमिका निभाते थे, जिन्हें कानून की कसौटी पर परखने के बाद न्यायाधीश निर्णय देता था। राजा की अदालत में बहुत कम मामले पहुंचते थे, क्योंकि अधिकतर लोग निचली अदालत के निर्णय से संतुष्ट हो जाते थे। राजा की सहायता के लिए परिषद होती थी, जिसमें न्यायमंत्री और निचली अदालत का प्रधान न्यायाधीश शामिल होता था। सुनवाई खुली अदालत में होती थी। उसमें राजा का उपस्थित होना जरूरी नहीं था, फिर भी उसे सदैव उपस्थित माना जाता था और सभी निर्णय उसके ही नाम से लिए जाते थे। इन न्यायालयों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां आम नागरिक की भाषा इस्तेमाल होती थी। नियम-कानून भी ऐसे होते थे, जिन्हें आम आदमी समझ सकता था। उसे समझने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं थी। पूरी प्रक्रिया मुकदमे के पक्षकारों के इर्द-गिर्द घूमती थी। इस समय सब कुछ ठीक उलटा है। इससे समूची प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं।

आज कानून की भाषा और अदालती प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें वादी कहीं दूर बेचारा सा खड़ा दिखाई देता है। न्यायाधीश, अधिवक्ता और जटिल कानून न्यायिक व्यवस्था के केंद्र में आ गए हैं। कानूनों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुझाव भी आए, किंतु उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका। मालिमथ कमेटी ने 2003 में अपनी रिपोर्ट में इस पर व्यापक अनुशंसा की थी। उसमें कहा गया था कि हर कानून में अनुसूची जोड़कर उसे स्थानीय भाषा में भी लिखकर शामिल किया जाए। उनका मत था कि इससे आम आदमी कानून की समझ विकसित कर सकेगा और उसका भरोसा बढ़ेगा। वैदिक अदालतों की दूसरी खासियत यह थी कि उनकी पहुंच सुदूर गांवों तक थी और अधिकतर मामलों का अंतिम निपटारा वहीं हो जाता था। अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रतिबद्ध लोग वहां पंचों की भूमिका में होते थे। स्थानीय परिस्थितियों और परंपराओं से वे बखूबी वाकिफ होते थे।

आज की स्थिति यह है कि सरकार और अदालतों की तमाम कोशिशों के बावजूद लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय चार करोड़ से ज्यादा मामले लंबित चल रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि यदि एक भी नया मुकदमा दायर नहीं किया जाए तब भी मौजूदा व्यवस्था में उन्हें निपटाने में सौ वर्ष लग जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए 2009 में संसद ने ग्राम न्यायालय अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अदालतों की स्थापना के लिए कानून बनाया था, किंतु उसके अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए। इसमें कुल आठ हजार न्यायालयों का गठन होना था, परंतु अब तक केवल 395 न्यायालयों की अधिसूचना जारी हो पाई है और उनमें से भी अधिकतर या तो निष्क्रिय हैं या आधे-अधूरे ढंग से काम कर रहे हैं। यदि उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो नए मामलों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। वैदिक कालीन अदालतों की एक विशेषता यह भी थी कि न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा असंदिग्ध होती थी।

उसका जीवन समाज के सामने खुली किताब की तरह होता था। यहां तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी किसी तरह की विधिक या नैतिक गलती अक्षम्य थी। ज्यूरी के आचरण के लिए कठोर नियम थे। यदि ज्यूरी का कोई सदस्य अपनी राय नहीं देता था या विधि विरुद्ध कार्य करता था तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता था। मौजूदा व्यवस्था में न्यायिक निष्पक्षता को मजबूती देने के लिए कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायपालिका ने काफी कुछ अपने हाथ में ले लिया है। अब नियुक्ति के मामले में सरकारी दखलंदाजी की संभावना नगण्य हो गई है, परंतु इसमें पारदर्शिता आवश्यक है।

● **राजेश बोरकर**

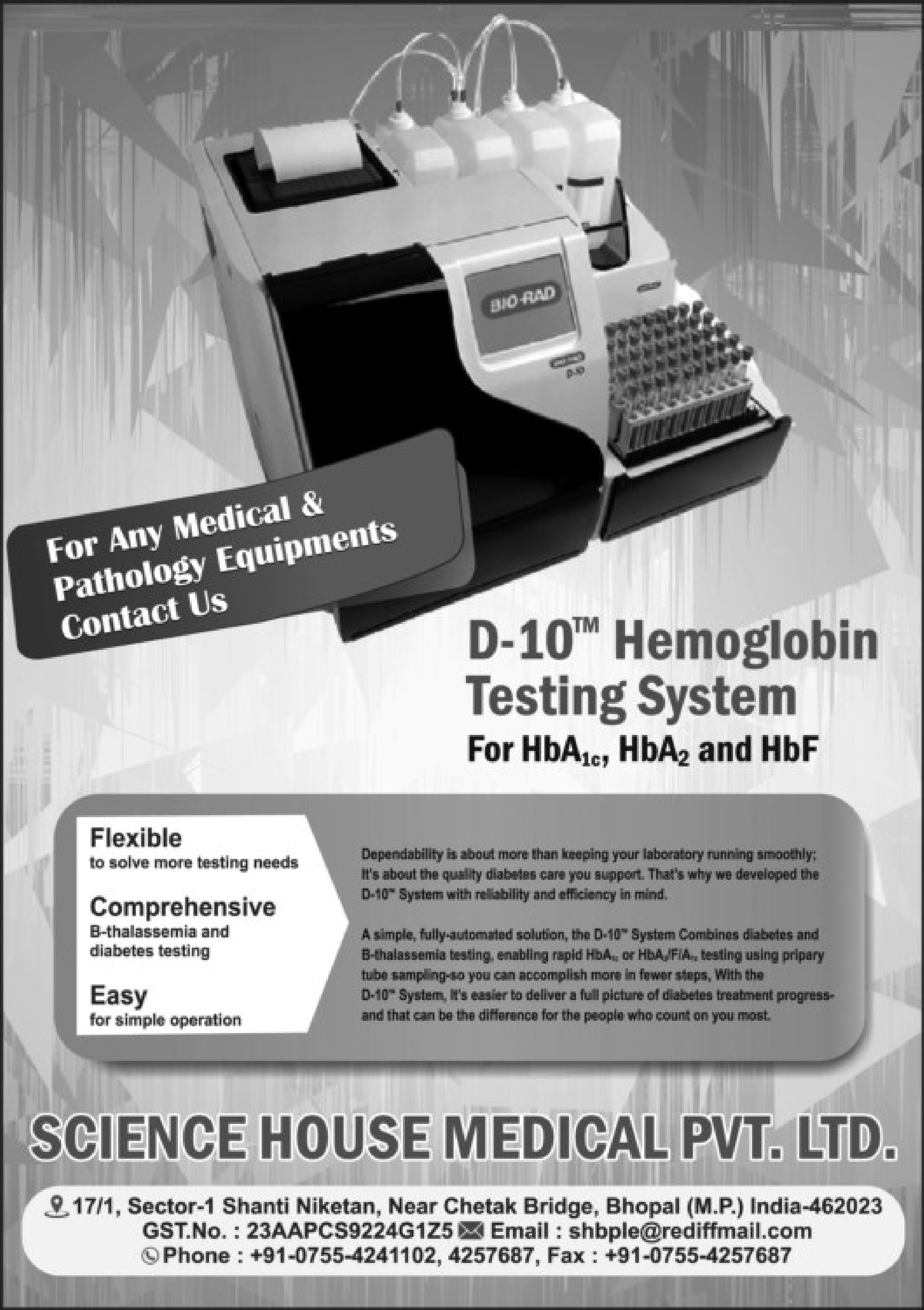
BIO-RAD
For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
D-10™ Hemoglobin
Testing System
For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF
Flexible
to solve more testing needs
Comprehensive
B-thalassemia and
diabetes testing
Easy
for simple operation
Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.
A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.
SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.
17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

दबाव में इमरान

इमरान खान जबसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, विवाद उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। हर बार नया विवाद खड़ा हो जाता है, जिसमें वे फंस जाते हैं। ताजा मामला पैंडोरा पेपर्स लीक का है, इस मामले में इमरान के करीबी लोग फंसे हैं। अब विपक्ष ने इमरान के खिलाफ लामबंदी तेज कर दी है।

अभी बीते दिनों ही अमेरिका में भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मुंह की खा चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला पैंडोरा पेपर्स लीक होने के बाद मचे सियासी घमासान का है। पैंडोरा पेपर्स में दुनिया भर में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के गुप्त वित्तीय लेन-देन का हिसाब-किताब है। जिसे लेकर वो हुआ है, जिसके बारे में इमरान खान या उनकी सरकार ने शायद ही कभी कल्पना की हो। मामले में दिलचस्प ये है कि इस खुलासे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबियों का तो नाम है ही। साथ ही विपक्ष के लोगों और सेना के कई आला अधिकारियों समेत 700 लोगों के नाम सामने आए हैं। बात प्रमुख नामों की हो तो इमरान सरकार में वित्त मंत्री शौकत तारिन, जल संसाधन मंत्री मूनिस इलाही, सांसद फैसल वावड़ा, उद्योग और उत्पादन मंत्री खुसरो बख्तियार वो लोग हैं जो पैंडोरा पेपर्स के जाल में फंसे हैं।

मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पैंडोरा पेपर्स लीक सबकी जुबान पर है। तो आखिर पैंडोरा पेपर है क्या? पैंडोरा पेपर 14 कॉरपोरेट सर्विस फर्म्स की ओर से लीक हुईं 1.19 करोड़ गुप्त फाइलें हैं। दिलचस्प ये है कि फाइलों में इन 14 सर्विस फर्म्स की ओर से खड़ी की गई 29,000 ऑफ-द-शेल्फ कंपनियों और प्राइवेट ट्रस्टों के नाम हैं, जिनके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य टैक्स चोरी था। जो बात आश्चर्य में डालती है वो ये कि इन ऑफ-द-शेल्फ कंपनियों को रिकॉर्ड छिपाने के लिए सिर्फ टैक्स हेवन देशों में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी बनाया गया था। मामले के मद्देनजर जो पेपर्स आईसीआईजे की तरफ से सामने लाए गए हैं, उनमें प्राइवेट ट्रस्टों के जरिए बड़े लोगों की विदेशों में जमा संपत्ति और निवेश से जुड़े खुलासे किए गए हैं। इनमें कैश, शेयर्स और रियल एस्टेट में किए गए निवेश की भी जानकारी शामिल है। बात बीते दिनों की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) ने 'पैंडोरा पेपर' का राज फाश किया है। जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के रिश्तेदार इशाक डार, पीपीपी के शरजील मेमन का भी नाम है। इसके अलावा कुछ रिटायर फौजी, बिजनेसमैन और मीडिया कंपनी के मालिकों के नाम भी पैंडोरा पेपर में सामने आए हैं।

पाकिस्तान में गड़बड़ घोटाला कोई आज का नहीं है बेईमानी और टैक्स चोरी के इस खेल की शुरुआत पाकिस्तान में 5 साल पहले तब हुई जब मुल्क का निजाम नवाज शरीफ के पास था। पूर्व में हम पनामा पेपर लीक से अवगत हो चुके हैं जिसमें नवाज शरीफ समेत दुनियाभर के कई प्रमुख लोगों के नाम टैक्स चोरी के मामले में सामने आए थे। इसे चुनाव के दौरान पाकिस्तान में इमरान खान ने खूब कैश किया और जनता से तमाम तरह के कसमें-वादे किए। माना जाता है कि इन्हीं वादों और नए पाकिस्तान के लॉलीपॉप से जनता इमरान के जाल में फंसी और अंत में वो देश के प्रधानमंत्री बने। इमरान के प्रधानमंत्री बनने से जनता को तो कोई फायदा नहीं हुआ हां लेकिन जो इमरान खान के करीबी थे उनके वारे न्यारे जरूर हुए।

लीक हुए पेपर्स में इस बात का जिक्र है कि इमरान खान के करीबियों के परिजनों ने गुपचुप तरीके से धन विदेशों में निवेश किया। ध्यान रहे इन टैक्स चोरों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने मौके बेमौके इमरान खान को वित्तीय मदद दी। चूंकि मामला पाकिस्तान समेत पूरा हाईलाइट है इसलिए मामले पर इमरान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि जिन लोगों का नाम पैंडोरा पेपर्स लीक में आया है उनकी जांच की जाएगी। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर उचित एक्शन भी लिया जाएगा। इमरान ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वो इस जरूरी मसले को जलवायु परिवर्तन की तरह ही गंभीरता से लें।

चूंकि इस मामले में सीधे-सीधे इमरान खान पर आरोप लग रहे हैं इसलिए उन्होंने ट्विटर पर सफाई दी है। इमरान ने ट्वीट किया है कि, 'हम पैंडोरा पेपर का स्वागत करते हैं जिसने गलत तरह से संपत्ति इकट्ठा करने वाले अमीरों का सच उजागर किया है, टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार किया है और वित्तीय हेवंस में हवाला के रास्ते पैसा पहुंचाया है। वहीं इमरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एफएसीटीआई का भी जिक्र किया जिसका दावा है कि करीब 7 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति चोरी करके विदेशों में जमा की गई है।

● ऋतेन्द्र माथुर

इमरान खान के करीबियों पर लग रहा निशाना

बहरहाल क्योंकि पैंडोरा पेपर्स लीक मामले में निशाना सीधे-सीधे इमरान खान के करीबियों पर लग रहा है। तो माना ये भी जा रहा है कि इस मामले की आंच इमरान खान और उनकी कुर्सी को भी प्रभावित करेगी। पैंडोरा पेपर्स लीक मामले को लेकर जैसा घमासान मचा है कहना गलत नहीं है कि इमरान खान को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ सकती है। विदेशों में जमा करीबियों की रकम इमरान को कितने कष्ट देगी इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा लेकिन मामले के बाद ये कहना भी गलत नहीं है कि टैक्स चोरी के लिए विदेशों की आड़ लेने वाले इमरान के करीबियों ने बता दिया है कि अपना फायदा सर्वोपरि है। मुल्क और ईमानदारी की बड़ी-बड़ी बातें जाएं भाड़ में।

संकट में चीन

चीन वर्तमान में तीन गंभीर संकटों से एक साथ जूझ रहा है। पहला, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों में ढांचागत परियोजनाएं निरस्त की जा रही हैं। दूसरा, रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड पर वित्तीय संकट आ गया है। तीसरा, बिजली के उत्पादन में कमी आ रही है। इससे शहरों में पावर कट किए जा रहे हैं। इन तीनों में बीआरआई का संकट बड़ा है। बीआरआई को चीन ने अपनी अतिरिक्त या सरप्लस पूंजी के निवेश के लिए बनाया था। पिछले 20 वर्षों में चीन के निर्यात ऊंचे रहे हैं और घरेलू बचत दर भी ऊंची रही है। इन मदों से अर्जित रकम को उसे कहीं न कहीं निवेश करना था। इसके लिए चीन ने बीआरआई योजना को बनाया। इसके तहत उसने विश्व के तमाम देशों को विभिन्न बुनियादी संरचना खड़ा करने के कर्ज दिए। विश्व बैंक ने 2019 में बीआरआई का अध्ययन किया। उसने पाया कि इसके तहत बनाई जा रहीं परियोजनाओं से स्थानीय देशों को लाभ हो सकते हैं।

डूब सकती है चीन की अर्थव्यवस्था

चीन के संकट के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं। बीआरआई में यदि चीन ने अपनी परियोजनाओं का सही आर्थिक मूल्यांकन कराकर घटिया परियोजनाओं को निरस्त कर दिया और केवल सुदृढ़ परियोजनाओं को ही बढ़ाया तो बीआरआई सफल हो जाएगी, अन्यथा डूबेगी। एवरग्रैंड जैसी कंपनियां यदि अपनी घटिया संपत्तियों को बेचकर सुदृढ़ हो गईं तो चीन वित्तीय संकट से बच जाएगा। इसके विपरीत यदि चीन ने बड़ी कंपनियों के वित्तीय दुराचार पर अंकुश नहीं लगाया तो उसकी अर्थव्यवस्था डूबेगी।

चीन से यूरोप के बीच बिछाई जा रही रेललाइन के कारण कजाखिस्तान और पोलैंड में विनिर्माण के बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बीआरआई में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। अक्सर ज्यादा लाभ दिखाकर परियोजनाओं को स्वीकृत करा लिया जाता है। इसलिए तमाम देश इससे पीछा छुड़ाने लगे हैं। पहले मालदीव में चीन समर्थक प्रोग्रेसिव पार्टी द्वारा बीआरआई का समर्थन किया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों वहां हुए चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी हार गई और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जीती, जो कि बीआरआई का विरोध करती है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने बीआरआई को उपनिवेशवाद का नया रूप बताया है। म्यांमार ने क्यौकप्यू बंदरगाह परियोजना को निरस्त कर दिया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने भी परियोजनाओं का रूप बदलने का आग्रह किया है। स्पष्ट है कि बीआरआई के लाभ होने के बावजूद इसमें कई खामियां हैं। यदि चीन इनको दूर करने में सफल होता है तो बीआरआई आगे बढ़ेगी, अन्यथा इसके डूबने की आशंका है। भारत को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए, अन्यथा हमारा माल विश्व बजार में चीन की तुलना में महंगा पड़ने लगेगा।

चीन का दूसरा संकट एवरग्रैंड कंपनी का है। इसके पीछे चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग का मौलिक विचार है। उन्होंने कहा है कि कंपनियों के लाभ की तुलना में प्रदूषण, असमानता और वित्तीय अस्थिरता को दूर करना ज्यादा जरूरी है। इसी के चलते उन्होंने एवरग्रैंड कंपनी द्वारा अधिक ऋण लेने पर अंकुश लगाया है। उन्होंने नई वित्तीय नीति बनाई है, जिसके अंतर्गत किसी भी कंपनी को तीन मदों पर आंका जाता है। पहला यह कि लिए गए ऋण के सामने उसके पास संपत्ति कितनी है? दूसरा यह कि उसके पास अल्पकालीन कर्ज की तुलना में नगद कितनी है? तीसरा यह कि उसके द्वारा कुल लिए गए ऋण की तुलना में उसकी अपनी पूंजी कितनी है? यदि कोई कंपनी किसी एक बिंदु पर भी फेल हो जाती है, तो बैंकों द्वारा उसे ऋण नहीं दिया जा सकता। एवरग्रैंड ने तमाम परियोजनाओं को पूरा किया है, लेकिन कोविड संकट के कारण उसकी ओर से बनाए गए फ्लैटों की बिक्री कम हो गई। इसलिए भी एवरग्रैंड संकट में आ गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन की सरकार ने सरकारी इकाइयों को आदेश दिया है कि वे एवरग्रैंड की परियोजनाओं को खरीद लें। जिस प्रकार अपने देश में संकटग्रस्त यस बैंक का अधिग्रहण सरकारी बैंक द्वारा किया गया, उसी प्रकार चीन की सरकारी कंपनियां एवरग्रैंड की संकटग्रस्त परियोजनाओं को खरीदकर उस कंपनी को डूबने से बचाने का प्रयास कर रही हैं।

देखा जाए तो चीन की सरकार ने एवरग्रैंड को सरकारी ऋण देकर बचाने का प्रयास नहीं किया है। दोनों विधाओं में मौलिक अंतर है। 2008 में अमेरिका में जब जनरल मोटर्स कंपनी संकट में आ गई थी, तो अमेरिकी सरकार ने जनरल मोटर्स को और ऋण देकर बचाया था। चीन की सरकार ने एवरग्रैंड को इस प्रकार का ऋण देकर बचाने से इंकार कर दिया और उसे मजबूर किया कि वह अपनी कुछ संपत्तियों को बेचकर अपने ऋण को कम करे। ऐसा करने से एवरग्रैंड के बचे रहने की संभावना बढ़ जाएगी और चीन की सरकार के ऊपर अनावश्यक वित्तीय भार भी नहीं आएगा। इससे चीन की अर्थव्यवस्था भी बची रहेगी। यद्यपि वर्तमान में यह प्रक्रिया संकट के रूप में दिख रही है। जैसे समय पूर्व उपचार भी बीमारी जैसा ही लगता है।

चीन का तीसरा संकट बिजली का है। चूंकि शी चिनपिंग ने प्रदूषण, असमानता और वित्तीय अस्थिरता को दूर करने का संकल्प लिया है। लिहाजा उन्होंने प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए थर्मल बिजली संयंत्रों को आदेश दिया कि वे अपने प्रदूषण स्तर को कम करें। इन नियमों का पालन न करने के कारण कई बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया गया। फलस्वरूप बिजली का उत्पादन कम हो गया। कई बिजली कंपनियों ने बड़ी आद्योगिक इकाइयों को बिजली देनी बंद कर दीं। कहीं-कहीं शहरों में पावर कट भी लागू करने पड़े हैं। देखा जाए तो चीन यह संकट अपने ऊपर स्वयं लाया है, क्योंकि वह स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन की ओर बढ़ना चाहता है। भारत की तुलना में चीन में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इसलिए चीन ने यह सख्त कदम उठाया है। इसके फलस्वरूप चीन में भी सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। ऐसा होने पर चीन शीघ्र ही इस बिजली संकट से उबर जाएगा।

● कुमार विनोद

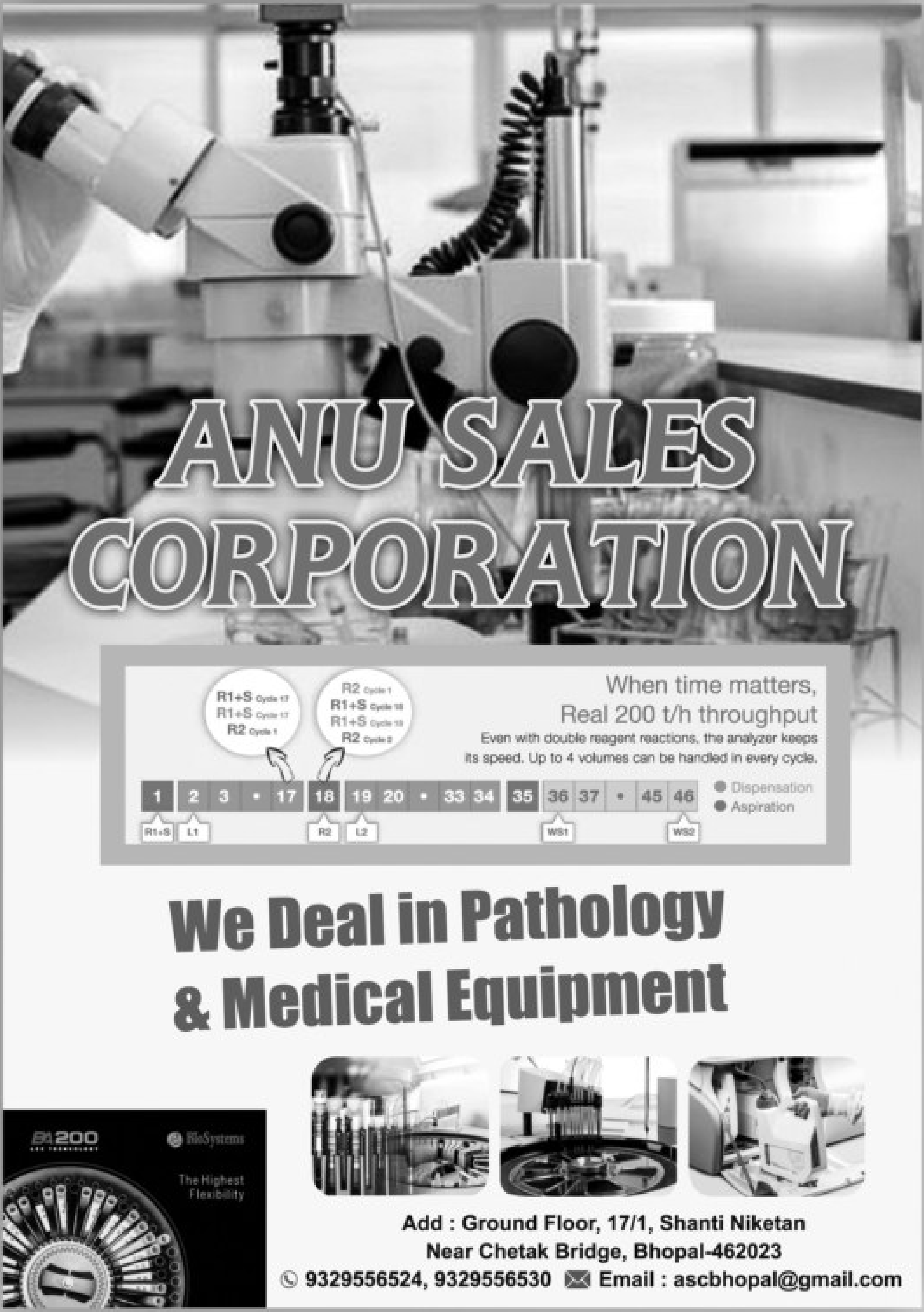
ANU SALES CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
1 2 3 • 17 18 19 20 • 33 34 35 36 37 • 45 46
R1+S L1 R2 L2 WS1 WS2
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology & Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

भूत

अचानक कुछ घसीटने की आवाज से पूनम की नींद खुल गई, नौ महीने की बेटी गहरी नींद में थी। पूनम की सहायिका उमा भी जाग गई थी। पूनम के पति किसी काम से बाहर गए थे इसलिए उमा उस रात पूनम के साथ ही रुक गई। रात के तीन बजे ऐसी अजीब आवाज आने से उमा घबरा गई। दीदी! जरूर कोई भूत-प्रेत यहां घूम रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है... उमा सहमी आवाज में कहने लगी। पूनम भी चिंतित थी मगर उमा के बात से समर्थ नहीं थी। अरे! ऐसा कुछ नहीं पगली, भूत-वूत कुछ नहीं होता।

मगर दीदी इतनी रात को ये कैसी आवाज, जो रुक ही नहीं रही। उमा अब भी डरी हुई थी। गांव में अंधविश्वास वैसे ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ था जिसका असर उमा के मस्तिष्क में भी छाया हुआ था। पूनम ने कहा- 'चलो बाहर देखकर आते हैं ये आवाज कैसी है।' 'नहीं दीदी हम नहीं जाएंगे बाहर अगर वो हमें भी घसीट कर ले गया तो!' उमा का डर चरम पर था। इस बात पर पूनम हंस पड़ी वह शहर की पढ़ी-लिखी लड़की थी और साहसी भी थी। अपनी बेटी को उमा के पास छोड़कर वह एक डंडा लेकर दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उमा बेहद डरी हुई थी बच्ची के पास दुबक कर बैठ गई। पूनम बाहर निकली और आंगन की लाइट जलाकर देखा एक कुत्ता कचरे का बैग घसीट रहा था, जिससे ऐसी आवाज आ रही थी... पूनम ने पलटकर उमा से कहा, देखा तूने आज आंगन का दरवाजा ठीक से नहीं बंद किया तभी यह भूत अंदर घुस आया, कहकर पूनम ठहाके मारकर हंसने लगी। इधर उमा घबराकर रोने लगी, दीदी! अब हमारा क्या होगा..

पूनम ने उसका हाथ पकड़ा और भूत के दर्शन कराने बाहर लेकर आई... डरते-डरते उमा बाहर आई और कुत्ते को देखकर सोच नहीं पाई अब हंसे कि रोए।

- सविता दास सवि

आधा गिलास पानी

मीनाक्षी अपनी एक आंटी से मिलने उनके घर गई। आंटी गिलास में पानी लेकर आईं। मीनाक्षी ने बोला- आंटी, इतनी प्यास नहीं है। इसे आधा कर दीजिए। आंटी बोली- पानी का क्या है। जितना पीना हो पी लो। यह कोई चाय थोड़े ही है जो आधा कप करो।

मीनाक्षी बोली- नहीं आंटी। हमारे देश में पीने योग्य पानी बहुत कम है। वेस्ट जाएगा। फिर पानी की बचत करेंगे तो बिजली की भी बचत होगी। एक पंथ दो काज। फिल्टर हाउस की मोटर, फिर हमारे घर में ऊपर ओवरहेड टैंक में पानी चढ़ाने के लिए मोटर, आरओ वाटर फिल्टर में बिजली, फिर पानी को ठंडा करने के लिए बॉटल में भरकर फ्रिज में रखने पर बिजली की जरूरत, इस प्रकार जो एक गिलास पानी आप मेरे लिए लेकर आई हैं, उसमे नदी से लेकर इस टेबल तक आने में चार जगह बिजली खर्च हुई है। इसीलिए मैं जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी लेती हूं।

आंटी बोली-मीनाक्षी, तुम तो बहुत समझदारी की बात करती हो। मैं भी अब पानी की बचत किया करूंगी। बिजली तो स्वयं ही बच जाएगी। बोलो चाय लोगी अथवा नींबू पानी। मीनाक्षी मुस्कराकर बोली-आंटी, आधा कप चाय। आंटी मुस्कराकर किचन में चाय बनाने चली गईं।

- दिलीप भाटिया

गीत

आंखें भरी - भरी सी
दिल घबराया हुआ है।
क्या बात हो गई
चेहरा मुरझाया हुआ है।
किसके लिए तड़पता
दिल तेरा बता दे।
क्या इश्क का लगा
तुमको रोग है जता दे।
यूं छुप-छुप रोने से
फायदा हुआ क्या।
कुछ दर्द कम हुआ होगा
और कुछ मिला क्या।
उसकी जुदाई में
चेहरा झुलसाया हुआ है।
आंखें भरी-भरी सी
दिल घबराया हुआ है।
क्या बात हो गई
चेहरा मुरझाया हुआ है।
वो कौन राज अपने
दिल में छुपाये हो तुम।
किसके कहर से खुद को
सबसे बचाए हो तुम।
जितना भी कर लो कोशिश
छुपती नहीं मुहब्बत।
ये होता जिसको उसपर
होती खुदा की रहमत।
बूंदें दे टपका आंखें भी
दहलाया हुआ है।
आंखें भरी-भरी सी
दिल घबराया हुआ है।
क्या बात हो गई
चेहरा मुरझाया हुआ है।
जिसको हुई मुहब्बत,
दुश्मन बना जमाना।
मंजिल तुम्हें मिलेगी,
अपना वादा निभाना।
कर के भरोसा इक-दूजे पर
मिशाल बनो।
चढ़ के कभी न उतरे
वैसा गुलाल बनो।
किस सोच में पड़े हुए हो,
सर चकराया हुआ है।
आंखें भरी-भरी सी
दिल घबराया हुआ है।
क्या बात हो गई
चेहरा मुरझाया हुआ है।

- अंजु दास गीतांजलि

कोहली की विराट कप्तानी और धोनी

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टी-20 वर्ल्ड कप से पहले टी-20 की कप्तानी से संन्यास की घोषणा कर दी। इस खबर ने सभी क्रिकेट प्रेमियों को सकते में ला दिया। उन्होंने अपनी कप्तानी को लेकर उठ रहीं उन सारी अटकलों पर उस वक्त विराम लगा दिया, जब ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी कि वो टी-20 वर्ल्ड कप के बाद टी-20 की कप्तानी छोड़ देंगे। विराट क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसे नाम है जिनके बारे में लिखकर बताने की जरूरत नहीं है। विराट ने अगर अपने गुस्से से एक अलग पहचान बनाई तो, कुछ खिलाड़ियों का सम्मान करके भी एक अलग जगह बनाई। टी-20 की कप्तानी से विराट कोहली के संन्यास ने एक बार फिर से कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट से विदाई की याद दिला दी।

धोनी ने 2017 में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया था। उस समय का विराट का बयान आज भी लोगों के जहन में बना हुआ है। विराट ने कहा था-भले ही धोनी ने क्रिकेट और कप्तानी से अलविदा कह दिया हो लेकिन वो हमेशा उनके कप्तान रहेंगे। आज धोनी के बाद क्या इस वाक्य को दोहराने वाला कोई दूसरा है। जो विराट के लिए यह बात कहे, क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो कैप्टन कूल ने 72 टी-20 मैचों में टीम की कमान संभाली और 41 में जीत दिलाई। इसके साथ ही 28 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं कोहली ने 45 मैचों में कप्तानी की और 27 में जीत दर्ज की। इन दोनों की तुलना आंकड़ों से की जाए तो कोहली आगे निकल जाएंगे, लेकिन दर्शकों के जहन में छाप छोड़ने वाली बात की जाए तो इसकी तुलना थोड़ी मुश्किल हो सकती है।

जब तक विराट और धोनी साथ खेले और उसके बाद भी, खेल प्रशंसकों के लिए धोनी और विराट के रिश्तों के बारे में जानना हमेशा उत्साहित करता रहा है। कई बार धोनी से और कई बार विराट से, इस संबध में उनके प्रशंसकों ने सवाल भी किए। दोनों ही खिलाड़ियों ने कई बार अपने विचार रखे और कई बार बहुत ही कम शब्दों में इसे बता दिया। एक बार जब विराट से धोनी के उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया था तो उनका कहना था कि 'विश्वास और सम्मान।' दोनों खिलाड़ियों की शैली और सोच में काफी फर्क है। दोनों ने क्रिकेट की बुलंदियों को देखा है। इनकी तुलना करना मुश्किल है। लेकिन क्या अब हर खिलाड़ी अपनी अलग पहचान बनाने में लग गया है। पहले एक दौर हुआ करता था जब हर खिलाड़ी क्रिकेट के भगवान सचिन की तरह बनने का सपना देखता था। धोनी ने इसे आगे बढ़ाया और एक अलग पहचान बनाई।

विराट के प्रशंसकों की संख्या भी किसी से कम नहीं है। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है कि कहीं क्रिकेट में ऐसा तो नहीं हो रहा कि प्रशंसकों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और अपने खिलाड़ियों को अपना आदर्श बनाने वालों की संख्या में गिरावट। अगर वाकई ऐसा नहीं है तो यह जानना होगा कि कौन विराट के लिए कहेगा कि वो उनके कप्तान हमेशा रहेंगे ?

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में जब मैदान पर उतरे तो एक खास रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया। आज वह टी-20 क्रिकेट में 300वें मैच में कप्तानी कर रहे थे। धोनी 2007 से लेकर अब तक भारतीय क्रिकेट टीम, चेन्नई सुपर किंग्स, इंडियंस 11, राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स समेत चार टीम की कप्तानी कर चुके हैं। धोनी 300 टी-20 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मैच से पहले टी-20 कप्तान के रूप में 299 मैच खेले। जिनमें उन्होंने 176 मैच जीते और 118 मुकाबले हारे थे। इस दौरान दो मैच टाई रहे जबकि, तीन मैचों का रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने अपनी कप्तानी में 59.79 फीसदी मैच जीते हैं। धोनी के बाद टी-20 मैचों में सबसे ज्यादा कप्तानी करने के मामले में डैरेन सैमी का नाम आता है। वह 208 मैचों में टीम के कप्तान रहे। जबकि, विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। वह 185 टी-20 मुकाबलों में कप्तानी कर चुके हैं।

सबसे ज्यादा टी-2 मैचों में कप्तानी के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो गौतम गंभीर चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 170 टी-20 मैचों में कप्तानी की। जबकि रोहित शर्मा 153 टी-20 मुकाबलों में अब तक कप्तानी कर चुके हैं। वहीं, अगर विनिंग प्रतिशत की बात की जाए तो रोहित शर्मा अव्वल हैं। हिटमैन का विनिंग प्रतिशत 62.74 रहा है। धोनी की कप्तानी में सीएसके ने अपना नौवा फाइनल खेला। इन सभी फाइनल मुकाबलों में धोनी ने कप्तानी की है। वह 2008 से टीम के कप्तान हैं।

● आशीष नेमा

धोनी के नाम चौथा आईपीएल खिताब

आईपीएल 2021 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 27 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ सीएसके ने चौथा आईपीएल खिताब अपने नाम किया। यह सभी खिताब सीएसके ने धोनी की कप्तानी में जीते हैं। चेन्नई ने इससे पहले 2010, 2011 और 2018 में खिताब जीता था। पिछले साल फिसड्डी रहने वाली सीएसके टीम ने इस बार कायापलट करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। पिछले सीजन ने चेन्नई प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनी थी। वहीं, इस बार चेन्नई प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम, फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम और चैंपियनशिप जीतने वाली टीम बन गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 192 रन बनाए। फाफ डुप्लेसिस ने सबसे ज्यादा 86 रन की पारी खेली। इसके जवाब में कोलकाता की टीम 20 ओवर में नौ विकेट गंवाकर 165 रन ही बना सकी। केकेआर की टीम अच्छी शुरुआत को जीत में नहीं बदल सकी। शुभमन गिल ने 51 रन और वेंकटेश अय्यर ने 50 रन की पारी खेली थी। चेन्नई की टीम इस जीत के साथ आईपीएल की दूसरे सबसे सफल टीम बन गई है। सीएसके के अलावा मुंबई ने सबसे ज्यादा पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है। वहीं, कोलकाता की टीम दो बार खिताब जीत सकी है।

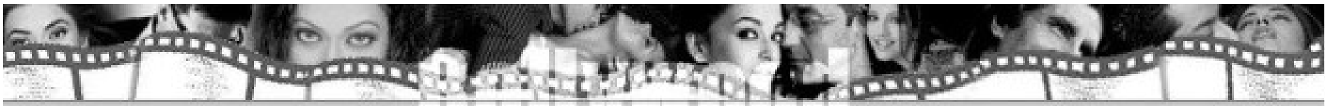

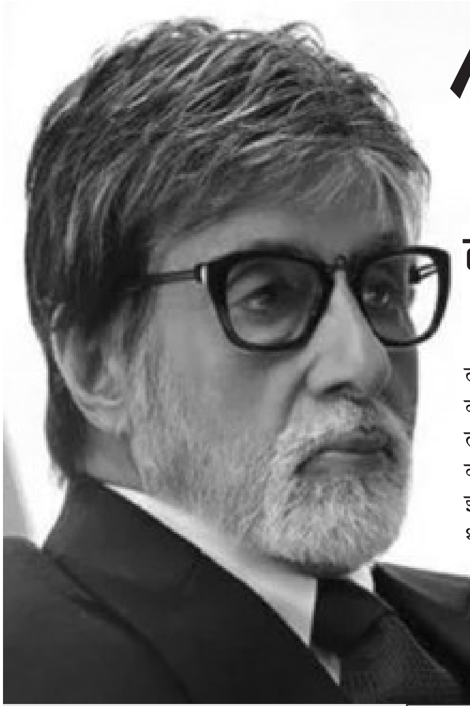

12 फ्लॉप फिल्में देकर फिल्ममेकर्स की ब्लैकलिस्ट में थे महानायक

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 79 सालों के हो चुके हैं। बिग बी ने पिछले 5 दशकों में हिंदी सिनेमा को कई नायाब और यादगार फिल्मों की सौगात दी है, हालांकि उनका शुरुआती करियर संघर्षों से भरा रहा था। लगातार नाकामयाबी का सामना करते हुए बिग बी ने हमेशा के लिए इंडस्ट्री छोड़ने का तक मन बना लिया था, हालांकि उनकी किस्मत उनका सुनहरा भविष्य लिए इंतजार कर रही थी। नौकरी की तलाश में अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे थे, लेकिन उनकी भारी आवाज के चलते उनका मजाक उड़ाकर उन्हें ऑडीशन से भगा दिया गया था। उस समय हर कोई अंजान था कि यही आवाज एक दिन दुनिया जीत लेगी।

रेडियो में नहीं मिली नौकरी तो कमाई के लिए अमिताभ बच्चन ने किया शिपिंग कंपनी में काम

आज बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक अमिताभ ने महज 500 रुपए की सैलेरी में अपनी पहली नौकरी की थी। जिसमें से कट-पिट कर उन्हें महज 460 रुपए ही मिला करते थे। बिग बी कोलकाता की बर्ड एंड शिपिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे। इस नौकरी के दौरान ही वो समय निकालकर प्ले में हिस्सा लिया करते थे।

जंजीर फिल्म ने हटा फ्लॉप एक्टर का टैग

उन दिनों प्रकाश मेहरा जंजीर (1973) की कास्टिंग को लेकर परेशान रहा करते थे। इस फिल्म से उन्हें काफी उम्मीदें थीं। वे अपने ऑफिस में इसी फिल्म के बारे में प्राण से चर्चा कर रहे थे। तब प्राण ने उन्हें अमिताभ का नाम सुझाया। लेकिन प्रकाश मेहरा ने बिना कुछ कहे ही इनकार कर दिया। तब प्राण ने केवल इतना कहा कि बेहतर ये होगा कि आप उसकी चंद फिल्में देख लें और फिर फैसला करें। साथ ही यह भी कहा कि बेशक उसकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हुई हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ खास जरूर है। टैलेंट की उसमें कमी नहीं। चंद फिल्में देखकर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ पर दाव लगा दिया। जंजीर के डायलॉग सलीम-जावेद की हिट जोड़ी ने लिखे थे। फिल्म बनकर तैयार हो गई, लेकिन ट्रायल शो को वितरकों ने बेहद ठंडा रिस्पॉन्स दिया। अमिताभ उनके लिए पिटे हुए हीरो थे, जिसकी मार्केट वैल्यू न के बराबर थी। लेकिन जब दर्शकों ने फिल्म देखी तो देखते ही रह गए।

सिल्वर जुबली फिल्म देने के बावजूद 4 साल तक नहीं था रोनित रॉय के पास काम, आर्थिक तंगी ने घेर लिया था, शराबी तक हो गए थे रोनित रॉय

रोनित रॉय टेलीविजन पर एक लोकप्रिय स्टार हैं। उन्होंने कसौटी जिंदगी की और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शो में काम किया है। टीवी के साथ-साथ उन्होंने उड़ान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2 स्टेट्स और काबिल जैसी फिल्मों में भी काम किया लेकिन उनके मुताबिक, एक वक्त ऐसा आया था, जब काम न होने के चलते वे डिप्रेशन में चले गए थे और शराब का सहारा लेने लगे थे।

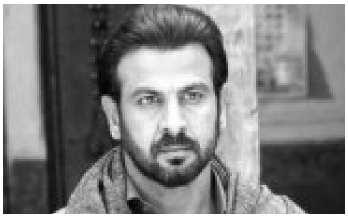

रोनित ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ? मैंने एक सिल्वर-जुबली फिल्म की थी, जो उस वक्त आसानी से नहीं मिलती थी। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, आज के समय में तो ये शब्द सुनने को भी नहीं मिलते। लेकिन सिल्वर जुबली फिल्म देने के बाद भी मेरे पास काम नहीं था। घबराहट में मैंने हर तरह के ऑफर लेने शुरू कर दिए। कुछ फिल्में चली नहीं तो कुछ बन नहीं पाईं। एक समय ऐसा भी आया जब मेरे पास कार में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं थे।

टीवी पर जस्सी जैसी कोई नहीं के जरिए मोना सिंह ने बनाई पहचान, कभी विद्युत जामवाल से होने वाली थी शादी लेकिन टूट गया था रिश्ता

टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह को ज्यादातर लोग टीवी की जस्सी के रूप में जानते हैं। हालांकि, मोना ने कई सीरियल्स और रियलटी शोज किए हैं, लेकिन साल 2003 से 2006 के बीच सोनी टीवी पर प्रसारित हुआ जस्सी जैसी कोई नहीं उनका अब तक का सबसे पॉपुलर शो है। सीरियल्स के अलावा मोना ने आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन स्टारर फिल्म 3 इडियट्स में करीना कपूर की बड़ी बहन का रोल निभाया था। मोना सिंह डांसिंग रियलटी शो झलक दिखला जा के पहले सीजन की विजेता हैं। साल 2013 में जब मोना सिंह का कथित एमएमएस लीक हुआ था, उसके बाद उनका अपने ब्वॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। बॉलीवुड मूवी कमांडो फेम विद्युत जामवाल से मोना के रिश्ते काफी अच्छे थे। दोनों जल्द ही शादी करने वाले भी थे, लेकिन एमएमएस आने के कुछ दिनों बाद अचानक दोनों के ब्रेकअप की खबर ने उनके फैन्स को निराश कर दिया।

बाजार की जुगलबंदी

उस दिन खाने की टेबल पर बैठा ही था कि मोबाइल की रिंगटोन बजी। कॉल अननोन नंबर से था। अपन की प्रवृत्ति जिज्ञासु हैं, इसलिए हाथ में लिया कौर मुंह में ढकेला और उसे गटककर दूसरे हाथ से मोबाइल कान से सटाकर 'हलो' कहा। उधर से परिचयात्मक स्वर उभरा कि वह किसी प्रकाशन संस्था से बोल रहा है। अब किसी प्रकाशक का फोन आए और लेखकनुमा जीव खुश न हो, यह संभव नहीं! मैं भी झटपट खुश हो लिया था। खैर फेसबुक पर लिखते-लिखते स्वयं के लेखक होने की फीलिंग तो आ ही गई है! वह फोन कॉल मुझे गर्वानुभूति दे गई थी। लेकिन अगले ही पल जब उसने कहा कि, आपने हमारे वेबसाइट पर अपना फोन नंबर दिया है, इसलिए फोन किया तो मेरा उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया था, क्योंकि मैं तो यह सोचकर खुश था कि जरूर इस प्रकाशन संस्था ने मेरे लिखे से प्रभावित होकर ही मुझे फोन किया होगा। खैर, कुछ दिन पहले अपने एक ब्लॉगनुमा लेख के कमेंटबाक्स में किसी के द्वारा दिए गए वेबसाइट पर मैंने अपना नाम और मोबाइल नंबर छोड़ा था।

उस फोन वार्ता में जब उसने यह कहा कि 'किताब प्रकाशित कराने के लिए टाइपिंग और कवरपेज बनाने का खर्चा दस हजार रुपया पहले देना होगा और यह काम हो जाने के बाद इसे आपको देखने के लिए भेजा जाएगा, फिर आगे की बात होगी' तो मैं नासमझ मुर्गे जैसी चुप्पी लगा गया था। फिर जैसे मेरी चुप्पी से विचलित होकर उसने पूछा था, वैसे आप क्या लिखते हैं? इस जायज बात पर मैंने भी बोल दिया था कि 'कोई खास नहीं, कभी-कभार कुछ व्यंग-वंग टाइप का लेख लिख देता हूं।' मेरी इस बात पर उसने एकदम से कहा था, अरे हां! आजकल तो व्यंग्य का ही मार्केट है, ठीक है..अब आप आगे का प्लान बताएं! चूंकि मेरे पास लेखन जैसे क्षेत्र में मार्केटिंग का अनुभव नहीं है, इसलिए बात को बढ़ाने की बजाय आगे प्लानिंग करने की बात कहकर उस फोन कॉल से छुट्टी पा ली थी। हां तब से लिखने से ज्यादा 'मार्केटिंग' का गुर सीखने में वक्त बिता रहा हूं। लेकिन कविता, कहानी और उपन्यास जैसी साहित्यिक विधाओं को छोड़ आजकल व्यंग्य ही क्यों बिकाऊ है?

इस पर विचारा तो इसके पीछे बुद्धिमानों की बढ़ती संख्या जिम्मेदार प्रतीत हुई। विसंगतियों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखने वाला यह जीव आजकल बैठे-ठाले भड़ासित मन से अपने 'अधरोष्ठों' पर मुस्कान लाए बिना व्यंग्य उगलता है। इसके उगले व्यंग्य में इसकी त्योरियां चढ़ी हुई प्रतीत होती है, जैसे यह बाहर की बजाय अपने अंदर की विसंगति से पीड़ित हो! खैर, जैसे ही मेरे दिमाग में यह बात आई मैंने अपने अंदर की विसंगति पर गौर करना शुरू किया, कि कितनी जल्दी इसे प्रकटाऊं और बिकूं!

लेकिन मेरी समस्या यह है कि बुद्धिमानों के बीच मेरी पैठ नहीं, जिससे मेरी एक्टीविटी इनके बीच चर्चा का विषय बन सके और मुझे बिकाऊ होने में मदद करे! मैं देखता हूं बिकने वाले साहित्यकार-कम-व्यंग्यकार इसीलिए लिखने से ज्यादा साहित्यिक गोष्ठियों में जाकर इसकी चर्चा करके बुद्धिमान लेखकों के बीच कायदे से अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं। रही बात पाठकों की, तो पाठकों से ज्यादा इन लेखकों की संख्या ही अब इतनी अधिक हो चुकी है कि पाठकों की तलाश करना लेखक की निरी बेवकूफी होगी! सोशल मीडिया से सक्रिय लेखकों से इनकी संख्या का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। तो लेखकों की संख्या और इनमें व्यंग्य की अच्छी समझ को देखते हुए मैंने तय कर लिया है कि पाठकों की बजाय लेखकों के बीच ही अपनी मार्केटिंग की जाए। इससे मेरी किताब बिकने के अधिक चांसेज उपलब्ध होंगे। वैसे भी पाठक बेचारा आजकल के व्यंग्य से अपनी विसंगति का तालमेल नहीं बैठा पाता, इसे पढ़कर वह अपना सिर खुजलाने लगता है। अपनी व्यंग्य वाली किताब को बिकाऊ बनाने के लिए एक अन्य तथ्यपूर्ण बात पर भी गौर कर रहा हूं, यह कि आजकल उन्हीं बुद्धिजीवी लेखकों के व्यंग्य अधिक धारदार माने जाते हैं, जो खेमेबाजी करते हैं। इसीलिए इनकी फैन फॉलोइंग की संख्या भी बड़ी होती है, जो इनके बिकने में मददगार साबित होती है। सोशल मीडिया पर लेखकों को मिले लाइक कमेंट की संख्या से भी इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। तो, बिकाऊ होने के लिए पार्टीबंदी की प्लानिंग के साथ विरोधी लेखकों से मुंहा-तुंहा की नीति अपनाकर मुझे व्यंग्य लेखन करना होगा। शायद इन सब हथकंडों से किताब का स्वयंमेव प्रचार भी हो जाए।

खैर, हमें भावी व्यंग्य की अपनी किताब को बाजार में बेचना है, इसलिए पहले बाजारवाद को भी अच्छे से समझना होगा। यहां, जो दिखता है वही बिकता भी है, का सिद्धांत चलता है। पहले का तो नहीं कह सकते, लेकिन आज लेखक, लेखक होने के साथ-साथ बुद्धिजीवी भी होता है, और इनकी आदत होती है कि ये कुछ करें या न करें, लेकिन विसंगति तलाश करने में अपनी बुद्धि जरूर खपाते हैं। इनकी बढ़ती संख्या से मैं मानता हूं कि आजकल व्यंग्यवाद का जमाना है और विज्ञापनों में व्यंग्य के तत्वों के इस्तेमाल को देखने से सिद्ध होता है कि व्यंग्यवाद और बाजारवाद में खूब जुगलबंदी चल रही है। यदि यह जुगलबंदी न होती, तो बाजारवाद का कबाड़ा करने के लिए इस पर लिखा व्यंग्य भी न बिकता! सच तो यह है कि ये आपस में किसी का कबाड़ा नहीं करते, बल्कि इस जुगलबंदी के कारण ही ये दोनों 'वाद' दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं!! यहां मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, कि बाजारवाद ने साहित्य का कबाड़ा किया हुआ है, पहली बात तो यह है कि साहित्य कोई कमोडिटी नहीं है कि वह बिक सके, बिकता वही है, जो कमोडिटी हो। व्यंग्य साहित्य न होकर 'चीज' है, जिसे आसानी से बेचा जा सकता है।

हां इतना अवश्य है कि बाजारवाद पैसे और प्रचार को आदमी से ऊपर रखकर चलता है और आदमी जब इन दोनों की गिरफ्त में होता है तो अकुलाता है कि वह दिखाई पड़े! कैसे दिखाई पड़े? इसके लिए वह पके फोड़े के मवाद जैसा फूटकर प्रकट हो जाता है। आखिर लेखक को भी प्रचार और पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए उसे भी बिकना होता है, यह तभी संभव है जब वह आदमी को नीचे रखकर लिखे। सोच रहा हूं, इन बातों पर पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ही उस प्रकाशन संस्था वाले को फोन किया जाए।

● **विनय कुमार तिवारी**

PRISM®
CEMENT
प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस
ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.
PRISM CHAMPION PLUS
PRISM®
चैम्पियन
प्लस
सीमेंट
HIGHER STRENGTH
DIGITAL PSD
BETTER WORKABILITY
SUPERIOR CONSTRUCTION
Portland Pozzolana Cement (Fly Ash Based)
PRISM JOHNSON LIMITED
Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in
दूर की सोच®

मध्य प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम

प्रदेश के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अनायास ही पर्यटक आकर्षित हो जाते हैं। मॉनसून पर्यटन वर्षा काल में पर्यटकों को प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचय कराने के लिए जंगल में 'बफर में सफर' कैंपेन चलाया गया। इस कैंपेन में पर्यटकों ने जंगल के बफर जोन में सफारी का आनन्द लिया।

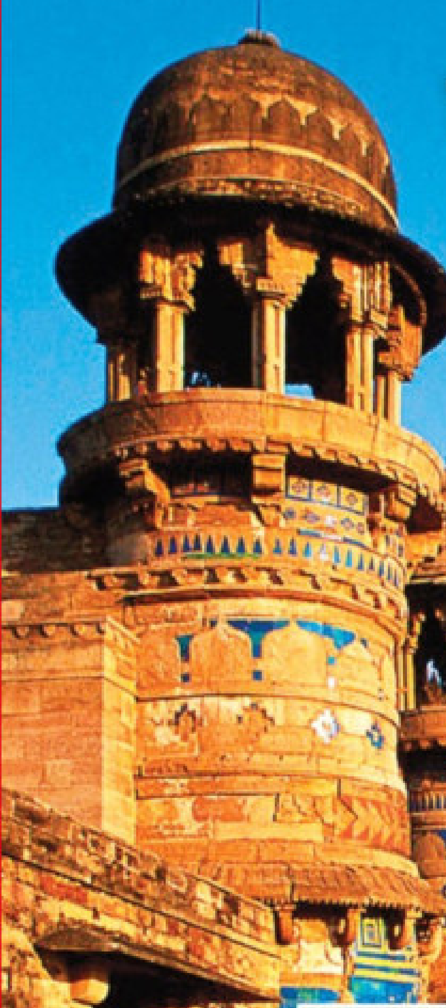

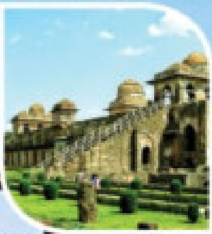

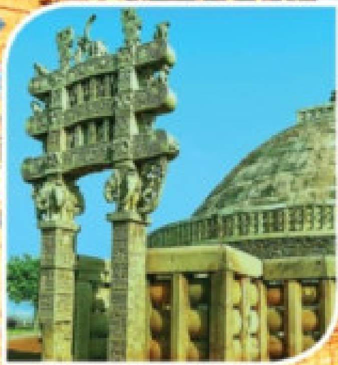

गांवों में विकसित होंगे हेरिटेज ग्राम

ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश के प्रमुख 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों में ग्रामों को हेरिटेज ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें 1500 से अधिक होमस्टे विकसित किए जायेंगे। पर्यटक को पर्यटन स्थल के समीप ही स्थानीय संस्कृति से परिचय, स्थानीय व्यंजन के स्वाद, हस्त-कला और हस्त-शिल्प के उत्पादों को क्रय करने का अवसर मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ओरछा के ग्राम लाडपुरा खास को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मे 'बेस्ट टूरिज्म विलेज' श्रेणी में नामांकित किया गया है।

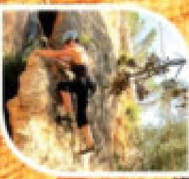

साहसिक पर्यटन के अंतर्गत युवाओं पर विशेष ध्यान

कैंपिंग और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'साहसिक पर्यटन' अंतर्गत प्रदेश में युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए चुनिंदा पर्यटन स्थलों पर साइकिल टूर, वॉटर स्पोर्ट्स, कैंपिंग, हॉट एयर बैलून सफारी जैसी रोमांचक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही मांडू उत्सव, खजुराहो नृत्य समारोह और जल महोत्सव में युवाओं के लिए यूजिक कंसर्ट का भी आयोजन किया जा रहा हैं।

D19239/21

मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए जीवन-यात्रा के विभिन्न आयामों और पड़ावों को पर्यटन से जोड़ रहा है।